

[2023] 9 एस सी आर 637:2023 आई. एन. एस. सी 560

क.

के. सी. निनान

वी.

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस। (2004 की सिविल अपील संख्या 2109-2110)

19 मई, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, सीजेआई, हिमा कोहली और पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003-एस.42 और 61-पिछले मालिक पर देय बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए बाद के मालिक की देयता-क्या पूर्व के मालिक से बकाया बिजली बकाया का दावा बाद के मालिक से किया जा सकता है, जिसने बंधक लागू करने या लेनदारों के बकाया का भुगतान करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में संपत्ति का अधिग्रहण किया है-अभिनिर्धारित किया गया:उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए, एक वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की लाइनें, ट्रांसफॉर्मर और अन्य उपकरण जैसे बुनियादी ढांचे को बिछाने की आवश्यकता होती है-उपभोक्ता के बिजली का उपयोग नहीं करने पर भी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए लाइसेंसधारियों की आवश्यकता होती है-2003 का अधिनियम बिजली उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है-एक नए मालिक से पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया की वसूली के लिए प्रदान की गई आपूर्ति शर्तें बुनियादी ढांचे को बिछाने के साथ-साथ बिजली उत्पादन और संचरण कंपनियों के प्रति चल रही वर्तमान देनदारियों की वसूली के लिए आवश्यक हैं-सार्वजनिक भलाई की रक्षा करने के अलावा, ऐसी शर्तों का 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ एक उचित संबंध भी है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

637

638 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 -s.100-प्रभार-क्या बिजली का बकाया शुल्क बन सकता है या आधार पर बोझ बन सकता है-वैधानिक विनियमों या नियामक आयोग द्वारा अधिनियमित नियमों का प्रभाव-आयोजित:किसी अंतरिती के खिलाफ आरोप तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास इसकी कोई सूचना न हो, जब तक कि इस तरह के नोटिस की आवश्यकता को कानून द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया हो-1910 अधिनियम, 1948 अधिनियम और 2003 अधिनियम के प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि बिजली बकाया का बकाया संपत्ति पर शुल्क होगा या यह कि ऐसा शुल्क बिना किसी सूचना के अंतरिती के खिलाफ लागू किया जा सकता है-ईशा मार्बल्स में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1910 अधिनियम आर/डब्ल्यू के प्रावधानों के तहत। 1948 अधिनियम, बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क नहीं लगाता है-नतीजतन, सामान्य कानून में, परिसर के हस्तांतरणकर्ता को पिछले मालिक के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि बिजली

बकाया स्वचालित रूप से परिसर पर शुल्क नहीं बन जाता है-नियम बनाने की शक्ति में यू/एस शामिल है।181 आर/डब्ल्यू। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 इस तरह के शुल्क के निर्माण के लिए प्रावधान करने वाले पूर्ण कानून में प्रावधान के अभाव में नियामक आयोग को एक वैधानिक शुल्क का प्रावधान करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है-बिजली उपयोगिताएँ अधीनस्थ कानून या आपूर्ति की वैधानिक शर्तों को तैयार करके एक शुल्क बना सकती हैं जो बाद के हस्तांतरणकर्ता से बिजली बकाया की वसूली को सक्षम बनाती हैं-ऐसी स्थिति बिजली की रक्षा के महत्व में निहित है जो एक सार्वजनिक वस्तु है-सार्वजनिक उपयोगिताएँ बिजली आपूर्ति प्रदान करने में भारी मात्रा में पूंजी और बुनियादी ढांचे का निवेश करती हैं-परिसर की बकाया बिजली की वसूली करने में विफलता या असमर्थता ऐसी सार्वजनिक उपयोगिताओं और लाइसेंसधारियों के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी-बिजली अधिनियम, 2003-एस.50 और 181-महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और आपूर्ति की अन्य शर्तें) विनियम, 2005-विनियम 10.5।

ग

डी.

ई.

च

विद्युत अधिनियम, 2003 -धारा 43-क्या बिजली की आपूर्ति करने का शुल्क निरपेक्ष है-आयोजित:धारा 43 इन शब्दों से शुरू होती है "इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार बचत करें"-इसलिए, धारा 43 का संचालन।43 2003 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के अधीन भी होगा।43, वितरण अनुज्ञप्तिधारी मालिक या अधिभोगकर्ता के परिसर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि मालिक या अधिभोगकर्ता सभी शुल्कों का भुगतान करता है और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करता है।43(2) आगे एक आवेदक द्वारा ए को देय "मूल्य" को संदर्भित करता है।

जी.

एच.

639

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

वितरण लाइसेंसधारक से बिजली की आपूर्ति की मांग या प्राप्त करना जारी रखना-"मूल्य" शब्द का व्यापक अर्थ सभी 'शुल्कों' और 'शुल्कों' को शामिल करने के लिए दिया जाना चाहिए जो उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं-इस प्रकार, बिजली की आपूर्ति करने का शुल्क यू/एस।43 पूर्ण नहीं है, और आवेदन के हिस्से के रूप में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्कों और अनुपालनों के अधीन है।

विद्युत अधिनियम, 2003-एस.2(15) और 43-क्या बिजली की आपूर्ति करने का शुल्क परिसर के संबंध में है या उपभोक्ता के संबंध में-आयोजित:'आपूर्ति' की परिभाषा में विशेष रूप से कहा गया है कि आपूर्ति का अर्थ है उपभोक्ता को बिजली की बिक्री-2003 के अधिनियम की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को होती है न कि परिसर को-यह मालिक या अधिभोगकर्ता है जिसे अपने उपयोग या व्यवसाय के तहत परिसर के लिए बिजली की "मांग" करने का वैधानिक अधिकार है-इस प्रकार, यह हमेशा उपभोक्ता होता है जिसे बिजली की आपूर्ति की जाती है और बिजली की आपूर्ति के लिए बकाया या शुल्क के भुगतान में चूक के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

ग

डी.

नीलामी-बिजली बकाया के संदर्भ में या उसके बिना-"जहां है" के आधार पर परिसरों की नीलामी-लागू करना-आयोजित:जब किसी संपत्ति को "जैसा है, जहां है" के आधार पर बेचा जाता है, तो बिक्री पर संपत्ति पर बोझ खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है-सभी संभावित नीलामी खरीदारों को बकाया भुगतान करने के दायित्व के बारे में सूचित किया जाता है जब नीलामी बिक्री समझौते में एक उचित "जैसा है, जहां है" खंड शामिल किया जाता है-एक "जैसा है, जहां है" खंड के प्रभाव की जांच करते समय, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से, नीलामी बिक्री को नियंत्रित करने वाले खंडों की शब्दावली के साथ, एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ई.

च

विधानों की व्याख्या-एजुस्टेड जेनरिस का सिद्धांत-निर्माण का नियम-सामग्री की प्रयोज्यता-पर चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

जी.

पकड़ना:**1.विद्युत अधिनियम, 2003** की धारा **43** के तहत, वितरण लाइसेंसधारी मालिक या अधिभोगकर्ता के परिसर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि मालिक या अधिभोगकर्ता सभी शुल्कों का भुगतान करता है और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करता है।धारा **43** से शुरू होती है

एच.

640 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

"इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए शब्दों को बचाएँ।"इसलिए, धारा **43** का संचालन भी **2003** के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा। धारा **43 (2)** का परंतुक आगे एक वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति की मांग करने या प्राप्त करना जारी रखने के लिए एक आवेदक द्वारा देय "मूल्य" को संदर्भित करता है।"मूल्य" का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाना है।यह "मूल्य" राज्य आयोग द्वारा निर्धारित विचार है, कि एक आवेदक बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है।"मूल्य" शब्द का व्यापक अर्थ सभी "शुल्क" और "शुल्क" को शामिल करने के लिए दिया जाना चाहिए जो उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।इसमें समय-समय पर उपयुक्त कमीशन द्वारा धारा **45** के तहत निर्धारित 'शुल्क' और 'शुल्क' शामिल हैं जो एक वितरण लाइसेंसधारी किसी भी उचित व्यय की वसूली के लिए धारा **46** के तहत लगा सकता है।'मूल्य' शब्द का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें वैधानिक बकाया भी शामिल है जिसे राज्य आयोग धारा **50** के तहत विनियमों के माध्यम से लागू करने का निर्णय लेता है।इस प्रकार, धारा **43** के तहत बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य निरपेक्ष नहीं है, और आवेदन के हिस्से के रूप में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्कों और अनुपालनों के अधीन है।[पैरा **32,40,41-43**] [**670-B-C; 672-F-G; 673-A-B**]

ग

डी.

2. 'आपूर्ति' की परिभाषा में विशेष रूप से कहा गया है कि आपूर्ति का अर्थ है उपभोक्ता को बिजली की बिक्री।उक्त परिभाषा से यह संकेत नहीं मिलता है कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता के परिसर के बराबर है।**2003** के अधिनियम की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को होती है न कि परिसर को।यह हमेशा उपभोक्ता होता है जिसे बिजली की आपूर्ति की जाती है और बिजली की आपूर्ति के लिए बकाया या शुल्क के भुगतान में चूक के लिए उत्तरदायी माना जाता है।बलपूर्वक, परिसर को चूककर्ता नहीं माना जा सकता है और उपभोक्ता के परिसर में कोई बकाया नहीं लगाया जा सकता है।
[पारस **50** और **56**] [**676-डी**]

ई.

च

3. 2003 के अधिनियम की धारा **43** के तहत, परिसर का मालिक या अधिभोगकर्ता विशेष परिसर के लिए बिजली की आपूर्ति की मांग कर सकता है। जब बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो मालिक या अधिभोगकर्ता केवल उन विशेष परिसरों के संबंध में उपभोक्ता बन जाता है जिनके लिए बिजली मांगी जाती है और प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक आवासीय परिसर में एक अपार्टमेंट का मालिक व्यक्ति ऐसे अपार्टमेंट में बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करता है, तो ए

जी.

एच.

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

वे केवल उस अपार्टमेंट के संबंध में उपभोक्ता बन जाते हैं जिसके लिए आवेदन किया जाता है और जिसे बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक और अपार्टमेंट हो सकता है जिसमें पहले से ही बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन उन्हें दूसरे अपार्टमेंट के संबंध में एक अलग उपभोक्ता माना जाएगा। एक आवेदन को 'पुनः कनेक्शन' के रूप में माने जाने के लिए, आवेदक को उसी परिसर के संबंध में बिजली की आपूर्ति की मांग करनी होगी जिसके लिए पहले से ही बिजली प्रदान की गई थी। भले ही उपभोक्ता एक ही हो, लेकिन परिसर अलग-अलग हो, इसे एक नया कनेक्शन माना जाएगा, न कि पुनः कनेक्शन। [पैरा **61**] [679-एच; 680-ए-सी] **4. 2003** के अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि धारा **181 (2)** के तहत राज्य आयोग की नियामक शक्तियां व्यापक रूप से महत्वपूर्ण हैं। आयोग के पास धारा **50** के तहत विद्युत आपूर्ति संहिता सहित धारा **181 (2)** में निहित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ पूर्ण शक्तियां हैं। तदनुसार, आयोग बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों जैसे "शुल्क की वसूली", "आपूर्ति का विच्छेदन" और "आपूर्ति की बहाली" को नियंत्रित करने वाली आपूर्ति संहिता को अधिसूचित कर सकता है। इस न्यायालय की राय में, ऐसा प्राधिकरण नए या बाद के मालिकों से पिछले मालिकों के बिजली बकाया की वसूली के लिए शर्तों को निर्धारित करने तक भी फैला हुआ है। [पैरा **84**] [690-एफ-जी]

ग

डी.

ई.

5. 2003 का अधिनियम बिजली उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। एक नए मालिक से पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया की वसूली के लिए प्रदान की जाने वाली आपूर्ति शर्तें बुनियादी ढांचे को निर्धारित करने के लिए खर्च की गई लागत के साथ-साथ बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों के प्रति चल रही वर्तमान देनदारियों की वसूली के लिए आवश्यक हैं। ऐसी शर्तों के अभाव में, वितरण लाइसेंसधारियों के लिए चूक भुगतान की वसूली करना मुश्किल हो सकता है, जिससे राजस्व घाटा बढ़ सकता है। इससे वितरण लाइसेंसधारियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान हो सकता है। आपूर्ति और बिजली आपूर्ति संहिता की शर्तें

च

जी.

एच.

642 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

जिनके लिए बिजली कनेक्शन देने की शर्त के रूप में पिछले मालिक के बिजली बकाया के भुगतान की आवश्यकता होती है, मूल विधानों की योजना और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक स्पष्ट संबंध है। वितरण लाइसेंसधारियों के लिए यह उचित और उचित है कि वे आपूर्ति की शर्तों को निर्दिष्ट करें जिसमें परिसर के बाद के मालिक या कब्जाधारक को अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में पिछले मालिक या कब्जाधारक के बिजली बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, साथ ही बिजली के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए भी। [पारस **87** और **91**] [691-जी-एच; 692-ए; 693-ई-एफ]

6. बिजली उपयोगिताएँ अधीनस्थ कानून या आपूर्ति की वैधानिक शर्तों को तैयार करके शुल्क लगा सकती हैं जिससे बाद में हस्तांतरणकर्ता से बिजली बकाया की वसूली की जा सके। ऐसी स्थिति बिजली की रक्षा के महत्व में निहित है जो एक सार्वजनिक वस्तु है। सार्वजनिक उपयोगिताएँ बिजली आपूर्ति प्रदान करने में भारी मात्रा में पूंजी और बुनियादी ढांचे का निवेश करती हैं। परिसर के बकाया बिजली की वसूली करने में विफलता या असमर्थता ऐसी सार्वजनिक उपयोगिताओं और लाइसेंसधारियों के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। व्यापक लोक हित में, अधीनस्थ कानून में शर्तों को शामिल किया गया है जिसके तहत विद्युत उपयोगिताएँ बिजली के बकाया की भरपाई कर सकती हैं। नई आधारभूत संरचना तैयार करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए धन और निवेश प्रदान करने के लिए बिजली बकाया की भरपाई आवश्यक है। इस तरह के प्रावधान के अभाव में, विद्युत उपयोगिताओं को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाएगा और बिजली का भारी बकाया होने पर भी वे एक नया बिजली कनेक्शन देने के लिए मजबूर होंगे। उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने के अलावा, यह उपभोक्ताओं के व्यापक निकाय को भी प्रभावित करेगा। [पैरा **113**] [700-एफ-एच; 701-ए]

ग

डी.

ई.

च

7. धारा **56 (2)** के तहत सीमा की अवधि धारा **56** के तहत देय राशि से संबंधित है। धारा **56** के तहत देय राशि बिजली के लिए भुगतान करने में किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण देय राशि से संबंधित है। धारा **56 (2)** में प्रावधान है कि ऐसी देय राशि दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई थी। धारा **56** के तहत प्रदान किए गए वसूली के साधन बिजली की आपूर्ति के विच्छेदन के उपचार से संबंधित हैं। पुनर्प्राप्त करने का अधिकार अभी भी बना हुआ है। यह न्यायालय नीलामी खरीदारों की इस दलील को खारिज करता है कि ए की वसूली

जी.

एच.

643

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

बकाया बिजली बकाया या तो पूर्ववर्ती उपभोक्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करके या बाद में हस्तांतरणकर्ता से आपूर्ति की प्रासंगिक शर्तों के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके **2003** के अधिनियम की धारा **56 (2)** के तहत सीमा के आधार पर वर्जित है। तदनुसार, जबकि धारा **56 (2)** के तहत सीमा का प्रतिबंध धारा **56** के तहत डिस्कनेक्शन के उपचार को प्रतिबंधित करता है, लाइसेंसधारी नागरिक उपचार के माध्यम से या आपूर्ति की शर्तों के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बिजली बकाया की वसूली करने का हकदार है। [पारस **129** और **131**] [709-बी-सी; एफ-एच]

8. सभी संभावित नीलामी खरीदारों को बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्व के बारे में सूचित किया जाता है जब नीलामी बिक्री समझौते में एक उपयुक्त "जैसा है वैसा ही" खंड शामिल किया जाता है। यह इच्छुक नीलामी खरीदार के लिए है

कि वह जिस संपत्ति को खरीदने का प्रस्ताव करता है, उसके संबंध में स्वामित्व, बोझ और लंबित वैधानिक बकाया जैसी परिस्थितियों के बारे में हर तरह से खुद को संतुष्ट करे।सार्वजनिक नीलामी बिक्री में, नीलामी खरीदारों के पास परिसर का निरीक्षण करने और उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने का अवसर होता है, जिसमें यह भी शामिल है कि परिसर में बिजली की आपूर्ति की जाती है या नहीं।बिजली के विच्छेदन के बारे में जानकारी उचित परिश्रम के साथ आसानी से खोजी जा सकती है, जो एक विवेकपूर्ण नीलामी खरीदार को विच्छेदन के कारणों के बारे में उचित पूछताछ पर रखता है।जब किसी परिसर में बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है, तो खरीदार के लिए यह कहना असंभव होगा कि वे बकाया बिजली के अस्तित्व से अनजान थे।कैविएट एम्प्टर के कानूनी सिद्धांत के संदर्भ में, खरीदार का कर्तव्य बन जाता है कि वह उचित परिश्रम करे।एक विक्रेता पेटेंट दोषों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसके बारे में एक खरीदार को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, **1882** की धारा **3** के संदर्भ में वास्तविक या रचनात्मक सूचना है।हालांकि, धारा **55 (1) (ए)** के संदर्भ में, इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, विक्रेता संपत्ति में या विक्रेता के स्वामित्व में भौतिक दोषों का खुलासा करने के लिए बाध्य है, जिसके बारे में वह जानता है और जिसे एक खरीदार सामान्य सावधानी के साथ अपने लिए नहीं खोज सकता है।"जैसा है जहां है" खंड के प्रभाव की जांच करते समय, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ नीलामी बिक्री को नियंत्रित करने वाले खंडों की शब्दावली को एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।[अनुच्छेद **141-143**]
[**715-G-H; 716-A-E**]

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

644 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

9. "इजसडेम जेनरिस" का नियम निर्माण का एक सिद्धांत है।नियम यह है कि जब सामान्य शब्द एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं, तो सामान्य शब्द उसी प्रकार की चीजों तक सीमित होने चाहिए जो निर्दिष्ट हैं।यह तब लागू होता है जब निम्नलिखित सामग्री मौजूद होती है: **(i)** कानून में विशिष्ट शब्दों की गणना होती है; **(ii)** गणना के विषय एक वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं; **(iii)** वह श्रेणी गणना से समाप्त नहीं होती है; **(iv)** एक सामान्य शब्द गणना का अनुसरण करता है; और **(v)** एक अलग विधायी इरादे का कोई संकेत नहीं है।इजसडेम जेनरिस नियम के अनुप्रयोग के लिए, यह आवश्यक है कि सामान्य शब्दों से पहले गिनाई गई चीजों को एक अलग श्रेणी या एक जीनस या एक परिवार का गठन करना चाहिए जो कई सदस्यों को स्वीकार करता है।[अनुच्छेद **187** और **188**] [**732-डी-एफ**] निष्कर्ष

ग

10. ए) 2003 के अधिनियम की धारा **43** के तहत बिजली की आपूर्ति करने का शुल्क पूर्ण नहीं है, और बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन के हिस्से के रूप में विद्युत उपयोगिताओं द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्कों और अनुपालनों के अधीन है;बी)। धारा **43** के तहत बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य परिसर के मालिक या अधिभोगियों के संबंध में है।**2003** के अधिनियम में उपभोक्ता और परिसर के बीच तालमेल पर विचार किया गया है।धारा **43** के तहत, जब बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो मालिक या अधिभोगकर्ता केवल उन विशेष परिसरों के संबंध में उपभोक्ता बन जाता है जिनके लिए बिजली की मांग की जाती है और विद्युत उपयोगिताओं द्वारा प्रदान की जाती है।सी)।एक आवेदन को 'पुनः कनेक्शन' के रूप में माने जाने के लिए, आवेदक को उसी परिसर के संबंध में बिजली की आपूर्ति की मांग करनी होगी जिसके लिए पहले से ही बिजली प्रदान की गई थी।भले ही उपभोक्ता एक ही हो, लेकिन परिसर अलग-अलग हो, इसे एक नया कनेक्शन माना जाएगा न कि पुनः कनेक्शन।डी)।**1948** के अधिनियम की धारा **49** के तहत अधिनियमित आपूर्ति की एक शर्त जिसमें परिसर के नए मालिक को बिजली आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में पिछले मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करने की

आवश्यकता होती है, का एक वैधानिक चरित्र होगा।ई)।**2003** के अधिनियम की धारा **50** के तहत राज्य आयोग की नियामक शक्तियों का दायरा नए या बाद के मालिकों से पिछले मालिकों के बिजली बकाया की वसूली के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।च)।पुनर्भुगतान के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

645

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

एक नए मालिक से पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया का **2003** के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है;जी)।**2003** के अधिनियम की धारा **50** के साथ पठित धारा **181** के तहत निहित नियम बनाने की शक्ति इतनी व्यापक है कि नियामक आयोग को ऐसे शुल्क के निर्माण के लिए प्रावधान करने वाले पूर्ण कानून में प्रावधान के अभाव में वैधानिक शुल्क का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।एच)।चूक करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करके वसूली की कार्यवाही शुरू करने की शक्ति **2003** के अधिनियम की धारा **56** के तहत वसूली के साधन के रूप में बिजली की आपूर्ति को काटने की शक्ति से स्वतंत्र है।(i)।"जैसा है जहां है" अभिव्यक्ति का निहितार्थ यह है कि प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को नोटिस पर रखा जाता है कि विक्रेता बकाया के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति के संबंध में जिम्मेदारी नहीं लेता है, जैसे कि सेवा शुल्क, बिजली कनेक्शन के लिए बिजली बकाया, और स्थानीय अधिकारियों के कर; और जे)।संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विद्युत उपयोगिताओं को मामलों के तथ्यों में नीलामी खरीदारों द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन की तारीख से मूलधन बकाया पर उपार्जित बकाया ब्याज को माफ करने का निर्देश दिया गया है।[पैरा **328**] [**781**-बी-एच; **782**-ए-ई]

ग

डी.

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010) 4 एससीसी 603:[2010] 3 एस. सी. आर. 609-अनुसरण किया गया।

ई.

उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, पार्क टाउन प्रभाग बनाम.

शा सुखराज पीराजी एयर 1968 एससी 67:[1967] 3 एससीआर

661 और केरल राज्य बनाम वी. टी. कल्लियानिकुट्टी (1999) 3

एससीसी **657**:[1999] 2 एस. सी. आर. **372**-लागू नहीं हुआ।

च

भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद बनाम बार काउंसिल

भारत सरकार (1995) 1 एस. सी. सी. 732:[1995] 1 एससीआर 304; भारत

सीमेंट लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य **(1990) 1 एससीसी**

12 :[1989] 1 पूरक।एस. सी. आर. 692; पंजाब शहरी नियोजन

और विकास प्राधिकरण बनाम रघु नाथ गुप्ता **(2012)**

जी.

8 एससीसी 197:[2012] 8 एस. सी. आर. 118; दिल्ली विकास

प्राधिकरण बनाम केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

लिमिटेड (2016) 13 एससीसी 561:[2016] 3 एससीआर 1126-प्रतिष्ठित।

दीपक थिएटर बनाम पंजाब राज्य **(1992) 1 एस. सी. सी.**

एच.

684 :[1991] 3 पूरक।एससीआर 242; के. रामनाथन बनाम राज्य

646 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

तमिलनाडु (1985) 2 एस. सी. सी. 116:[1985] 2 एससीआर 1028;

वी. एस. राइस एंड ऑयल मिल्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **[1964] 7 एस. सी. आर. 456;** दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम मैसर्स पैरामाउंट पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड। ए. आई. आर. **2007 एस. सी. 2:**

[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 635 और पश्चिमांचल विद्युत

विट्रान निगम लिमिटेड बनाम डी. वी. एस. स्टील और मिश्र धातु निजी

लिमिटेड (2009) 1 एससीसी 210:[2008] 15 एससीआर 766-पर निर्भर।

बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक

आयोग (2015) 2 एससीसी 438:[2014] 6 एससीआर 50-पुष्टि की गई।

ग

ईशा मार्बल्स बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड **(1995) 2**

एससीसी 648:[1995] 1 एस. सी. आर. 847; अहमदाबाद बिजली

कं. लिमिटेड बनाम।गुजरात इन्स (पी) लिमिटेड **(2004) 3 एस. सी. सी. 587:[2004] 3 एस. सी. आर. 23;** हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड **(1998) 4 एस. सी. सी. 470:[1998] 2 एस. सी. आर. 620;** तेलंगाना राज्य दक्षिणी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम.श्रीघधा बेवरेजेस **(2020) 6**

डी.

एससीसी 404:[2020] 4 एस. सी. आर. 295; चंदू खमारू बनाम नयन मलिक (2011) 12 एस. सी. सी. 314: [2011] 11 एससीआर 112;

एपी ट्रांस्को बनाम साई रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड **(2011)**

ई.

11 एससीसी 34:[2010] 8 एससीआर 636; बी. एस. ई. एस. लिमिटेड बनाम.टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (2004) 1 एस. सी. सी. 195:[2003] 4 पूरक।

एस. सी. आर. **932**; बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर बनाम मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, जबलपुर (1969) 1 एससीसी 200:[1969] 2 एस. सी. आर. 939; एपी राज्य बनाम.

च

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड **(2002) 5** एससीसी

203 :[2002] 3 एस. सी. आर. 278; उत्तर प्रदेश पावर

निगम लिमिटेड बनाम अनीस अहमद **(2013) 8** एस. सी. सी. **491:[2013] 13** एस. सी. आर. **388**; जीवेंद्र नाथ कौल बनाम कलेक्टर /

जिला मजिस्ट्रेट (1992) 3 एस. सी. सी. 576:[1992] 3 एससीआर

642; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हिंदुस्तान एल्यूमीनियम

जी.

निगम (1979) 3 एससीसी 229:[1979] 3 एससीआर 709;

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बस्सी शीत भंडारण,

खरार और एक अन्य (1994) 2 पूरक एस. सी. सी. 124:[1994]

3 एस. सी. आर. 33; जे. अगदाम्बा पेपर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (1983) 4 एस. सी. सी. 508:

एच.

647

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

क.

[1984] 1 एस. सी. आर. **165**; बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम परमेश्वर कुमार अग्रवाल **(1996) 4** एस. सी. सी. **686:[1996] 3** पूरक।एस. सी. आर. **29**; फेरो मिश्र धातु निगम।लिमिटेड बनाम ए

पी राज्य विद्युत बोर्ड (1993) 4 पूरक एस. सी. सी. 136:

[1993] 3 एस. सी. आर. **199**; इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ

एमपी (2000) 3 एससीसी 379:[2000] 1 एससीआर 925; हरियाणा

राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हनुमान राइस मिल्स, धनौर

(2010) 9 एससीसी 145:[2010] 10 एससीआर 217; जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.भारत संघ (2007) 13 एससीसी 673:[2007]

12 एससीआर **136**; एम. एल. अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एम. वी. वेंकट

शास्त्री एंड संस (1969) 1 एस. सी. सी. 573:[1969] 3 एस. सी. आर. 513;

अहमदाबाद नगर निगम बनाम हाजी अब्दुलगफुर हाजी हुसैनभा (1971) 1 एस. सी. सी. 757; दत्तात्रेय शंकर मोटे बनाम आनंद चिंतामन दातार और अन्य। (1974) 2 एससीसी 799:[1975] 2 एससीआर 224; कर्नाटक राज्य बनाम श्रेयस

ग

पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (2006) 1 एससीसी 615:[2006] 1 एससीआर 235;

ए. आई. चम्पदानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक

डी.

(2009) 4 एससीसी 486:[2009] 2 एससीआर 705; अजमेर विद्युत

विट्रान निगम लिमिटेड बनाम रहमतुल्लाह खान **(2020) 4**

एससीसी 650:[2020] 2 एस. सी. आर. 929; मेसर्स प्रेम कोर्टेक्स बनाम उत्तर

हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड निर्णय डी.

5.10.2021 2009 के सीए 7235 में; बिहार एसईबी बनाम आइसबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2020) 20 एससीसी 745:
[2020] 6 एस. सी. आर. 232;

ई.

मेसर्स स्वास्टिक इंडस्ट्रीज बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत

बोर्ड (1997) 9 एससीसी 465:[1997] 1 एससीआर 532;

कुसुमम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड

(2008) 12 एस. सी. सी. 212:[2008] 9 एससीआर 752; यू. टी.

चंडीगढ़ प्रशासन बनाम अमरजीत सिंह **(2009) 4**

च

एससीसी 660:[2009] 4 एस. सी. आर. 54; मध्य प्रदेश राज्य बनाम टीकमदास (1975) 2 एस. सी. सी. 100:
[1975] पूरक।एससीआर

234; विशेष अधिकारी, वाणिज्य, उड़ीसा की पूर्वोत्तर विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम रघुनाथ

पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 13 एस. सी. सी. 479:[2012]

13 एस. सी. आर. 71; अमर चंद्र बनाम उत्पाद शुल्क कलेक्टर,

जी.

त्रिपुरा (1972) 2 एससीसी 442:[1973] 1 एस. सी. आर. 533; ग्रासिम

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर **(2002) 4 एस. सी. सी. 297:[2002] 2 एस. सी. आर. 945;**
लोकमत न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड।

बनाम शंकरप्रसाद (1999) 6 एस. सी. सी. 275:[1999] 3 एससीआर

907; जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम. टिहरी हाइड्रो

एच.

648 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

विकास निगम।(इंडिया) लिमिटेड **(2019) 17 एससीसी 786:[2019] 2 एस. सी. आर. 41;** एडोनी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड **(1976) 4 एस. सी. सी. 68:[1977] 1 एस. सी. आर. 133;** मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल **(1978)**

3 एससीसी 248:[1978] 3 एस. सी. आर. 913; वालपाराइसो कोट्टाराथिल

कोचुनी बनाम मद्रास और केरल राज्य **[1960] 3 एससीआर 887;** भेल बनाम ग्लोब हाई-फैब्स लिमिटेड **(2015) 5 एससीसी 718;** टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम भारत के फार्मास्युटिकल उत्पाद

लिमिटेड (2008) 7 एससीसी 619:[2008] 9 एस. सी. आर. 267; एल. आई. सी. बनाम डी. जे. बहादुर (1981) 1 एस. सी. सी. 315:[1981] 1 एससीआर 1083; यूपी

राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरि शंकर जैन **(1978) 4**

ग

एससीसी 16:[1979] 1 एस. सी. आर. 355; के. एस. एल. एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 166:[2014] 14 एस. सी. आर. 1097-संदर्भित।

सूरज बनाम के. एस. ई. बी. 2005 (3) के. एल. टी. 856; ए. रामचंद्रन बनाम के. एस. ई. बी. 2000 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 75-संदर्भित।

डी.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1995] 1 एससीआर 847

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

[2004] 3 एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

ई.

[1998] 2 एससीआर 620

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 635 पैरा 20 [2008] 15 एस. सी. आर. 766 पैरा 21 [2020] 4 एस. सी. आर. 295 पैरा 22 [2011] 11 एस. सी. आर. 112 पैरा 31 [2014] 6 एस. सी. आर. 50 पर निर्भर था

च

पैरा **32 [2010] 8 एस. सी. आर. 636 पैरा 38 [2003] 4 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 932 पैरा 39 [1969] 2 एस. सी. आर. 939 पैरा 44 [2002] 3 एस. सी. आर. 278 पैरा 44 [2013] 13 एस. सी. आर. 388 पैरा 46 ए.**

जी.

एच.

649

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

[1992] 3 एससीआर 642

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[1979] 3 एससीआर 709

संदर्भित किया गया है

पैरा 66

[1994] 3 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 69

[1984] 1 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पैरा 69

[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 29 पैरा 69 [1993] 3 एस. सी. आर. 199 को संदर्भित करता है, पैरा 70 [2000] 1 एस. सी. आर. 925 को संदर्भित करता है, पैरा 73 [1991] 3 को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 242 पैरा 75 [1985] 2 एस. सी. आर. 1028 पैरा 75 [1964] 7 एस. सी. आर. 456 पैरा 76 [2010] 10 एस. सी. आर. 217 पैरा 77 [2007] 12 एस. सी. आर. 136 पैरा 82 पैरा 83

ग

डी.

[2010] 3 एससीआर 609

पीछा किया।

[1969] 3 एससीआर 513

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

(1971) 1 एस. सी. सी. 757

संदर्भित किया गया है

पैरा **93**

ई.

[1975] 2 एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पैरा **96**

[2006] 1 एससीआर 235

संदर्भित किया गया है

पैरा **96**

[2009] 2 एससीआर 705

संदर्भित किया गया है

पैरा **97**

च

[1967] 3 एससीआर 661

लागू नहीं होने वाला पैरा **105**

[1995] 1 एससीआर 304

प्रतिष्ठित

पैरा **105**

[1989] 1 पूरक।एस. सी. आर. 692 विशिष्ट पैरा **105** **[2020] 2 एस. सी. आर. 929** पैरा **114** **[1999] 2 एस. सी. आर. 372** लागू नहीं हुआ पैरा **116** **[2020] 6 एस. सी. आर. 331** पैरा **121** **[1997] 1 एस. सी. आर. 532** पैरा **123** को संदर्भित

जी.

एच.

650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट **[2023] 9 एस. सी. आर.**

क.

[2008] 9 एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पैरा **125**

[2012] 8 एससीआर 118

प्रतिष्ठित

पैरा **132**

[2016] 3 एससीआर 1126

प्रतिष्ठित

पैरा 132

[2009] 4 एससीआर 54

संदर्भित किया गया है

पैरा 134

[1975] पूरक।पैरा 160 [2012] 13 एस. सी. आर. 71 पैरा 185 [1973] 1 एस. सी. आर. 533 पैरा 187 [2002] 2 एस. सी. आर. 945 पैरा 187 [1999] 3 एस. सी. आर. 907 पैरा 188 [2019] 2 एस. सी. आर. 41 पैरा 188 [1977] 1 एस. सी. आर. 133 पैरा 188 [1978] 3 एस. सी. आर. 913 पैरा 194 [1960] 3 एस. सी. आर. 887 पैरा 196 (2015) 5 एस. सी. सी. 718 पैरा 196 [2008] 9 एस. सी. आर. 267 पैरा 282 [1981] 1 एस. सी. आर. 1083 पैरा 284 [1979] 1 एस. सी. आर. 355 पैरा 285 [2014] 14 एस. सी.

ग

डी.

ई.

च

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2004 की सिविल अपील सं. 2109-2110।

1991 के ओ. पी. <आई. डी. 2 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 3 और 2003 के आर. पी. सं. 307 में दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

जी.

सह

सिविल अपील संख्या 2004 की 2108,2005 की 7303,2022 की 6579,2022 की 3018,7169,6591,6595,6879-6881,6592,6828,7064,6590 और 2022 की 3640।

एच.

651

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

क.

रंजीत कुमार, विजय हंसारिया, एम. जी. रामचंद्रन, अजीत एस. भासमे, वी. गिरी, शेखर नाफडे, राणा मुखर्जी, भरत पटेल, पी. एस. पटवालिया, रवींद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री सायरी बसु मलिक, अभिनव गर्ग, शाश्वत सिंह, ई. सी. अग्रवाल, प्रदीप मिश्रा, दिलीप ध्यानी, मनोज कुमार शर्मा, क्षितिज मित्तल, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री श्रीजा चौधरी, सुश्री काव्या झावर, सुश्री सृष्टि खिंदारिया, भार्गव वी. देसाई, सुश्री चारु मोदी, दीपांशु, संजय कुमार विसेन, मुकेश कुमार पांडे, सुरेश कुमार भान, संदीप जोशी, सुश्री रितु रस्तोगी, सुश्री मोहिनी कुमारी, अमन, ई. एम. एस. अनम, पुनीत जैन, क्रिस्टी जैन, योगित कामत, मान अरोड़ा।उपस्थित दलों के लिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

652

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई टेबल ऑफ कंटेंट *

ए. सारांश. 4 बी. विनियामक व्यवस्था. 5 सी. कानून में स्थिति. 10 डी. मुद्दे. 14 ई. प्रस्तुतियाँ. 15 एफ. विश्लेषण. 25 जी. अनुप्रयोग:व्यक्तिगत मामलों के तथ्य. 89 I. केरल. 90 II. महाराष्ट्र. 99 III. गुजरात. 132 IV. असम. 166 बनाम पश्चिम बंगाल. 170 एच. समानता और निष्पक्षता. 175 I. निष्कर्ष. 177

ग

डी.

ई.

ए. सारांश

1. अपीलों के इस समूह के उन्नीस मामले तथ्यों के एक समान पैटर्न का पालन करते हैं। पिछले मालिकों द्वारा परिसर में बिजली की खपत के लिए बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। पहले के मालिकों ने पैसे उधार लिए थे या अपने परिसर की प्रतिभूति पर ऋण लिया था। कुछ मामलों में, पूर्व मालिक परिसमापन में चला गया। परिसरों को नीलामी बिक्री में आम तौर पर "जैसा है जहां है" के आधार पर बेचा जाता था। नीलामी में संपत्तियों को खरीदने वाले नए मालिकों ने उस परिसर के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया, जिसमें बकाया का भुगतान करने में विफल रहने पर बिजली काट दी गई थी। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज ने बिजली कनेक्शन देने से तब तक इनकार कर दिया जब तक कि नीलामी खरीदार पिछले मालिक के बकाया का भुगतान नहीं करता। यह अस्वीकृति अधीनस्थ कानूनों, अधिसूचनाओं, बिजली आपूर्ति संहिताओं या राज्य विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों से प्राप्त हुई थी।

च

जी.

एच.

*एड। ध्यान दें: तालिका में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

653

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

बिजली की आपूर्ति से इनकार करने के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाएं दायर की गईं, जिसके परिणामस्वरूप निर्णय अपील में हैं।

2. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुपर एंड

इस न्यायालय ने 24 अगस्त 2006 के एक आदेश द्वारा बिजली के बकाया की वसूली के मुद्दे से निपटने के लिए सिविल अपील को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। संदर्भ आदेश में इस सवाल का उल्लेख किया गया कि क्या बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क है जहां तक हस्तांतरणकर्ता और इकाई के हस्तांतरणकर्ता का संबंध है।

3. विवाद की समान प्रकृति से जुड़े मामलों को 1 नवंबर 2007 के एक आदेश द्वारा उपरोक्त संदर्भ के साथ जोड़ा गया था। इन अपीलों में जो मुद्दा उठाया गया है, वह यह है कि क्या पूर्व मालिक से बकाया बिजली के बकाया का दावा बाद के मालिक से किया जा सकता है, जिसने बंधक लागू करने या लेनदारों के बकाया का भुगतान करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में संपत्ति का अधिग्रहण किया है।

ग

डी.

B. विनियामक व्यवस्था

4. भारत के संविधान के तहत बिजली एक समवर्ती विषय है। विद्युत अधिनियम 2003 2 के अधिनियमन से पहले, विद्युत अधिनियम 1910 3 भारत में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उपयोग को नियंत्रित करता था। 1910 के अधिनियम ने बिजली की आपूर्ति से संबंधित केबल बिछाने और अन्य कार्यों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया। इसने विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक कानूनी ढांचा भी निर्धारित किया और निजी लाइसेंसधारियों के माध्यम से बिजली उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बिजली की आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों पर कुछ जिम्मेदारियां और दायित्व लगाए।

ई.

च

5. 1910 के अधिनियम की धारा 2 (सी) ने "उपभोक्ता" को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो लाइसेंसधारी या अधिनियम के तहत जनता को ऊर्जा की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए जुड़ा हुआ था। धारा 21 (2) एक लाइसेंसधारी को उन व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को विनियमित करने के लिए शर्तें बनाने का अधिकार देती है जो उपभोक्ता थे या बनने का इरादा रखते थे। धारा 22 एक लाइसेंसधारी को आपूर्ति करने के लिए बाध्य करती है

जी.

1 सिविल अपील सं. 2005 का 5312-5313 2 "2003 अधिनियम"

3 "1910 ऐक्ट "

एच.

654

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

विद्युत ऊर्जा, उपयोग पर, आपूर्ति क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को उसी शर्तों पर, जिस पर उसी क्षेत्र का कोई अन्य व्यक्ति हकदार था। धारा 24 ने लाइसेंसधारक को बिजली की आपूर्ति बंद करने का अधिकार दिया यदि कोई व्यक्ति लाइसेंसधारक के कारण किसी भी शुल्क या ऊर्जा के लिए राशि का भुगतान करने में लापरवाही करता है।

6. 1910 का अधिनियम भारत में बिजली के समन्वित विकास और "ग्रिड-प्रणाली" के लिए अपर्याप्त पाया गया। इसलिए, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 4 को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति को तर्कसंगत बनाने और बिजली के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 1948 के अधिनियम ने राज्य सरकारों को धारा 5 के तहत राज्य विद्युत बोर्डों का गठन करने के लिए अनिवार्य किया और उन्हें ग्रिड-प्रणाली के प्रशासन और राज्य में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी। धारा 26 में प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के पास 1910 के अधिनियम के तहत एक लाइसेंसधारी की सभी शक्तियां और दायित्व होंगे। धारा 49 ने बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार दिया, जो लाइसेंसधारी नहीं है। धारा 70 (2) के संदर्भ में, 1948 के अधिनियम के प्रावधान 1910 के अधिनियम के अतिरिक्त थे, न कि अपमान में।

ग

डी.

7. संसद ने सरकार को शुल्क निर्धारण से दूर रखने के उद्देश्य से विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 5 लागू किया। 1998 के अधिनियम ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का निर्माण किया और राज्य सरकारों को राज्य विद्युत नियामक आयोग बनाने में सक्षम बनाया।

ई.

8. संसद ने 2003 के अधिनियम को लागू करके 1910 के अधिनियम, 1948 के अधिनियम और 1998 के अधिनियम के प्रावधानों को समेकित और सुसंगत बनाया। इस प्रक्रिया में, 2003 के अधिनियम ने उपरोक्त तीन कानूनों को निरस्त कर दिया। 2003 के अधिनियम का लंबा शीर्षक इस प्रकार है:

च

“बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए एक अधिनियम और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली शुल्क को तर्कसंगत बनाने, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करने, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और

जी.

4 “1948 अधिनियम "5" 1998 अधिनियम

एच.

655

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए।”

9. 2003 का अधिनियम बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुसरण में लागू किया गया है। 2003 के अधिनियम के अन्य उद्देश्यों में सरकार से नियामक आयोगों को नियामक जिम्मेदारियां सौंपना, बिजली उत्पादन को अलग करना, कैप्टिव उत्पादन को बढ़ावा देना और खुली पहुंच संचरण को प्रोत्साहित करना शामिल है। 2003 के अधिनियम की धारा 2 (15) 'उपभोक्ता' को 1910 के अधिनियम की धारा 2 (सी) के समान शब्दों में

परिभाषित करती है। 2003 के अधिनियम का भाग VI बिजली के वितरण से संबंधित है। धारा 43 किसी मालिक या अधिभोगकर्ता के परिसर में बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी पर एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व 6 डालती है। राज्य आयोग को धारा 50 के तहत बिजली शुल्क की वसूली, बिजली शुल्क के बिलिंग के लिए अंतराल और भुगतान न करने पर बिजली की आपूर्ति को काटने के लिए एक बिजली आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। धारा 56 के तहत, उत्पादन कंपनी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति की बिजली आपूर्ति काट सकता है जो बिजली के लिए किसी भी शुल्क या राशि का भुगतान करने में लापरवाही करता है। धारा 181 (2) (x) में प्रावधान है कि राज्य आयोग अन्य बातों के साथ-साथ धारा 50 के तहत विद्युत आपूर्ति संहिता के लिए विनियम बना सकता है।

ग

डी.

10. 1910 के अधिनियम, 1948 और 2003 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में, विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं जैसे राज्य विद्युत नियामक आयोगों, राज्य विद्युत बोर्डों और वितरण लाइसेंसधारियों ने आपूर्ति की शर्तों को अधिसूचित किया, जिसमें परिसर के नए मालिक को पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अपीलों के समूह में उन्नीस मामले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों से उत्पन्न होते हैं।

ई.

च

11. केरल में, केरल राज्य विद्युत बोर्ड 7 ने 1990 में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों को अधिसूचित किया। आपूर्ति की शर्तों की शर्त 15 (ई) में प्रावधान है कि किसी भी परिसर को फिर से कनेक्शन या नया कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

जी.

12. महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड 8 ने बिजली की आपूर्ति के लिए एम. एस. ई. बी. की शर्तें और विविध शुल्क तय किए।

6 "यूएसओ "7" केएसईबी "8" एमएसईबी "

एच.

656

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

विद्युत ऊर्जा, 1976 9 1948 अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग में। एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों के खंड 23 (बी) ने बोर्ड को चूक करने वाले उपभोक्ता के उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, हस्तांतरणकर्ता, समनुदेशक या उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति या नया कनेक्शन देने से इनकार करने की अनुमति दी। 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और आपूर्ति की अन्य शर्तें) विनियम 2005 10 बनाए गए। विनियमन 10.5 provides कि अवैतनिक बिजली बकाया संपत्ति पर एक शुल्क का गठन करता है और हस्तांतरणकर्ता से वसूल किया जा सकता है (आपूर्ति की गई बिजली के लिए अधिकतम छह महीने के अवैतनिक शुल्क के अधीन)। 13. गुजरात में, गुजरात विद्युत बोर्ड ने 2001 में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शर्तों और विविध शुल्कों में शर्त 2 (जे) जोड़ी। 11 इस शर्त ने बोर्ड को इस बात पर जोर देने का अधिकार दिया कि परिसर का नया अधिभोग फिर से जोड़ने या नए कनेक्शन जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में पिछले उपभोक्ता के बकाया बिजली का भुगतान करे। 2005 में, गुजरात विद्युत नियामक बोर्ड ने गुजरात विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) विनियम, 2005 12 को अधिसूचित किया। गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के खंड 4.1.11 में प्रावधान किया गया है कि नए कनेक्शन

के लिए आवेदन के समय केवल आवेदक का बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने की आवश्यकता थी। उक्त खंड को बाद में 2010 में संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि वितरण लाइसेंसधारी को फिर से कनेक्शन या नए कनेक्शन के लिए आवेदन स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उन परिसरों से संबंधित किसी भी बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग

डी.

ई.

14. असम में, असम विद्युत नियामक आयोग 13 ने असम विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) विनियम, 2004 तैयार किए। 14 बिजली आपूर्ति की मांग से संबंधित खंड 3.6 में एक नए परिसर में रहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी बकाया बिजली का विधिवत भुगतान किया जाए और उसका भुगतान किया जाए।

च

15. पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2012-15

जी.

9 "एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तें "

10 "महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 "11" गुजरात आपूर्ति की शर्तें "

12 "गुजरात विद्युत आपूर्ति कोड "13" एईआरसी "

14 "एईआरसी आपूर्ति कोड "

एच.

15 "डब्ल्यू. बी. विद्युत आपूर्ति कोड "

657

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

2003 के अधिनियम के तहत अधिसूचित। खंड 3.4।2 उक्त विनियमों में से लाइसेंसधारी को नए उपभोक्ता से परिसर के संबंध में पिछले उपभोक्ता के बकाया की वसूली करने का अधिकार केवल तभी है जब पिछले उपभोक्ता और नए उपभोक्ता के बीच कोई सांठगांठ हो।

16. परिसर के बाद के मालिकों या कब्जाधारियों ने विद्युत उपयोगिताओं द्वारा अधिनियमित आपूर्ति और बिजली आपूर्ति संहिताओं की शर्तों को संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी, जब उन्हें पिछले मालिकों के बकाया या परिसर से संबंधित बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

C. कानून में स्थिति

ग

17. 2003 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले, ईशा मार्बल्स बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, 16 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक वैधानिक विनियमन द्वारा परिसर पर आरोप लगाए जाने के अभाव में, एक नीलामी

खरीदार को बिजली के अनुदान की पूर्व शर्त के रूप में बिजली बकाया के पिछले बकाया को चुकाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने 1910 के अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में इस बात पर जोर देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया कि आपूर्ति का अनुबंध केवल बिजली बोर्ड और पिछले उपभोक्ता के बीच था, और बाद वाला खरीदार 1910 के अधिनियम के अर्थ में न तो उपभोक्ता था और न ही उसका बिजली बोर्ड के साथ कोई संविदात्मक संबंध था। इस न्यायालय ने कहा कि हालांकि बिजली सार्वजनिक संपत्ति है जिसकी कानून को रक्षा करनी चाहिए, फिर भी कानून, जैसा कि उस समय था, परिसर के बाद के खरीदार के खिलाफ पिछले उपभोक्ता के अवैतनिक बिजली शुल्क के दायित्व को लागू करने के लिए अपर्याप्त था। ईशा मार्बल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय को किसी भी वैधानिक नियम, विनियमन या आपूर्ति की शर्तों से निपटने की आवश्यकता नहीं थी जो बाद के खरीदार पर बिजली बकाया के भुगतान के लिए दायित्व के अधिरोपण से संबंधित थी।

डी.

ई.

च

18. इसके बाद अहमदाबाद में तीन न्यायाधीशों की एक और पीठ बनी।

इलेक्ट्रिसिटी कं. लिमिटेड बनाम गुजरात इंस (पी) लिमिटेड, 17 ने माना कि एक मामले में

नया कनेक्शन, हालांकि परिसर समान हैं, नीलामी खरीदारों को उस संबंध में एक विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में परिसर को आपूर्ति की गई बिजली के संबंध में पिछले मालिकों द्वारा किए गए बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, इस न्यायालय ने राय दी कि ईशा मार्बल्स (ऊपर) में निर्धारित "कानून के व्यापक प्रस्तावों" पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

जी.

16 1995 एससीसी (2) 648 17 (2004) 3 एससीसी 587

एच.

658 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

19. हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

विद्युत बोर्ड, 18 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विद्युत बोर्डों द्वारा अधिसूचित आपूर्ति के नियम और शर्तें वैधानिक हैं क्योंकि उन्हें 1948 अधिनियम की धारा 49 के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। केवल यह तथ्य कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत समझौते किए गए थे, समझौते को प्रकृति में संविदात्मक नहीं बनाता था।

20. इस न्यायालय के बाद के निर्णयों की एक श्रृंखला में, दो-न्यायाधीशों की पीठ के विभिन्न निर्णयों ने बाद के खरीदारों से बकाया की वसूली को सक्षम करने वाले विशिष्ट वैधानिक नियमों पर ध्यान दिया है। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने ईशा मार्बल्स (उपरोक्त) को अलग किया, जहां न्यायालय के पास इसी तरह के प्रावधानों पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। दक्षिण हरियाणा में बिजली वितरण

ग

निगम लिमिटेड बनाम मेसर्स पैरामाउंट पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड, 19 यह न्यायालय था

आपूर्ति की प्रासंगिक शर्तों के खंड 21 ए के साथ व्यवहार करते हुए, जो एक लाइसेंसधारी को हस्तांतरणकर्ता से बकाया देय राशि के भुगतान की मांग करने का अधिकार देता है यदि वे सेवा कनेक्शन चाहते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ईशा मार्बल्स (उपर्युक्त) को खंड 21 ए को निरस्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस मामले में न्यायालय के

पास इसी तरह के खंड के प्रभाव पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। इस मामले को एक नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया था क्योंकि इसने आपूर्ति की शर्तों के खंड 21 ए के निहितार्थ पर निर्णय नहीं दिया था।

डी.

21. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम डी. वी. एस. स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, 20 में इस न्यायालय ने कहा कि

ई.

अनुज्ञप्तिधारी या बिजली वितरक वैधानिक नियमों, विनियमों या आपूर्ति की शर्तों को पूरा करने पर जोर दे सकते हैं जब तक कि वे मनमाने और अनुचित न हों। यह भी कहा गया कि बिजली की आपूर्ति बहाल करने या परिसर को नया कनेक्शन देने से पहले एक नए खरीदार द्वारा पिछले मालिक के बिजली बकाया की निकासी को अनिवार्य करने वाली आपूर्ति की शर्तों को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

च

22. पैरामाउंट पॉलिमर में तैयार की गई कानून की स्थिति

(ऊपर) और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ऊपर)

जी.

इस न्यायालय द्वारा आगामी निर्णयों में लगातार इसका पालन किया गया है। हाल ही में,

तेलंगाना राज्य दक्षिणी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम

18 (1998) 4 एस. सी. सी. 470 19 ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2 20 (2009) 1 एस. सी. सी. 210 ए

एच.

659

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

श्रीघधा बेवरेजेस, 21 इस न्यायालय ने पिछले मालिकों के बिजली बकाया के संबंध में बाद के मालिकों के दायित्व पर न्यायिक सोच को दोहराया। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

“ 16.1. वह बिजली बकाया, जहां वे बिजली अधिनियम के तहत वैधानिक हैं और आपूर्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए माफ नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 56 (बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 24 के साथ समान रूप से), और विशुद्ध रूप से संविदात्मक प्रकृति के बकाया के रूप में भाग नहीं ले सकते हैं। जहां, विचाराधीन ई-नीलामी सूचना के मामलों की तरह, बिजली बकाया का अस्तित्व, चाहे उसकी मात्रा निर्धारित की गई हो या नहीं, विशेष रूप से खरीदार के दायित्व के रूप में उल्लेख किया गया है और बिक्री "जैसा है वैसा ही है, जो कुछ भी है और बिना आमदनी के" पर है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बिजली बकाया का भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी (खरीदार) पर मौजूद है।

ग

डी.

16.3. कनेक्शन या पुनर्संयोजन पर बहस वर्तमान जैसे मामलों में मौजूद नहीं होगी जहां दोनों पहलू आपूर्ति के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 8.4 के अनुसार शामिल हैं।" कानूनी और निर्णयात्मक ढांचे का चरण निर्धारित करने के बाद, हमें अपीलों के वर्तमान समूह पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।

ई.

डी. मुद्दे

23. पक्षों की प्रस्तुतियों के आधार पर, निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दे हैं:

ए। क्या 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व उस परिसर से जुड़ा है जिससे कनेक्शन मांगा गया है;

च

बी। चाहे नीलामी खरीदार द्वारा मांगी गई बिजली आपूर्ति के कनेक्शन में पुनः कनेक्शन शामिल हो या नया कनेक्शन; ग. क्या परिसर के नीलामी-खरीदार से पिछले मालिक या कब्जाधारक के बकाया की वसूली करने की शक्ति 2003 के अधिनियम की नियामक व्यवस्था के अंतर्गत आती है।

जी.

घ. नीलामी-खरीदार से पिछले मालिक या कब्जाधारक के बकाया की वसूली को सक्षम करने की शक्ति क्या हो सकती है

एच.

21 (2020) 6 एस. सी. सी. 404

660

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

राज्य आयोगों द्वारा अधीनस्थ कानून के माध्यम से प्रदान किया गया;

ई. क्या 1910 अधिनियम, 1948 अधिनियम और 2003 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं जो परिसर पर शुल्क या बोझ के सृजन को सक्षम बनाते हैं;

च. क्या 2003 के अधिनियम की धारा 56 (2) के तहत प्रदान की गई दो साल की सीमा के बाद बिजली बकाया की वसूली पर वैधानिक प्रतिबंध, ऐसे बकाया की वसूली के लिए विद्युत उपयोगिताओं के नागरिक उपचारों पर प्रभाव डालेगा; और

छ. परिसर के बिजली बकाया के संदर्भ में या उसके बिना, "जैसा है वैसा ही" आधार पर परिसर की नीलामी-बिक्री का क्या निहितार्थ है?

ग

ई. प्रस्तुतियाँ

24. उपर्युक्त मुद्दों को उनके उचित संदर्भ में रखने के लिए, हम पक्षों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत व्यापक कानूनी प्रस्तुति का उल्लेख करते हैं।

डी.

I. विद्युत उपयोगिताएँ

25. सर्वश्री एम. जी. रामचंद्रन, श्री रंजीत कुमार, श्री विजय हंसारिया, श्री अजीत भास्मे, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

ई.

क. यू. एस. ओ. निरपेक्ष नहीं है।

आई. 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने का लाइसेंसधारी का कर्तव्य पूर्ण नहीं है। धारा 43 में प्रावधान है कि एक आवेदक को बिजली की आपूर्ति का हकदार बनने के लिए संबंधित दायित्वों को पूरा करना होगा; ii. धारा 43 (1) "अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर" शब्दों के साथ शुरू होती है, जो 2003 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों का अनुपालन करती है, जिसमें धारा 50 भी शामिल है जो राज्य आयोग को बिजली आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है।

च

जी.

iii. धारा 43 (1) के स्पष्टीकरण में आवेदक से आवश्यक शुल्क और अन्य अनुपालनों के भुगतान को दर्शाने वाले दस्तावेजों के साथ सभी मामलों में पूर्ण आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है। इस भुगतान में न केवल आवेदन शुल्क शामिल है, बल्कि इसमें ए से संबंधित शुल्क भी शामिल हैं।

एच.

661

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

बिजली की आपूर्ति के लिए; अन्य अनुपालनों में किसी भी लंबित या बकाया बकाया का उचित निर्वहन शामिल होगा, यदि लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा करने की मांग की जाती है; और

iv. धारा 43 (2) विशेष रूप से प्रदान करती है कि आवेदक को बिजली की आपूर्ति की मांग के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के दायित्व को पूरा करना होगा। धारा 43 में प्रयुक्त "मूल्य" शब्द बिजली की आपूर्ति के लिए विचार है।

बी। बिजली की आपूर्ति परिसर के संबंध में है।

आई. बिजली की आपूर्ति 2003 के अधिनियम की धारा 2 (15), 43, 45 और 50 के अनुसार "परिसर" के संदर्भ में है। 1910 के अधिनियम और 1948 के अधिनियम में भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद थे। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 56 और 1910 के अधिनियम की धारा 24 में वर्णित संबंध विच्छेद अनिवार्य रूप से चिन्हित परिसरों से संबंधित है।

ग

डी.

ii. धारा 2 (15) के तहत उपभोक्ता की परिभाषा

2003 अधिनियम में "कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर कुछ समय के लिए बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी के कार्यों से जुड़ा हुआ है।"

इसलिए अभिव्यक्ति "परिसर" बिजली की आपूर्ति के लिए निरंतर चिन्हित स्थान है, चाहे मालिक या अधिभोगकर्ता में कोई भी बदलाव हो; और

ई.

iii. विद्युत उपयोगिताओं के पास उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए एक बुनियादी ढांचा होना आवश्यक है। बिजली की आपूर्ति के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें संचालन और रखरखाव की लागत वहन करनी पड़ती है। इसलिए, यदि

दायित्व परिसर के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है, तो इस तरह के शुल्क अंततः सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा वहन किए जाएंगे क्योंकि यह शुल्क के निर्धारण में शामिल होगा।

च

ग. बिजली बकाया की वसूली के लिए विनियामक व्यवस्था

जी.

आई. 1948 के अधिनियम की धारा 49 विद्युत बोर्ड को ऐसे नियमों और शर्तों पर बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार देती है जो बोर्ड उचित समझता है। 1948 के अधिनियम की धारा 79 के तहत बोर्ड ऐसे विनियम बना सकता है जो अधिनियम और बनाए गए नियमों के साथ असंगत न हों।

एच.

662 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

इसके नीचे हैदराबाद वनस्पति (ऊपर) में यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विद्युत बोर्ड द्वारा 1948 अधिनियम की धारा 49 के तहत तैयार किए गए आपूर्ति के नियम और शर्तें वैधानिक हैं।

ii. 2003 के अधिनियम के तहत आपूर्ति के नियम और शर्तें एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद 2003 के अधिनियम की धारा 181 (2) (x) के साथ पठित धारा 50 के संदर्भ में स्वतंत्र नियामकों द्वारा तैयार की गई हैं। इसलिए, राज्य आयोग द्वारा बनाई गई विद्युत आपूर्ति संहिता एक अधीनस्थ कानून है और इसका एक वैधानिक चरित्र है। यह वैधानिक प्राधिकरण आपूर्ति संहिता को बाद के मालिक से पिछले मालिक के बकाया की वसूली का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है; और

ग

iii. बकाया राशि के भुगतान की शर्त धन की अनिवार्य निकासी नहीं है और इसके लिए संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा प्राथमिक कानून की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शर्त एक अधीनस्थ कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

डी.

घ. परिसर पर शुल्क के रूप में बिजली बकाया

आई.आई. यह विद्युत उपयोगिताओं का मामला नहीं है कि इस रूप में संपत्ति पर कोई बंधक या शुल्क है कि लाइसेंसधारी एक सुरक्षित लेनदार है। लाइसेंसधारक को नया कनेक्शन देने से पहले परिसर के बकाया भुगतान पर जोर देने का अधिकार है।

ई.

ई. उपयोगिताओं के बिजली बकाया की वसूली के लिए नागरिक और वैधानिक उपाय

च

(i) 2003 के अधिनियम की धारा 56 (2) कानून के अनुसार वसूली के अन्य तरीकों के माध्यम से बिजली बकाया की वसूली पर रोक नहीं लगाती है।

(ii) 2003 के अधिनियम की धारा 56 (2) के तहत दो साल की सीमा लाइसेंसधारी द्वारा कनेक्शन काटने पर रोक के संदर्भ में है। बकाया राशि का भुगतान न करने पर बिजली बंद होने के बाद धारा 56 के तहत कोई सीमा नहीं है। बिजली बकाया की वसूली के लिए आपूर्ति की शर्त 2003 के अधिनियम की धारा 56 (2) के तहत सीमा द्वारा वर्जित नहीं है; और

जी.

एच.

663

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

(iii) बकाया भुगतान होने तक बिजली कनेक्शन से इनकार करने का वितरण लाइसेंसधारी का अधिकार एक निरंतर अधिकार है और इसे समाप्त नहीं कहा जा सकता है। इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब नया मालिक या अधिभोगकर्ता कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी से संपर्क करता है।

च. "जैसा है, जहां है" के आधार पर परिसरों की नीलामी-बिक्री का प्रभाव

आई. आई. नीलामी खरीदारों को बकाया चुकाने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था क्योंकि सार्वजनिक नीलामी-"जैसा है वैसा ही" आधार पर परिसर की बिक्री में बिजली बकाया के भुगतान के विशिष्ट संदर्भ के साथ या उसके बिना उक्त परिसर के संबंध में सभी देनदारियों को स्वीकार करने की शर्त शामिल होगी।

ग

आई.ii. परिसर का अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों पर यह दायित्व है कि वे नीलामी में बोली मूल्य का हवाला देते समय लाइसेंसधारी से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र सत्यापित करें और प्राप्त करें या अन्यथा बकाया राशि को ध्यान में रखें; और

डी.

ii.iii. खरीदार परिसर के बकाया भुगतान की आवश्यकता के बारे में जानकारी से इनकार नहीं कर सकता है जब ये आपूर्ति या आपूर्ति संहिता की शर्तों के लिए प्रदान किए जाते हैं।

ई.

II. नीलामी खरीदार

26. नीलामी खरीदारों की ओर से सर्वश्री शेखर नाफड़े, श्री वी. गिरि, श्री पी. एस. पटवालिया, श्री एस. गणेश, वरिष्ठ वकील और श्री पुनीत जैन, श्री अमर दवे, श्री ई. एम. एस. अनम, श्री डी. एन. रे, श्री टी. श्रीनिवास मूर्ति, श्री भरत पटेल, श्री राम लाल रॉय, श्री पूर्वश जितेंद्र मलकान और श्री एम. वाई. देशमुख ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत करने का आग्रह किया है:

च

ए. यू. एस. ओ निरपेक्ष है।

i. (i) बिजली संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 53, 54 और 56 के अर्थ के भीतर और माल की बिक्री अधिनियम 1930 के तहत वस्तुओं का गठन करती है।

जी.

ii. (ii) 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने का दायित्व किसी शर्त से सुरक्षित नहीं है।

एच.

664

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिछले उपभोक्ता द्वारा किए गए बकाया का निर्वहन करना;

iii.(iii) 2003 के अधिनियम की धारा 43 (2) में "उचित कमीशन द्वारा निर्धारित मूल्य" वाक्यांश केवल वह मूल्य हो सकता है जिस पर वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, धारा 43 के तहत 'मूल्य' में पिछले उपभोक्ता के बकाया शामिल नहीं हो सकते हैं; (iv) धारा 43 के तहत विचार किए गए आवश्यक "शुल्क" और "अन्य अनुपालन" का भुगतान आवेदन शुल्क से संबंधित है, और इसे तीसरे पक्ष के बकाया भुगतान की आवश्यकता की शक्ति को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है; (v) किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा एक महीने के भीतर आवेदन पर बिजली की आपूर्ति करने का लाइसेंसधारी का वैधानिक कर्तव्य 2003 के अधिनियम की धारा 43 (1) में निहित है। इस वैधानिक दायित्व का एकमात्र अपवाद धारा 44 द्वारा प्रदान किया गया है जहां लाइसेंसधारी को चक्रवात, बाढ़, तूफान या अपने नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियों के कारण आपूर्ति देने से रोका जाता है; और (vi) विधायिका ने जानबूझकर उन सभी मूल आवश्यकताओं को शामिल किया है जिन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पूरा करना आवश्यक है, जिसे मुख्य रूप से 2003 के अधिनियम की धारा 43 (2), 45, 46, 47 और 48 के तहत दर्ज किया गया है। इसलिए, राज्य आयोग को नए कनेक्शन की मांग करने वाले बाद के मालिक पर पिछले मालिकों के बकाया की निकासी की पूर्व शर्त प्रदान करने के रूप में कोई अन्य मूल शर्त लागू करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। ऐसी कोई भी शर्त धारा 43 के विपरीत होगी।

ग

डी.

ई.

च

बी। बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता के संबंध में है।

(i) धारा 2 (15) के साथ-साथ 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा में "परिसर" का संदर्भ केवल एक स्थिति तय करने के लिए है, यानी संपत्ति के संबंध में क्षेत्र में काम करने वाले लाइसेंसधारी की पहचान करने के लिए है। इसलिए धारा 2 (15) के तहत उस "व्यक्ति" पर जोर दिया जाता है जो परिसर का मालिक या अधिभोगकर्ता है; और

जी.

एच.

665

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

(ii) धारा 2 (15), 43 और 44 "परिसर" को संदर्भित करती है क्योंकि एक साधारण निर्माता या वितरक उपभोक्ता को माल की आपूर्ति लेने के लिए इस कारखाने या गोदाम में आने के लिए जोर दे सकता है, वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति को उपभोक्ता के परिसर में ले जाने के लिए बाध्य है। इसलिए, जिस परिसर में आपूर्ति की जानी है, उसकी पहचान अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

ग. बिजली बकाया की वसूली के लिए विनियामक व्यवस्था

ए। 1910 के अधिनियम और 1948 के अधिनियम के प्रावधान बिजली बोर्ड को ऐसे परिसर के नए मालिक या कब्जाधारक से पिछले मालिक या कब्जाधारक के बिजली बकाया की वसूली करने का अधिकार नहीं देते हैं। बिजली बकाया का भुगतान

करने का दायित्व केवल उस व्यक्ति पर है जिसे बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह एक संविदात्मक दायित्व है; बी। 1948 के अधिनियम की धारा 49 केवल बोर्ड को संभावित उपभोक्ता के साथ किए जाने वाले अनुबंध में आपूर्ति की शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। आपूर्ति की ऐसी शर्तों को नियम या विनियम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होते हैं और इसलिए, विनियमों की प्रकृति नहीं हो सकती है और वे वैधानिक नहीं हैं; और

ग

डी.

ई.

ग. एक शर्त जिसमें एक आवेदक को नए कनेक्शन के लिए आवेदन पर विचार करने से पहले पिछले उपभोक्ता के पिछले बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, स्पष्ट रूप से अनुचित है। बकाया राशि पिछले उपभोक्ता द्वारा की गई चूक और विद्युत उपयोगिताओं की लापरवाही के कारण है, जिन्होंने अपनी डिस्कनेक्शन की शक्ति का सहारा लिए बिना, डिफॉल्ट के बावजूद बिजली की आपूर्ति जारी रखी।

च

घ. अधीनस्थ विधान

ए। एक व्यक्ति का दायित्व, चाहे वह वैधानिक हो या संविदात्मक, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए कानून में कोई ठोस प्रावधान न हो। दायित्व के इस तरह के प्रवर्तन को प्रत्यायोजित कानून के एक टुकड़े द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है;

जी.

बी। भले ही यह माना जाता है कि इस तरह के दायित्व को एक प्रत्यायोजित कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, मूल कानून को स्पष्ट रूप से करना चाहिए।

एच.

666

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

इस तरह के कानून बनाने की शक्ति निर्धारित करें। न तो 1910 के अधिनियम और न ही 1948 के अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है जो विद्युत बोर्ड को नए मालिक या विचाराधीन परिसर के अधिभोगियों से परिसर के पिछले मालिक या अधिभोगियों के बिजली बकाया की वसूली करने का अधिकार देता है।

ग. 2003 के अधिनियम की योजना, धारा 43 से 49 तक, यह स्पष्ट करती है कि 2003 के अधिनियम की धारा 181 के साथ पठित धारा 50 के तहत राज्य आयोग को या 2003 के अधिनियम की धारा 180 के तहत राज्य को किसी अन्य उपभोक्ता के पिछले बकाया की निकासी जैसी और ठोस शर्तों को जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है; और

ग

घ. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी नियम या विनियमन को तैयार करने के लिए, मूल विधान में शक्ति का एक विशिष्ट स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए।

डी.

ई. बिजली बकाया परिसर पर शुल्क नहीं है।

ए। बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क नहीं है क्योंकि वे भूमि के साथ नहीं चलते हैं। भूमि या किसी अन्य अचल संपत्ति पर केवल वैधानिक अधिभार के माध्यम से राजकोषीय शुल्क लगाया जा सकता है। 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत राज्य आयोग केवल बिजली की आपूर्ति के लिए नियम बना सकता है और उसके पास किसी भी वित्तीय अधिभार के लिए प्रावधान करने की कोई शक्ति नहीं है। केवल एक राज्य विधान सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 53 के तहत बिजली की खपत या बिक्री पर शुल्क लगाने का प्रावधान करके किसी संपत्ति पर शुल्क का प्रावधान कर सकता है।

ई.

च

बी। परिसर पर प्रभार बनाने के लिए 2003 के अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है और विनियमों के माध्यम से शुल्क लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि विषय वस्तु 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत नहीं आती है।

जी.

ग. आपूर्ति की शर्तें संविदात्मक हैं और इसलिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 के तहत शुल्क का गठन नहीं करती हैं। आपूर्ति की शर्तें एक अनुबंध में निहित हैं और एक शुल्क का गठन करने के लिए, ए

एच.

667

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

यह भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत पंजीकृत होना चाहिए; और

घ. हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति के खिलाफ आरोप का प्रवर्तन बिना आरोप की सूचना के विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है। बिजली बकाया केवल एक असुरक्षित ऋण है।

च. उपयोगिताओं के बिजली बकाया की वसूली के लिए नागरिक और सांविधिक उपाय

ए। 2003 के अधिनियम की धारा 56 के तहत, भुगतान की चूक में आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार चूक करने वाले उपभोक्ता द्वारा किए गए चूक से संबंधित है। विद्युत उपयोगिताएँ 2003 के अधिनियम की धारा 56 (2) में जो प्रावधान किया गया है, उससे अधिक बकाया की वसूली नहीं कर सकती हैं; और

ग

बी। जिस हद तक परिसमापन में कंपनी की बिक्री से प्राप्त धन बिजली बकाया जैसे असुरक्षित ऋणों को चुकाने के लिए अपर्याप्त था, वे कम हो जाएंगे। विद्युत उपयोगिताओं ने बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने के बजाय बकाया राशि को बढ़ाने की अनुमति दी। आपूर्ति की शर्तों का उपयोग समय-बाधित ऋण को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

छ. "जैसा है, जहां है" के आधार पर परिसरों की नीलामी-बिक्री का प्रभाव।

(i) "जैसा है और जो कुछ भी है" जैसी शर्त भौतिक संपत्तियों की एक विशेषता है और उन दावों तक विस्तारित नहीं होती है जो शुल्क, बंधक या भूमि के साथ चलने वाले अन्य बोझ नहीं हैं; और

च

(ii) ईशा मार्बल्स (उपरोक्त) के फैसले को देखते हुए बिजली बकाया का पता लगाने के लिए आवेदकों पर कोई दायित्व नहीं था और जो उन सभी मामलों में जारी है जहां बाद के खरीदारों पर पिछले मालिकों के पिछले बकाया के लिए दायित्व का कोई वैधानिक अधिरोपण नहीं है।

जी.

एफ. विश्लेषण

I. सार्वभौमिक सेवा दायित्व पूर्ण नहीं है।

एच.

668

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

27. विद्युत उपयोगिताओं ने तर्क दिया है कि 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने का शुल्क पूर्ण नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 43 के तहत, एक आवेदक को बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार बनने के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित 'मूल्य' का भुगतान करने के दायित्व को पूरा करना होगा। यह आग्रह किया जाता है कि 'मूल्य' में आवेदन शुल्क के साथ-साथ पिछले मालिक या कब्जाधारक के बकाया बिजली का बकाया भी शामिल है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज का तर्क है कि यदि पिछले मालिक का बकाया है तो वे नए कनेक्शन से इनकार करने या बिजली की आपूर्ति शुरू करने से इनकार करने के हकदार हैं जब तक कि पिछले मालिक द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके विपरीत, नीलामी खरीदारों ने आग्रह किया है कि धारा 43 नीलामी खरीदार द्वारा मांग किए जाने पर वितरण लाइसेंसधारियों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य करती है। यह भी आग्रह किया जाता है कि धारा 43 में 'मूल्य' का अर्थ केवल वह मूल्य हो सकता है जिस पर वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति की जाती है, और इसमें परिसर के पिछले मालिक या कब्जाधारक का बकाया शामिल नहीं हो सकता है। 28. अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों को प्रासंगिक बनाने के लिए, 1910 और 2003 के अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है। 1910 के अधिनियम की धारा 3 के तहत, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस दे सकती है। धारा 3 (2) (च) के आधार पर, अनुसूची में निहित प्रावधान लाइसेंस में शामिल किए गए थे। पहली अनुसूची की धारा 3 (2) (एफ) और खंड VI के साथ पठित धारा 22 के तहत, वितरण लाइसेंसधारियों पर बिजली की आपूर्ति करने का दायित्व था। 1910 के अधिनियम की धारा 22 ने लाइसेंसधारी को आपूर्ति क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को उसी शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया, जिस पर उसी क्षेत्र का कोई अन्य व्यक्ति हकदार था। खंड VI में प्रावधान किया गया है कि लाइसेंसधारी आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा मांग किए जाने के एक महीने के भीतर ऊर्जा की आपूर्ति करेगा।

ग

डी.

ई.

च

29. 2003 के अधिनियम की धारा 43 1910 के अधिनियम की धारा 22 के समान है जिसे बाद के अधिनियम की अनुसूची I के खंड VI के साथ पढ़ा जाता है। 2003 के अधिनियम के भाग VI में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली के वितरण से संबंधित प्रावधान हैं। धारा 2 (17) एक 'वितरण लाइसेंसधारी' को उपभोक्ता को उनके आपूर्ति क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए एक वितरण प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए अधिकृत एक लाइसेंसधारी के रूप में परिभाषित करती है। 2003 के अधिनियम की धारा 43 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी पर ऐसे परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर परिसर में बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य डालती है। इस प्रावधान के तहत वितरण लाइसेंसधारी को आपूर्ति की मांग करने वाले उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में अपना नेटवर्क स्थापित करना होता है।

जी.

एच.

669

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

30. धारा 43 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“43. अनुरोध पर आपूर्ति करने का कर्तव्य-(1) अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार बचत करें।

इस अधिनियम में, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता के आवेदन पर, ऐसी आपूर्ति की आवश्यकता वाले आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, ऐसे परिसरों में बिजली की आपूर्ति करेगा:

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "आवेदन" का अर्थ है आवश्यक शुल्क और अन्य अनुपालनों के भुगतान को दर्शाने वाले दस्तावेजों के साथ, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आवश्यक उचित प्रपत्र में सभी मामलों में पूरा किया गया आवेदन।

ग

(2) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक का यह कर्तव्य होगा कि वह उप-धारा (1) में निर्दिष्ट परिसरों में बिजली की आपूर्ति करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो बिजली संयंत्र या बिजली की लाइन प्रदान करे:

डी.

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति अलग आपूर्ति वाले किसी भी परिसर के लिए बिजली की आपूर्ति की मांग करने या प्राप्त करना जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह उचित आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के लिए लाइसेंसधारी से सहमत न हो जाए।"

ई.

(जोर दिया गया) 31। धारा 43 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी ऐसी आपूर्ति की आवश्यकता वाले आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर मालिक या अधिभोगकर्ता के परिसर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी पर मालिक या कब्जाधारक के परिसर में बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य डालता है। तदनुसार, परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता को वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने का अधिकार है। 22 अधिकार और संबंधित कर्तव्य दोनों कानून द्वारा लगाए गए हैं। बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए परिसर के मालिक या अधिभोगियों को एक आवेदन जमा करना होगा।

च

जी.

32. बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 23

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि परिसरों में बिजली की आपूर्ति करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी का दायित्व इसके बाद शुरू होगा

22 चंदू खमारू बनाम नयन मलिक, (2011) 12 एससीसी 314 23 (2015) 2 एससीसी 438

एच.

670

ऐसे परिसर का मालिक या अधिभोगकर्ता एक पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करता है। धारा 43 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन "आवश्यक शुल्क" के भुगतान और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आवश्यक अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी मामलों में पूरा होना चाहिए। इस प्रकार, धारा 43 के तहत, वितरण लाइसेंसधारी मालिक या अधिभोगकर्ता के परिसर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि मालिक या अधिभोगकर्ता सभी शुल्कों का भुगतान करता है और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करता है। धारा 43 इन शब्दों से शुरू होती है "इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार बचत करें"। इसलिए, धारा 43 का संचालन भी 2003 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा।

ग

33. धारा 45 धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ली जाने वाली कीमत की गणना का तरीका बताती है। इसमें प्रावधान है कि एक वितरण लाइसेंसधारी संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीकों और सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क तय कर सकता है। धारा 46 के तहत, एक वितरण लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति करने के लिए बिजली देने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी बिजली की लाइन या बिजली संयंत्र को प्रदान करने में उचित रूप से किए गए किसी भी खर्च का शुल्क लेने का अधिकार है। धारा 47 वितरण लाइसेंसधारी को धारा 43 के तहत आपूर्ति की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति से उचित सुरक्षा लेने का अधिकार देती है। यह आगे प्रावधान करता है कि वितरण लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करने से इनकार कर सकता है जो प्रतिभूति जमा करने में विफल रहता है। प्रावधान नीचे निकाला गया है:

डी.

ई.

"47. प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति-(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक वितरण लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति से, जिसे धारा 43 के अनुसरण में बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है, उसे उन सभी धन के भुगतान के लिए उचित प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसे देय हो सकते हैं -

च

((क) ऐसे व्यक्ति को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के संबंध में; या

(ख) जहां ऐसे व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए कोई बिजली लाइन या बिजली संयंत्र या बिजली मीटर प्रदान किया जाना है, ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर के प्रावधान के संबंध में,

जी.

और यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में विफल रहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी, यदि वह उचित समझता है, तो ए की आपूर्ति देने से इनकार कर सकता है।

एच.

(जोर दिया गया) 34। धारा 47 इंगित करती है कि एक वितरण लाइसेंसधारी धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है। धारा 48 के तहत, एक वितरण लाइसेंसधारी आवेदक, जिसे धारा 43 के अनुसरण में बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, से (i) धारा 53 के तहत बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार करने की आवश्यकता हो सकती है; और (ii) जिस व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति की जाती है, उसकी लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए वितरण लाइसेंसधारी के किसी भी दायित्व को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी शर्तें। इस प्रकार, यह निहित है कि वितरण लाइसेंसधारी आवेदक को बिजली की आपूर्ति से तब तक इनकार कर सकता है जब तक कि वे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा कानून के लिए प्रासंगिक रूप से लगाए गए ऐसे नियमों और प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं कर लेते।

ग

35. इसके अलावा, धारा 50 राज्य आयोग को अन्य बातों के अलावा बिजली शुल्क की वसूली के लिए एक बिजली आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। विद्युत उपयोगिताओं ने आग्रह किया है कि बिजली की आपूर्ति का शुल्क धारा 50 के तहत निर्दिष्ट बिजली आपूर्ति संहिता के अधीन है। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, एक आवेदक को आवश्यक शुल्क और अन्य अनुपालनों के भुगतान को दिखाने वाले दस्तावेजों के साथ एक पूर्ण आवेदन जमा करना आवश्यक है। विद्युत आपूर्ति संहिता ऐसे अन्य अनुपालनों को निर्धारित कर सकती है जिनका एक आवेदक को धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए पालन करना पड़ता है। इसलिए, धारा 45, 46, 47, 48 और 50 के साथ धारा 43 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति की मांग करने का आवेदक का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अधिकार शुल्क के भुगतान, प्रतिभूति जमा के साथ-साथ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए नियमों और प्रतिबंधों के अधीन है।

डी.

ई.

च

36. वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे नियम और शर्तें निर्धारित कर सकता है जो उसे आवश्यक लगे जब परिसर का कोई मालिक या अधिभोगकर्ता बिजली की आपूर्ति के लिए उससे संपर्क करता है। दो-न्यायाधीशों की पीठ

जी.

इस न्यायालय ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया कि

वितरण लाइसेंसधारी उन नियमों और शर्तों को निर्धारित कर सकता है जिनके अधीन वह आवेदक को बिजली की आपूर्ति करेगा जो मनमाने और अनुचित नहीं हैं।

एच.

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

37. नीलामी खरीदारों ने आग्रह किया है कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए "शुल्क" को धारा 45 द्वारा स्पष्ट रूप से निपटाया जाए। यह भी आग्रह किया गया कि धारा 45 में यह प्रावधान नहीं है कि शुल्क में परिसर के पिछले मालिक या कब्जाधारक का बकाया शामिल होना चाहिए। इसके विपरीत, वितरण लाइसेंसधारियों ने तर्क दिया है कि धारा 43 में प्रयुक्त 'मूल्य' शब्द राज्य आयोग द्वारा निर्धारित बिजली की आपूर्ति के लिए विचार है। यह तर्क दिया गया है कि परिसर के पिछले मालिक या कब्जाधारक का बकाया भी राज्य आयोग द्वारा निर्धारित एक 'मूल्य' है और बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करते समय देय है।

38. "मूल्य", "शुल्क" या "शुल्क" शब्दों को 1910 के अधिनियम या 2003 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। एपी ट्रांस्को बनाम साई रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड, 24 में इस न्यायालय ने कहा कि 2003 के अधिनियम में "शुल्क" शब्द को न तो परिभाषित किया गया है और न ही समझाया गया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधान में किसी विशिष्ट परिभाषा के अभाव में, उपाय करना होगा

ग

सामान्य कानून के तहत या आम बोलचाल में इन अभिव्यक्तियों से जुड़े अर्थ को लिया जाता है।" 25

डी.

39. बीएसईएस लिमिटेड बनाम.टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, 26 दो-न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के संदर्भ में 'शुल्क' की व्याख्या की। यह देखा गया:

"16. अधिनियम में "शुल्क" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। "शुल्क" वाणिज्य का एक समूह है और आम तौर पर यह दरों की एक पुस्तक है। इसका अर्थ होगा शुल्क में निर्दिष्ट ग्राहकों की श्रेणी या श्रेणियों को प्रदान की गई मानक कीमतों या शुल्कों की एक अनुसूची।" 40. धारा 43 (2) का परंतुक आगे एक वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति की मांग करने या प्राप्त करना जारी रखने के लिए एक आवेदक द्वारा देय "मूल्य" को संदर्भित करता है। "मूल्य" का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाना है। यह "मूल्य" राज्य आयोग द्वारा निर्धारित विचार है, कि एक आवेदक बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है।

ई.

च

41. "मूल्य" शब्द का व्यापक अर्थ सभी "शुल्क" और "शुल्क" को शामिल करने के लिए दिया जाना चाहिए जो उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। इसमें समय-समय पर उपयुक्त आयोग द्वारा धारा 45 के तहत निर्धारित 'शुल्क' और 'शुल्क' शामिल हैं जो -

जी.

24 (2011) 11 एससीसी 34 25 (2011) 11 एससीसी 34 26 (2004) 1 एससीसी 195 ए

एच.

673

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

वितरण अनुज्ञातिधारी किसी भी उचित व्यय की वसूली के लिए धारा 46 के तहत अधिरोपित कर सकता है। 'मूल्य' शब्द का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें वैधानिक बकाया भी शामिल है जिसे राज्य आयोग धारा 50 के तहत विनियमों के माध्यम से लागू करने का निर्णय लेता है।

42. इस प्रकार, धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य निरपेक्ष नहीं है, और आवेदन के हिस्से के रूप में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्कों और अनुपालनों के अधीन है।

II. बिजली की आपूर्ति का कर्तव्य उपभोक्ता के संबंध में है।

43. विद्युत उपयोगिताओं का आग्रह है कि बिजली की आपूर्ति का कर्तव्य परिसर के संबंध में है न कि किसी व्यक्ति के लिए। वे 2003 के अधिनियम की धारा 2 (15) और धारा 43 के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा,

यह आग्रह किया गया कि 2003 के अधिनियम की धारा 50 और धारा 181 (2) (x) वितरण लाइसेंसधारक को परिसर में आपूर्ति की जाने वाली बिजली के बकाया के भुगतान के लिए सक्षम बनाती है यदि उसी परिसर के लिए फिर से कनेक्शन या नया कनेक्शन मांगा जाता है। इसके विपरीत, नीलामी खरीदारों ने प्रस्तुत किया है कि बिजली की खपत हमेशा परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा परिसर के भीतर स्थापित उपकरणों और उपकरणों के माध्यम से की जाती है। धारा 2 (15) के साथ-साथ 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा में परिसर का संदर्भ, यह आग्रह किया जाता है, केवल परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता को बिजली की आपूर्ति के लिए एक स्थिति तय करने के लिए है।

ग

डी.

ई.

44. बिजली एक चल वस्तु है क्योंकि इसे किसी भी अन्य चल संपत्ति की तरह संचारित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है और कब्जा किया जा सकता है। 27 कानून की यह स्थिति इस संविधान पीठ द्वारा स्थापित की गई थी।

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड में न्यायालय 28 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ

च

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति माल की बिक्री है। उपभोक्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को भुगतान किया गया शुल्क अनिवार्य रूप से आपूर्ति और उपभोग की गई वस्तुओं के लिए भुगतान की गई कीमत है। एक उपभोक्ता द्वारा बिजली की खपत हमेशा परिसर के भीतर स्थापित उपकरणों या उपकरणों के माध्यम से प्रभावित होती है।

जी.

45. 2003 के अधिनियम की धारा 2 (15) 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

27 बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर बनाम मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, जबलपुर (1969) 1 एससीसी 200

28 (2002) 5 एस. सी. सी. 203, पैरा 20।

एच.

674 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

“(15) “उपभोक्ता” से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे आपूर्ति की जाती है

इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली

और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों से जुड़ा हुआ है, जैसा भी मामला हो;

(जोर दिया गया) 46। 2003 के अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत “उपभोक्ता” की परिभाषा 1910 के अधिनियम में “उपभोक्ता” की परिभाषा के समान है। परिभाषा में दो अंग होते हैं:

ग

((i) कोई भी व्यक्ति जिसे अपने उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है; और

((ii) कोई भी व्यक्ति जिसका परिसर बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को अपने उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की गई हो या नहीं।²⁹

डी.

परिभाषा के पहले अंग को "साधन" के साथ प्रस्तुत किया गया है जबकि दूसरे अंग को "शामिल" के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह परिभाषा परिभाषित अभिव्यक्ति के दायरे की संपूर्ण है। समावेशी भाग का उद्देश्य परिभाषा के प्रारंभिक अंग के दायरे का विस्तार करना है।

ई.

47. जीवेन्द्र नाथ कौल बनाम कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट 30,

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि "कुछ समय के लिए" वाक्यांश के अर्थ का अर्थ इस समय या मौजूदा स्थिति है। दूसरे अंग में परिसर के संदर्भ से संकेत मिलता है कि गारंटीकृत शुल्क या बकाया की मांग तब भी होगी जब मालिक या अधिभोगकर्ता ने कुछ समय के लिए बिजली की खपत बंद कर दी हो, लेकिन परिसर जुड़ा हुआ हो। दूसरा अंग स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता जो परिसर में बिजली प्राप्त करना शुरू कर देता है, वह उपभोक्ता बना रहेगा, भले ही वह कुछ समय के लिए बिजली की खपत करना बंद कर दे, जब तक कि परिसर बिजली प्रणाली से जुड़ा हुआ है। दूसरे अंग में विभिन्न प्रकार की पूर्वानुमेय और व्यावहारिक परिस्थितियाँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि उपभोक्ता ने किसी किरायेदार को परिसर किराए पर दिया हो।

च

जी.

29 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अनीस अहमद, (2013) 8 एससीसी 491 30 (1992) 3 एससीसी 576 ए

एच.

675

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

इस स्थिति में, उपभोक्ता एक उपभोक्ता बना रहता है क्योंकि बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से परिसर कुछ समय के लिए जुड़े हुए हैं, हालांकि उपभोक्ता स्वयं बिजली का उपभोग नहीं कर रहा होगा (खपत किरायेदार द्वारा की जा रही है)। यहां, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता से शुल्क की मांग करता है, भले ही किरायेदार द्वारा बिजली की खपत की जा रही हो। दूसरे अंग के तहत विचार की जाने वाली एक अन्य स्थिति यह है कि उपभोक्ता दुर्घटना या हड़ताल जैसी परिस्थितियों के कारण बिजली का उपभोग करने में असमर्थ है। इस मामले में, जब तक उपभोक्ता का परिसर बिजली प्रणाली से जुड़ा हुआ है, उन्हें वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित मांग शुल्क और न्यूनतम गारंटी शुल्क का भुगतान करना होगा।

ग

48. हम विद्युत उपयोगिताओं के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि धारा 2 (15) का दूसरा अंग परिसर में बिजली की आपूर्ति को दर्शाता है, चाहे मालिक या अधिभोगकर्ता में कोई बदलाव हो। 2003 का अधिनियम धारा 2 (51) के तहत 'परिसर' की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है। परिभाषा के अनुसार, परिसर में भूमि, भवन या संरचना शामिल है। दूसरा अंग केवल यह कहने तक जाता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष भूमि, भवन या संरचना पर बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता बना रहेगा, भले ही वे बिजली की खपत नहीं कर रहे हों, जब तक कि बिजली कनेक्शन मौजूद है। दूसरे अंग में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'परिसर' उस स्थान की पहचान करती है जहाँ बिजली की आपूर्ति की जानी है।

डी.

ई.

49. 2003 के अधिनियम के तहत कुछ अन्य परिभाषाओं का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा जो इस बात पर जोर देती हैं कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता के संबंध में है:

"2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

च

(17) "वितरण अनुज्ञापिधारी" से बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए अधिकृत अनुज्ञापिधारी अभिप्रेत है।

अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ता;

जी.

(19) "वितरण प्रणाली" का अर्थ है संचरण लाइनों पर वितरण बिंदुओं या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन और कनेक्शन के बिंदु के बीच तारों और संबंधित सुविधाओं की प्रणाली।

उपभोक्ताओं की स्थापना के लिए;

एच.

676

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

(61) "'सर्विस लाइन' से कोई भी विद्युत आपूर्ति लाइन अभिप्रेत है जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है या जिसका इरादा है -

(क) वितरण मुख्य से या वितरण लाइसेंसधारी के परिसर से तुरंत किसी एकल उपभोक्ता को; या (ख) वितरण मुख्य से उसी परिसर में या वितरण मुख्य के उसी बिंदु से आपूर्ति किए गए आस-पास के परिसरों में उपभोक्ताओं के समूह को वितरण मुख्य से;

(70) "बिजली के संबंध में 'आपूर्ति' का अर्थ है

किसी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता को बिजली; "

ग

(जोर दिया गया) 50। 'आपूर्ति' की परिभाषा में विशेष रूप से कहा गया है कि आपूर्ति का अर्थ है उपभोक्ता को बिजली की बिक्री। उक्त परिभाषा से यह संकेत नहीं मिलता है कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता के परिसर के बराबर है। 2003 के अधिनियम की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को होती है न कि परिसर को।

डी.

51. 2003 के अधिनियम की धारा 43 एक वितरण लाइसेंसधारी को "किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता के आवेदन पर" बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रावधान के तहत, बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार परिसर के मालिक या अधिभोगियों के पास निहित है। निश्चित रूप से, ऐसे मालिक या अधिभोगकर्ता का अर्थ धारा 2 (15) के तहत उपभोक्ता है। जैसा कि आयोजित किया गया है

ई.

बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम (ऊपर),

बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य केवल परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर लागू होता है। इसलिए, "परिसर" शब्द को पूर्ववर्ती भाग, अर्थात् परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता के संबंध में संदर्भित और समझा जाना चाहिए।

च

52. धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य केवल परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता के संबंध में है, न कि परिसर के संबंध में, क्योंकि यह मालिक या अधिभोगकर्ता है जिसे अपने उपयोग या व्यवसाय के तहत परिसर के लिए बिजली की "मांग" करने का वैधानिक अधिकार है। इसके अलावा, यह आवेदक है जिसे अपने परिसर में बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार बनने के लिए 2003 के अधिनियम के तहत निर्धारित सभी वैधानिक शर्तों को पूरा करना होता है। आवेदक को आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा और बिजली की आपूर्ति के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

जी.

एच.

677

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

53. यह सच है कि 2003 के अधिनियम की धारा 43 और 44 परिसरों में बिजली की आपूर्ति के बारे में बात करती है। हालाँकि, इस तरह के वाक्यांशों का उपयोग बिजली की आपूर्ति के व्यावहारिक विचार से होता है। अन्य वस्तुओं के विपरीत, एक वितरण लाइसेंसधारी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि उपभोक्ता बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने कारखाने या गोदाम में आए। वितरण लाइसेंसधारी को अपने परिसर में बिजली संचारित करने और सीधे उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए बिजली की लाइनें और ट्रांसफॉर्मर जैसे विशेष बुनियादी ढांचे को अनिवार्य रूप से स्थापित करना होता है। एक आवेदन पर, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है। नतीजतन, जिस स्थान पर बिजली की आपूर्ति की जानी है, उसकी पहचान करना आवश्यक है। इस प्रकार, धारा 43 और 44 उपभोक्ता के परिसर को बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से स्थिति निर्धारित करने के लिए संदर्भित करती है।

ग

54. धारा 56 में प्रावधान है कि बिजली की आपूर्ति के संबंध में बिजली के लिए शुल्क का भुगतान करना उपभोक्ता का दायित्व है। धारा 56 के तहत बिजली के लिए शुल्क का भुगतान करने का कर्तव्य एक व्यक्ति, यानी उपभोक्ता पर है। इसके अलावा, धारा 56 (2) में विशेष रूप से "किसी भी उपभोक्ता से कोई राशि देय नहीं" अभिव्यक्ति शामिल है। धारा 126 में "ऐसे व्यक्ति या इस तरह के उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क" शब्दों का भी उपयोग किया गया है। इस प्रकार, 2003 के अधिनियम की समग्र योजना यह स्पष्ट करती है कि केवल एक उपभोक्ता को बिजली बकाया या शुल्क के भुगतान में चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

डी.

ई.

55. 2003 के अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न नियम और विनियम बनाए हैं। सरकार ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 31 को अधिसूचित किया, जिसमें बिजली के उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित किया गया है। नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और वितरण लाइसेंसधारियों के दायित्वों का विवरण देते हैं; नए कनेक्शन जारी करना; मीटरिंग व्यवस्था; बिलिंग और भुगतान; डिस्कनेक्शन और पुनः कनेक्शन; शिकायत निवारण तंत्र, अन्य के बीच। नियम एक 'आवेदक' को किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता के रूप में परिभाषित करते हैं जो बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारी के साथ आवेदन पत्र दाखिल करता है। नियम 'आपूर्ति बिंदु' को उस बिंदु के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसा कि राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिस पर एक उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति की जाती है। नियम यह स्पष्ट करते हैं कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की जाती है।

च

जी.

56. इस प्रकार, यह हमेशा उपभोक्ता होता है जिसे बिजली की आपूर्ति की जाती है और उसे बिजली की आपूर्ति के लिए बकाया या शुल्क के भुगतान में चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

31 "नियम "

एच.

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

बिजली। बलपूर्वक, परिसर को चूककर्ता नहीं माना जा सकता है और उपभोक्ता के परिसर में कोई बकाया नहीं लगाया जा सकता है।

III. क्या बाद के मालिक द्वारा माँगा गया बिजली कनेक्शन एक पुनः कनेक्शन या नया कनेक्शन है

57. हमारे सामने एक और मुद्दा, जैसा कि वकील द्वारा तर्क दिया गया है, यह है कि क्या बाद के मालिक द्वारा मांगा गया कनेक्शन एक पुनर्संयोजन या नए कनेक्शन का गठन करता है। इशमार्बल्स (ऊपर) में, बिजली बोर्ड ने 1910 के अधिनियम की धारा 24 के तहत अपनी शक्ति के अनुसार पूर्व मालिक को आपूर्ति की गई बिजली काट दी थी। बिजली बोर्ड ने नीलामी खरीदार पर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में पूर्व मालिक द्वारा बकाया का भुगतान करने पर जोर दिया। बोर्ड ने आपूर्ति की किसी भी वैधानिक शर्तों पर भरोसा नहीं किया। इस न्यायालय ने कहा कि कानून, जैसा कि तब था, इस तरह के दायित्व को लागू करने के लिए अपर्याप्त था। न्यायालय ने आगे कहा कि बाद के खरीदार द्वारा मांगे गए संबंध को पुनर्संयोजन माना जाना चाहिए:

ग

"49. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि खरीदारों ने नए कनेक्शन के रूप में बिजली कनेक्शन की मांग की थी, लेकिन इसे नया कनेक्शन नहीं माना जा सकता है। यह केवल एक पुनर्संयोजन है क्योंकि परिसर को पहले से ही विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जा चुकी थी। इस तरह की आपूर्ति इस वजह से काट दी गई थी कि

डी.

उपभोक्ता की चूक। उस उपभोक्ता ने बकाये का भुगतान करने के लिए खुद को बोर्ड से बांधा था। उन्होंने अधिनियम और नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमति व्यक्त की, जिसमें बकाया राशि का भुगतान भी शामिल है।"

ई.

(जोर दिया गया) 58। इस अदालत ने आगे कहा कि एक वितरण लाइसेंसधारी नीलामी-खरीदार को उसी परिसर के लिए बिजली आपूर्ति के पुनः कनेक्शन की मांग करते समय उत्तरदायी नहीं बना सकता है। न्यायालय के अनुसार, यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं था कि "प्रत्येक के परिवर्तन के साथ

च

स्वामित्व के लिए नए कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए [जो] सही दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ऐसी स्थिति बिजली बोर्ड की बकाया राशि की वसूली नहीं करने में निष्क्रियता के कारण आती है या जब वे देय हो जाते हैं या खुद को पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं करते हैं।

जी.

जमा।" हालाँकि, इस न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कानून ऐसा निर्धारित करता है तो नीलामी-खरीदारों पर पिछले मालिकों की देनदारी तय की जा सकती है। 59. गुजरात इंस (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक अन्य तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संपत्तियों की नीलामी-खरीदारों द्वारा मांगा गया संबंध ए

एच.

679

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

यह एक नया संबंध बनाएगा। न्यायालय ने कहा कि एक नए संबंध के मामले में, नीलामी खरीदारों को किसी विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में पिछले मालिकों द्वारा किए गए बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह देखा गया:

"3. हमारी राय में, वर्तमान दो मामले नए संबंध के मामले हैं। उत्तरदाताओं (नीलामी-खरीदारों) के विद्वान वकील ने कहा है कि उन्होंने नए कनेक्शन लिए हैं और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि उनके कनेक्शन को उस तारीख को दिए गए नए कनेक्शन के रूप में माना जाता है जिस दिन परिसर में बिजली की आपूर्ति बहाल की गई थी। हम स्पष्ट रूप से

राय है कि एक नए कनेक्शन के मामले में, हालांकि परिसर समान हैं, नीलामी-खरीदारों को परिसर में बिजली आपूर्ति के संबंध में पिछले मालिकों द्वारा किए गए बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है।

ग

ध्यान दें। यद्यपि हम ईशा मार्बल्स मामले [(1995) 2 एस. सी. सी. 648] में निर्धारित कानून के व्यापक प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कुछ योग्यता पाते हैं, हम सोचते हैं कि वर्तमान इस तरह के अभ्यास का मामला नहीं है। हम याचिका को एक उपयुक्त मामले में विचार के लिए खुला छोड़ते हैं।" (जोर दिया गया) 60। ईशा मार्बल्स (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि उसी परिसर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक आवेदन को पुनः कनेक्शन माना जाना चाहिए। इस न्यायालय ने 1910 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए इस धारणा पर अपना तर्क दिया कि बिजली की आपूर्ति परिसर के संबंध में है न कि उपभोक्ता के संबंध में। हालाँकि, 2003 के अधिनियम ने वैधानिक रूप से इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता के संबंध में है। यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि जब परिसर का कोई नया मालिक या अधिभोगकर्ता 2003 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करता है, तो यह एक नए कनेक्शन का गठन करेगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि जिस परिसर के लिए बिजली मांगी गई है, उसे पहले बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। बिजली की आपूर्ति के लिए एक आवेदन को केवल तभी पुनर्संयोजन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब परिसर का वही मालिक या अधिभोगकर्ता, जो पहले से ही एक उपभोक्ता था, बिजली की आपूर्ति काट दिए जाने की स्थिति में उसी परिसर के संबंध में बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करता है।

डी.

ई.

च

जी.

61. हमें इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि 2003 का अधिनियम उपभोक्ता और परिसर के बीच तालमेल पर विचार करता है। 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत,

एच.

680

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

परिसर का मालिक या अधिभोगकर्ता विशेष परिसर के लिए बिजली की आपूर्ति की मांग कर सकता है। जब बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो मालिक या अधिभोगकर्ता केवल उन विशेष परिसरों के संबंध में उपभोक्ता बन जाता है जिनके लिए बिजली मांगी जाती है और प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक आवासीय परिसर में एक अपार्टमेंट का मालिक व्यक्ति ऐसे अपार्टमेंट में बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करता है, तो वे केवल उस अपार्टमेंट के संबंध में उपभोक्ता बन जाते हैं जिसके लिए आवेदन किया जाता है और जिसके लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक और अपार्टमेंट हो सकता है जिसमें पहले से ही बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन उन्हें दूसरे अपार्टमेंट के संबंध में एक अलग उपभोक्ता माना जाएगा। एक आवेदन को 'पुनः कनेक्शन' के रूप में माने जाने के लिए, आवेदक को उसी परिसर के संबंध में बिजली की आपूर्ति की मांग करनी होगी जिसके लिए पहले से ही बिजली प्रदान की गई थी। भले ही उपभोक्ता एक ही हो, लेकिन परिसर अलग-अलग हो, इसे एक नया कनेक्शन माना जाएगा, न कि पुनः कनेक्शन।

ग

62. गुजरात इन में। (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नीलामी-खरीदार द्वारा बिजली के लिए एक आवेदन नए कनेक्शन का गठन करेगा, भले ही परिसर समान हों। तर्क इस सही धारणा पर आधारित है कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता के संबंध में है, न कि परिसर के संबंध में। इसलिए, भले ही वह परिसर वही हो जिसमें पहले से ही बिजली की आपूर्ति की जा चुकी थी, लेकिन उस स्थिति में इसे एक नया कनेक्शन माना जाएगा जहां एक अलग आवेदक, उस मामले में एक नीलामी-खरीदार, बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करता है।

डी.

ई.

IV. विद्युत बोर्डों/राज्य आयोगों की विनियामक शक्ति

63. विद्युत उपयोगिताओं ने प्रस्तुत किया है कि: (i) 1948 के अधिनियम की धारा 49 ने बोर्ड को ऐसे नियमों और शर्तों पर बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार दिया जो वह उचित समझता है; (ii) 1948 के अधिनियम की धारा 79 में "विनियमन" वाक्यांश का एक व्यापक निहितार्थ है जो राज्य आयोग को बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक सब कुछ करने की अनुमति देता है; (iii) 2003 के अधिनियम की धारा 181 (2) (x) के साथ पठित धारा 50 के तहत अधिसूचित बिजली आपूर्ति संहिता परिसरों में बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करती है; और (iv) आपूर्ति की शर्तें जो पिछले उपभोक्ता के बकाया भुगतान के लिए प्रदान करती हैं, उनका 2003 के अधिनियम की योजना और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ स्पष्ट संबंध है।

च

जी.

64. दूसरी ओर से नीलामी खरीदारों ने आग्रह किया है कि: (i) 1910 अधिनियम, 1948 अधिनियम और 2003 अधिनियम के प्रावधानों में ए नहीं है।

एच.

681

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

विद्युत बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, वितरण लाइसेंसधारी को परिसर के नए मालिक या अधिभोगियों से पिछले उपभोक्ता की बिजली के बकाया की वसूली करने का अधिकार; और (ii) 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित आपूर्ति की शर्तों में विनियमों की प्रकृति नहीं है और वे वैधानिक नहीं हैं।

65. 1910 के अधिनियम की धारा 2 (एच) ने "लाइसेंसधारी" को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भाग 2 के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि एक वितरण लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा 21 (2) लाइसेंसधारी को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ उपभोक्ता के साथ अपने संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से शर्तें बनाने का अधिकार देती है।

ग

66. 1910 के अधिनियम में राज्य विद्युत बोर्ड को "लाइसेंसधारी" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। 1948 के अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि बोर्ड के पास, पूरे राज्य के संबंध में, 1910 के अधिनियम के तहत एक लाइसेंसधारी की सभी शक्तियां और दायित्व होंगे। पहले परंतुक में निर्दिष्ट किया गया था कि 1910 के अधिनियम के कुछ प्रावधान जो किसी लाइसेंसधारी के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित हैं, बोर्ड पर लागू नहीं होंगे। राज्य में अपने निर्णय में

डी.

उत्तर प्रदेश बनाम हिंदुस्तान एल्यूमीनियम निगम **32** यह न्यायालय

1948 के अधिनियम की धारा 26 और 1910 के अधिनियम की धारा 22 के बीच परस्पर संबंध का विश्लेषण किया गया। अदालत ने कहा कि 1910 के अधिनियम की धारा 22 के तहत आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा की आपूर्ति करने का दायित्व बोर्ड को नहीं दिया गया है। यद्यपि 1910 के अधिनियम की अनुसूची का खंड VI भी लाइसेंसधारक को मांग पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए अनिवार्य करता है, दूसरा परंतुक निर्दिष्ट करता है कि उक्त खंड बोर्ड पर केवल तभी लागू होता है जब बोर्ड द्वारा वितरण मुख्य निर्धारित किया गया हो और उनमें से किसी के माध्यम से आपूर्ति शुरू हो गई हो।

ई.

67. 1910 के अधिनियम की धारा 21 के तहत, आपूर्ति लाइसेंसधारी ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ शर्तें निर्धारित कीं। इसी तरह, बोर्ड 1948 के अधिनियम की धारा 26 के आधार पर 1910 के अधिनियम की धारा 21 के तहत भी शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।

च

68. 1948 के अधिनियम की धारा 49 इस प्रकार है:

जी.

"49. बोर्ड द्वारा बिजली की बिक्री के लिए प्रावधान

लाइसेंसधारियों के अलावा अन्य व्यक्ति।- **(1)** इस अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रावधान किया गया है, तो बोर्ड

किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति कर सकता है जो लाइसेंसधारी नहीं है

32 (1979) 3 एससीसी 229

एच.

682 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

ऐसे नियमों और शर्तों पर जो बोर्ड उचित समझता है और

ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए एक समान शुल्क तय कर सकते हैं।” ***

(1948 के अधिनियम के तहत, बिजली बोर्डों को धारा 79 (जे) के साथ पठित धारा 49 के तहत आपूर्ति के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। बोर्ड को ऐसे नियम और शर्तें तय करने का अधिकार दिया गया था जो वह किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए उचित समझता है जो लाइसेंसधारी नहीं है। धारा 79 ने बोर्ड को धारा 49 के तहत लाइसेंसधारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के लिए विनियम बनाने की अनुमति दी:

ग

“79. विनियम बनाने की शक्ति।- बोर्ड अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र में, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत विनियम बनाएँ, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(जे) धारा 49 के तहत लाइसेंसधारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

धारा 79 के खंड (जे) ने बोर्ड को उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले विनियम बनाने का अधिकार दिया। धारा 79 ए के अनुसार, बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना था। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा धारा 79 और धारा 79 ए के साथ पठित धारा 49 के तहत तैयार की गई आपूर्ति की शर्तें वैधानिक प्रकृति की थीं और उपभोक्ताओं पर बाध्यकारी होंगी। 69. यह कानून में एक सुसंगत स्थिति रही है कि लाइसेंसधारियों या बोर्डों द्वारा निर्धारित आपूर्ति की शर्तों का एक वैधानिक चरित्र है। 33 जगदम्बा पेपर इंडस्ट्रीज (पी) मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

ई.

च

लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, 34 एक चुनौती से निपट रहा था।

विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं के साथ समझौते के तहत बोर्ड द्वारा सुरक्षा में एकतरफा वृद्धि करना। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बोर्ड को 1948 के अधिनियम की धारा 49 (1) के तहत उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनके आधार पर आपूर्ति की जाती है।

जी.

बनाने के लिए। इसी तरह, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम परमेश्वर

33 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बस्सी कोल्ड स्टोरेज, खरार और अन्य, 1994 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 124

34 (1983) 4 एससीसी 508 ए

एच.

683

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

कुमार अग्रवाल 35, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जिन नियमों और शर्तों पर बोर्ड उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करता है, उनका एक वैधानिक चरित्र है।

70. फेरो मिश्र धातु निगम में लिमिटेड बनाम ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड 36

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 1948 के अधिनियम की धारा 49 की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि धारा 49 के तहत अधिसूचित नियम और शर्तें उस उद्देश्य और उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था। वहाँ, न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में प्रतिभूति जमा निर्धारित करने के लिए बोर्ड के अधिकार को बरकरार रखा:

“102. [.....] धारा 79 (जे) के साथ पठित धारा 49 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत उपभोक्ता केवल हकदार है और बोर्ड का दायित्व है कि वह विनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों पर उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति करे। यदि, इसलिए, नियमों ने एक प्रतिभूति जमा निर्धारित किया है जिसका पालन करना होगा। विद्युत अधिनियम की अनुसूची के खंड VI के तहत यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बोर्ड द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मांग परंतुक (ए) के तहत की जानी है, जब एक लिखित अनुबंध को पर्याप्त प्रतिभूति के साथ विधिवत निष्पादित किया जाता है। यह, ऊपर बताए गए नियमों के साथ, कानूनी मंजूरी के साथ इसे पहनने के लिए पर्याप्त हो सकता है।”

ग

डी.

71. हैदराबाद वनस्पति (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को "आपूर्ति के नियमों और शर्तों" की शर्त 39 की वैधता पर निर्णय लेना था, जिसमें दंडात्मक नुकसान का आकलन करने और उसे वसूलने के लिए एक न्यायिक तंत्र निर्धारित किया गया था। इस न्यायालय ने 1910 के अधिनियम और 1948 के अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि बाद के अधिनियम की धारा 49 के तहत अधिसूचित नियम और शर्तें वैध थीं और उनके पास वैधानिक बल था। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे निकाला गया है: “20. हम पहले ही देख चुके हैं कि आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 बोर्ड को ऐसे नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देती है जो वह लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए उचित समझता है। यह अनुभाग बोर्ड को ऐसी आपूर्ति के लिए समान शुल्क निर्धारित करने का भी अधिकार देता है। धारा 79 (जे) के तहत बोर्ड इसके लिए विनियमन बना सकता था, लेकिन माना जा सकता है कि बोर्ड द्वारा अब तक कोई विनियमन नहीं बनाया गया है। आपूर्ति के नियम और शर्तों को बी. पी. एम. संख्या 690 दिनांक 17-9-1975 में अधिसूचित किया गया था।

ई.

च

जी.

35 (1996) 4 एस. सी. सी. 686

36 1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 136

एच.

684

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। वे 20-10-1975 से लागू हुए। बोर्ड से बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए इन्हें लागू किया गया था।

अधिनियम की धारा में बोर्ड को व्यक्तिगत उपभोक्ता के साथ अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत अनुबंध के अभाव में भी, बोर्ड द्वारा अधिसूचित आपूर्ति के नियम और शर्तें उपभोक्ता पर लागू होंगी और वह उनसे बाध्य होगा। संभवतः उपभोक्ता द्वारा किसी भी संभावित अनुरोध से बचने के लिए कि उसे आपूर्ति के नियमों और शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, प्रत्येक उपभोक्ता के साथ लिखित समझौते किए जाते हैं। यह शर्तों को विशुद्ध रूप से संविदात्मक नहीं बनाएगा। बोर्ड एक वैधानिक कर्तव्य के निष्पादन में एक वैधानिक शक्ति के प्रयोग में बनाए गए कुछ विशिष्ट नियमों और शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति करता है। निस्संदेह नियम और शर्तें वैधानिक हैं और उन्हें विशुद्ध रूप से संविदात्मक नहीं कहा जा सकता है।"

ग

डी.

(जोर दिया गया) 72। उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि आपूर्ति की शर्तें अधिसूचित की गई थीं: पहला, 1910 अधिनियम की धारा 21 के तहत आपूर्ति लाइसेंसधारी और बिजली बोर्डों द्वारा; और दूसरा, 1948 अधिनियम की धारा 49 के तहत बिजली बोर्डों द्वारा। हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय इस तथ्य का उदाहरण है कि अदालतों ने बिजली बोर्डों द्वारा अधिसूचित आपूर्ति की शर्तों की वैधता को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय रूप से, हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय में कहा गया है कि 1948 अधिनियम की धारा 49 के तहत नियम और शर्तें तैयार करने की बोर्ड की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 79 के तहत सन्निहित विनियम बनाने की शक्ति से अलग है। इसलिए, धारा 49 के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित आपूर्ति के नियम और शर्तें, हालांकि अधीनस्थ विधान की प्रकृति में, 1948 अधिनियम की धारा 79 ए के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता नहीं थी। उस मामले में, यह भी माना गया था कि वैधानिक शर्तों को केवल तभी अमान्य किया जा सकता है जब वे 1948 के अधिनियम या संविधान के किसी भी प्रावधान के साथ संघर्ष में हों।

ई.

च

जी.

73. नीलामी-खरीदारों ने इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी **37** का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि आपूर्ति की शर्तें वैधानिक नहीं हैं, बल्कि बिजली के बीच अनुबंध का एक हिस्सा हैं।

37 (2000) 3 एससीसी 379 ए

एच.

685

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

बोर्ड और उपभोक्ता। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इन संविदात्मक शर्तों को बोर्ड द्वारा परिसर के नए मालिक या अधिभोगकर्ता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (उपरोक्त) में, दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकार 1948 अधिनियम की धारा 43 और 43-ए के तहत किए गए बिजली खरीद समझौते की शर्तों में बदलाव कर सकती है। धारा 43 ने बोर्ड को बिजली की खरीद या बिक्री के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करने का अधिकार दिया। धारा 43-ए में प्रावधान किया गया है कि एक उत्पादक कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री के लिए शुल्क केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित संचालन और संयंत्र-भार कारक के संबंध में मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इन प्रावधानों के आलोक में, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 43 और 43-ए के तहत प्रदत्त सक्षम शक्ति का प्रयोग करते हुए एक उत्पादन कंपनी और बिजली बोर्ड के बीच किए गए समझौते का प्रत्येक प्रावधान अनुबंध की संपूर्णता को वैधानिक नहीं बनाता है। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

ग

“11. [.....] केवल इसलिए कि एक अनुबंध एक कानून द्वारा प्रदत्त एक सक्षम शक्ति के प्रयोग में किया जाता है जो स्वयं अनुबंध को एक वैधानिक अनुबंध नहीं बना सकता है। अगर एक में प्रवेश करें

डी.

निर्धारित नियमों और शर्तों वाला अनुबंध कानून के तहत आवश्यक है तो वह अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध बन जाता है। यदि किसी अनुबंध में कुछ नियम और शर्तें शामिल हैं जो वैधानिक हैं तो उक्त अनुबंध

ई.

उस हद तक वैधानिक है। एक अनुबंध में कुछ अन्य नियम और शर्तें हो सकती हैं जो एक वैधानिक चरित्र के नहीं हो सकते हैं और जिन्हें पार्टियों के बीच आपसी समझौते के परिणामस्वरूप इसमें शामिल किया गया है। इसलिए, पी. पी. ए. हो सकते हैं

उन्हें केवल इस हद तक वैधानिक माना जाता है कि उनमें धारा 43-ए (2) की शुल्क निर्धारण और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। उद्धाटन और

च

एस्करो खाते या एस्करो समझौते को बनाए रखना वैधानिक आवश्यकताएं नहीं हैं और इसलिए, केवल इसलिए कि पी. पी. ए. एस्करो खातों को बनाए रखने पर विचार करते हैं कि दायित्व को वैधानिक नहीं माना जा सकता है।”

जी.

(जोर दिया गया) 74। हमारी राय है कि इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय का तर्क वास्तव में इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज के तर्कों का समर्थन करता है। जैसा कि हैदराबाद वनस्पति (ऊपर) से पता चलता है,

एच.

686

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

बोर्ड द्वारा अधिनियमित आपूर्ति की शर्तों का एक वैधानिक चरित्र है। इसलिए, 1948 के अधिनियम की धारा 49 के तहत अधिनियमित किसी भी शर्त, विशेष रूप से बिजली आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने के लिए नए मालिक की आवश्यकता, का एक वैधानिक चरित्र होगा। जब ऐसी शर्त को किसी अनुबंध के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो ऐसा अनुबंध भी एक वैधानिक चरित्र प्राप्त करता है और उसमें निहित दायित्व एक

वैधानिक दायित्व बन जाता है, जिसे उपयोगिताओं द्वारा तीसरे पक्ष के खिलाफ लागू किया जा सकता है, जिसमें विचाराधीन परिसर के नए मालिक भी शामिल हैं।

75. अगला सवाल जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या विद्युत उपयोगिताएँ नए मालिक से पिछले मालिक के बिजली बकाया की भरपाई के लिए एक शर्त लागू कर सकती हैं। 1948 के अधिनियम के तहत, बोर्ड धारा 79 (जे) के साथ पठित धारा 49 के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तें लागू कर सकता है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर कहा है कि 'विनियमन' शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए जो संगठित कार्यान्वयन, विकास और व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक हर चीज के प्रदर्शन की अनुमति देती है। दीपक थिएटर बनाम पंजाब राज्य 38 के मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विनियमन की शक्ति का तात्पर्य व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक ऐसे सभी उचित और उचित नियमों को निर्धारित करने और लागू करने की शक्ति से है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

ग

डी.

“3. यह तय कानून है कि अधिनियम के तहत सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए वैध रूप से बनाए गए नियमों को कानून का हिस्सा माना जाए। नियमों के तहत जारी किए गए लाइसेंस की शर्तें कानून का एक अभिन्न हिस्सा हैं। सवाल यह उठता है कि क्या विनियमन शब्द में प्रवेश की दरें तय करने और सीटों के वर्गीकरण की शक्ति शामिल होगी। विनियमित करने की शक्ति में लाइसेंस देने या लाइसेंस से इनकार करने या लाइसेंस लेने की आवश्यकता की शक्ति शामिल हो सकती है और इसमें कर लगाने या कराधान से छूट देने की शक्ति भी शामिल हो सकती है, लेकिन नियम बनाने की शक्ति में राजस्व के लिए कर लगाने की शक्ति नहीं हो सकती है जब तक कि इसमें कोई वैध कानून न हो।

ई.

च

की ओर से। इसलिए, किसी विशेष व्यवसाय या आह्वान को विनियमित करने की शक्ति का तात्पर्य ऐसे सभी उचित और उचित नियमों और विनियमों को निर्धारित करने और लागू करने की शक्ति से है जो व्यवसाय को उचित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं। इसमें उचित नियम, विनियम या शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है।

जी.

38 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 684 ए

एच.

687

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

जिसके अधीन व्यवसाय की अनुमति दी जा सकती है या

आयोजित किया गया। धारा 5, धारा 9, नियम 4 और शर्त 4-ए का एक संयुक्त पठन, इसलिए, लाइसेंस प्राधिकरण को सीटों को वर्गीकृत करने और सिनेमा थिएटर में प्रवेश की दरों को निर्धारित करने की शक्ति देता है।”

(जोर दिया गया)

76. के. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य 39 में तीन न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि "विनियमन" शब्द का कोई कठोर या लचीला अर्थ नहीं है। इस न्यायालय ने कहा कि "विनियमन की शक्ति अपने साथ विनियमन के अधीन चीज़ पर पूरी शक्ति रखती है और प्रतिबंधात्मक शब्दों के अभाव में, शक्ति को पूरे विषय पर पूर्ण माना जाना चाहिए।" वी. एस. राइस एंड ऑयल मिल्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 40 के मामले में संविधान पीठ ने यह भी कहा कि "विनियमन" शब्द का व्यापक महत्व है।

ग

77. उपरोक्त विश्लेषण को 1948 के अधिनियम की धारा 79 (जे) के साथ पठित धारा 49 की व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसने बोर्ड को ऐसे नियम और शर्तों को लागू करने का अधिकार दिया है जो बोर्ड उचित समझता है। बोर्ड की यह शक्ति बिजली की आपूर्ति के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में नए मालिक से पूर्व मालिक के बकाया की वसूली के लिए प्रावधान करने वाली शर्तों को लागू करने के लिए विस्तारित होगी। इसके अलावा, इस न्यायालय ने बिजली की आपूर्ति के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में नए मालिक से पिछले मालिक के बकाया की भरपाई के प्रावधान वाली आपूर्ति की शर्तों को लगातार बरकरार रखा है।

डी.

ई.

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ।

हनुमान राइस मिल्स, धनौरी 41, की स्थिति का सारांश देते हुए

पैरामाउंट पॉलिमर (ऊपर) और पश्चिमांचल में निर्धारित कानून

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उपरोक्त) ने कहा कि आपूर्तिकर्ता संपत्ति के खरीदार से पिछले मालिक या कब्जाधारक के बिजली बकाया की वसूली कर सकता है यदि वैधानिक नियम या आपूर्ति के नियम और शर्तें जो चरित्र में वैधानिक हैं, उन्हें अधिकृत करती हैं:

च

"12. अतः स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क नहीं है। इसलिए सामान्य कानून में, किसी परिसर के हस्तांतरणकर्ता को पिछले मालिक/अधिभोगकर्ता के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

जी.

39 (1985) 2 एससीसी 116 40 (1964) 7 एससीआर 456 41 (2010) 9 एससीसी 145

एच.

688 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

(ii) जहां वैधानिक नियम या आपूर्ति के नियम और शर्तें जो वैधानिक हैं, बिजली के आपूर्तिकर्ता को बिजली के पुनर्संयोजन या नए कनेक्शन का दावा करने वाली संपत्ति के खरीदार से मांग करने के लिए अधिकृत करते हैं, ऐसे परिसरों में बिजली की आपूर्ति के संबंध में पिछले मालिक/अधिभोगकर्ता द्वारा देय बकाया, आपूर्तिकर्ता एक खरीदार से बकाया वसूल कर सकता है।"

(जोर दिया गया) 78। पैरामाउंट पॉलिमर (ऊपर) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को आपूर्ति के नियमों और शर्तों के खंड 21-ए की वैधता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि किसी खरीदार को परिसर के संबंध में कोई नया कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि खरीदार पिछली उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करता। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 के तहत आपूर्ति के नियमों और शर्तों में खंड 21-ए सम्मिलित करना विद्युत बोर्ड की शक्ति के भीतर है:

ग

डी.

“15. [...] आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 के तहत, लाइसेंसधारी या बल्कि, विद्युत बोर्ड, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के नियम और शर्तें निर्धारित करने का हकदार है। इसके लिए उपलब्ध शक्ति के आलोक में, आपूर्ति की धारा 79 (जे) के संदर्भ में भी

अधिनियम, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के नियमों और शर्तों में खंड 21-ए का सम्मिलन अपीलार्थी की शक्ति से परे है।”

ई.

(जोर दिया गया) 79। जहां तक 2003 के अधिनियम का संबंध है, विद्युत उपयोगिताओं का कहना है कि धारा 181 (2) (x) के साथ पठित धारा 50 राज्य आयोग को बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली शर्तों को तैयार करने के लिए अधिकृत करती है, जिससे बिजली शुल्क की वसूली की जा सके, जिसमें नए मालिक से पिछले मालिक की बिजली बकाया भी शामिल है। नीलामी खरीदार स्वीकार करते हैं कि 2003 के अधिनियम की धारा 50 संपूर्ण है, लेकिन तर्क देते हैं कि यह राज्य आयोग को पिछले मालिक के बिजली बकाया की वसूली के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम नहीं बनाता है। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण का व्यापक विश्लेषण करने के लिए, 2003 के अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

च

जी.

80. 2003 के अधिनियम की धारा 2 (24) "विद्युत आपूर्ति संहिता" को धारा 50 के तहत निर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संहिता के रूप में परिभाषित करती है। धारा 50 इस प्रकार है:

एच.

689

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

“50. विद्युत आपूर्ति संहिता-राज्य आयोग

बिजली शुल्क की वसूली, बिजली शुल्क के बिलिंग के लिए अंतराल प्रदान करने के लिए एक बिजली आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करेगा,

भुगतान न करने पर बिजली की आपूर्ति काटना, बिजली की आपूर्ति बहाल करना, इसके लिए उपाय

बिजली संयंत्र या बिजली की लाइन या मीटर में छेड़छाड़, परेशानी या क्षति को रोकना, वितरण लाइसेंसधारी या उसकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रवेश या आपूर्ति को काटना और मीटर को हटाना, बिजली की लाइनों या बिजली संयंत्रों या मीटर को बदलने, बदलने या बनाए रखने के लिए प्रवेश और ऐसे अन्य मामलों को रोकना।”

(जोर दिया गया) 81। 2003 के अधिनियम की धारा 50 निर्दिष्ट करती है कि राज्य आयोग एक विद्युत आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करेगा। धारा 2 (64) "राज्य आयोग" को धारा 82 (1) के तहत गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग के रूप में परिभाषित करती है। राज्य आयोग धारा 181 (2) (x) के तहत विद्युत आपूर्ति संहिता को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत है। धारा 50 के तहत "बिजली शुल्क की वसूली", "आपूर्ति का विच्छेदन", "आपूर्ति की बहाली" जैसी अभिव्यक्तियों का उपयोग इंगित करता है कि उक्त प्रावधान के तहत राज्य आयोग की नियामक शक्तियों का दायरा परिसर में बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।

ग

डी.

ई.

82. 2003 का अधिनियम भारत में बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग के लिए विधायी ढांचा निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया में, संसद ने विनियामक प्राधिकरणों, विशेष रूप से केंद्रीय आयोग और राज्य आयोग को कानून में निर्धारित विधायी नीति के ढांचे के भीतर आगे के विवरणों पर काम करने का विवेकाधिकार भी दिया है। अधीनस्थ विधान बनाते समय, प्रत्यायोजित प्राधिकारी को पूर्ण विधान की सीमा के भीतर कार्य करना होता है। 42 केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग द्वारा अधिनियमित नियम या विनियम असंगत प्रावधानों को निर्धारित करके या मूल कानून को प्रतिस्थापित करके 2003 के अधिनियम को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। 83. 2003 का अधिनियम राज्य आयोग को धारा 181 (2) के तहत निर्दिष्ट मामलों पर विनियम बनाने का अधिकार देता है। पीटीसी इंडिया में

च

जी.

लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 43 ए संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि विनियम राज्य द्वारा बनाए जा सकते हैं

42 जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2007) 13 एस. सी. सी. 673 43 (2010) 4 एस. सी. सी. 603

एच.

690

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

आयोग जब तक वे दो शर्तों को पूरा करते हैं: पहला, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए और दूसरा, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा:

“28. 2003 के अधिनियम में तीन प्रकार के प्रत्यायोजित कानूनों पर विचार किया गया है। सबसे पहले, धारा 176 के तहत, केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तदनुसार, राज्य सरकारों को भी धारा 180 के तहत नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। दूसरा, धारा 177 के तहत, केंद्रीय प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम बनाने का भी अधिकार है। तीसरा, धारा 178 के तहत केंद्रीय आयोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है। एस. ई. आर. सी. के पास धारा 181 के तहत एक संबंधित शक्ति है। नियम और विनियमों को, यथास्थिति, संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष धारा 179 और 182 के तहत रखा जाना चाहिए। संसद के पास नियमों/विनियमों को संशोधित करने की शक्ति है। यह शक्ति राज्य को नहीं दी गई है।

ग

डी.

विधायिकाएँ। 2003 के अधिनियम के समग्र अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनियम तब तक बनाए जा सकते हैं जब तक कि दो शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात्, वे अधिनियम के अनुरूप हैं और वे अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।

ई.

(जोर दिया गया) 84।2003 के अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि धारा 181 (2) के तहत राज्य आयोग की नियामक शक्तियां व्यापक रूप से महत्वपूर्ण हैं।आयोग के पास धारा 50 के तहत विद्युत आपूर्ति संहिता सहित धारा 181 (2) में निहित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ पूर्ण शक्तियां हैं।तदनुसार, आयोग बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों जैसे "शुल्क की वसूली", "आपूर्ति का विच्छेदन" और "आपूर्ति की बहाली" को नियंत्रित करने वाली आपूर्ति संहिता को अधिसूचित कर सकता है।हमारी राय में, इस तरह के प्राधिकरण का विस्तार नए या बाद के मालिकों से पिछले मालिकों के बिजली बकाया की वसूली के लिए शर्तों को निर्धारित करने तक है।

च

जी.

85. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (ऊपर) में, दो-न्यायाधीश

पीठ उपविभाजित भूखंडों के खरीदार से बिजली बकाया वसूलने के लिए अपीलकर्ता लाइसेंसधारी की कार्यवाहियों की वैधता पर विचार कर रही थी।उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता के खंड 4.3 में निर्धारित किया गया है कि एक नया ए

एच.

691

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

उपविभाजित परिसरों के लिए कनेक्शन तभी दिया जाएगा जब ऐसे परिसरों के लिए देय बकाया का हिस्सा आवेदक द्वारा विधिवत भुगतान किया जाए।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि बिजली की आपूर्ति के संबंध में बकाया राशि, जब वे पिछले मालिक या रहने वाले के कब्जे में थे, बिजली की आपूर्ति बहाल करने या परिसर में एक नया कनेक्शन प्रदान करने से पहले चुकाई जानी चाहिए।इसलिए, एक शर्त जो वितरण लाइसेंसधारी को परिसर में बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू करने से पहले पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया के भुगतान पर जोर देने में सक्षम बनाती है, 2003 के अधिनियम की योजना के तहत वैध और अनुमेय है।

ग

86. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या बाद के मालिक से पिछले उपभोक्ता के बकाया की भरपाई के लिए प्रावधान करने वाले विनियमन का 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ उचित संबंध है। 2003 के अधिनियम की धारा 42 में वितरण लाइसेंसधारी से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति के लिए अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता है। एक वितरण लाइसेंसधारी एक मध्यस्थ होता है, जो उपभोक्ता को उनके परिसर में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बिजली की आपूर्ति करने का कार्य करता है।उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए, एक वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की लाइनें, ट्रांसफॉर्मर और अन्य उपकरण जैसे बुनियादी ढांचे को बिछाने की आवश्यकता होती है।बिजली की आपूर्ति की प्रकृति उपभोक्ता के प्रकार के साथ-साथ उनकी आवश्यकताओं पर भी निर्भर करती है।धारा 42 के अनुसार बुनियादी ढांचे को तैयार रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ संचालन और रखरखाव लागत के लिए लाइसेंसधारी को एक महत्वपूर्ण पूंजी परिव्यय करना पड़ता है।उपभोक्ता द्वारा बिजली का उपभोग नहीं करने पर भी लाइसेंसधारियों को बुनियादी ढांचे को बनाए रखना आवश्यक है।उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों के बकाया का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है।

डी.

ई.

च

87. 2003 का अधिनियम बिजली उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। एक नए मालिक से पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया की वसूली के लिए प्रदान की जाने वाली आपूर्ति शर्तें बुनियादी ढांचे को निर्धारित करने के लिए खर्च की गई लागत के साथ-साथ बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों के प्रति चल रही वर्तमान देनदारियों की वसूली के लिए आवश्यक हैं। ऐसी शर्तों के अभाव में, वितरण लाइसेंसधारियों के लिए यह मुश्किल हो सकता है

जी.

एच.

692

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

राजस्व घाटे को बढ़ाते हुए चूक किए गए भुगतानों की वसूली करना। इससे वितरण लाइसेंसधारियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान हो सकता है।

88. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (ऊपर) में, यह न्यायालय

यह देखा गया कि वितरक के हितों की रक्षा के लिए एक शर्त यह निर्धारित की गई थी कि वितरण लाइसेंसधारी नए मालिक या अधिभोगकर्ता से बिजली बकाया वसूल कर सकता है। यह देखा गया:

“13. वितरक द्वारा एक शर्त कि परिसर में आपूर्ति की जाने वाली बिजली के संबंध में बकाया राशि का भुगतान बिजली की आपूर्ति बहाल होने या किसी परिसर में नया कनेक्शन दिए जाने से पहले किया जाना चाहिए, को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की शर्त के अभाव में, एक बेईमान उपभोक्ता दंड से मुक्ति के साथ चूक कर सकता है, और जब भुगतान न करने के कारण बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है, तो वह संपत्ति बेच सकता है और दूसरी संपत्ति में जा सकता है, जिससे वितरक के लिए बकाया वसूल करना असंभव नहीं तो मुश्किल हो जाता है। होने के नाते

ग

डी.

बिजली के उपभोक्ताओं की बहुत बड़ी संख्या और औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रतिष्ठानों के बार-बार स्थानांतरण या स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए, वितरक के हितों की रक्षा के लिए बिजली आपूर्ति संहिता के खंड 4.3 (जी) और (एच) के समान प्रावधान आवश्यक हैं।”

ई.

(जोर दिया गया) 89। बिजली एक सार्वजनिक वस्तु है। कानून की अदालत की व्याख्या से इस स्थिति को बढ़ावा मिलना चाहिए। हैदराबाद वनस्पति (उपर्युक्त) में यह न्यायालय आपूर्ति की शर्तों के खंड 39 की वैधता पर निर्णय ले रहा था जिसमें विभिन्न कदाचारों को परिभाषित किया गया था और नामित अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए प्रावधान किया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि पूरे राज्य में सबसे कुशल और किफायती तरीके से बिजली की आपूर्ति, प्रसारण और वितरण करना बोर्ड का वैधानिक कर्तव्य है। यह भी देखा गया कि उपभोक्ताओं द्वारा अनधिकृत उपयोग, चोरी या कदाचार को रोकने के लिए खंड 39 जैसे नियम और शर्तें आवश्यक थीं। इस तरह की शर्तें चोरी से हुए नुकसान की भरपाई करने और इसी तरह के कदाचार की निरंतरता को रोकने के लिए आवश्यक थीं।

च

जी.

90. एक सार्वजनिक वस्तु की रक्षा करने के अलावा, ऐसी स्थितियों का 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ एक उचित संबंध भी है, जैसे कि बिजली उद्योग का एक मजबूत विकास, ए के हितों की रक्षा करना।

एच.

693

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

उपभोक्ताओं के साथ-साथ वितरण लाइसेंसधारियों के वित्तीय हित। वितरण लाइसेंसधारियों के वित्तीय हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को 2003 के अधिनियम की धारा 61 में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है जो उपयुक्त आयोग को वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। धारा 61 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“61. शुल्क नियम।- उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करेगा, और ऐसा करने में, निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा, अर्थात्:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

(ख) बिजली का उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर की जाती है।

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और साथ ही उचित तरीके से बिजली की लागत की वसूली करना।

डी.

(जोर दिया गया) 91। आपूर्ति और बिजली आपूर्ति संहिता की शर्तें जिनके लिए बिजली कनेक्शन देने की शर्त के रूप में पिछले मालिक के बिजली बकाया के भुगतान की आवश्यकता होती है, मूल कानूनों की योजना और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक स्पष्ट संबंध है। वितरण लाइसेंसधारियों के लिए यह उचित और उचित है कि वे आपूर्ति की शर्तों को निर्दिष्ट करें जिसमें परिसर के बाद के मालिक या अधिभोगियों को अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में पिछले मालिक या अधिभोगियों के बिजली बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

ई.

च

V. क्या बिजली का बकाया परिसर पर शुल्क या बोझ बन सकता है।

92. अगला मुद्दा जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या बिजली का बकाया परिसर पर शुल्क या बोझ बन सकता है। एक सहायक मुद्दा यह है कि क्या इस तरह के बकाया केवल कानून के एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से संपत्ति पर शुल्क बन सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना विश्लेषण शुरू करें, हम स्पष्ट करते हैं कि पंजीकरण के संबंध में नीलामी खरीदारों के प्रस्तुतिकरण से निपटना अनावश्यक है।

जी.

एच.

694

भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 एक शुल्क का गठन करने के लिए अनुबंध में निहित आपूर्ति की शर्तों के लिए है। का निर्णय

एम. एल. अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एम. वी. वेंकट शास्त्री और

पुत्र, 44 इस हद तक सीमित था कि यह मानता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 के तहत पक्षों के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया आरोप भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 59 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है।

93. नीलामी खरीदारों का तर्क है कि बिजली का बकाया संपत्ति पर शुल्क नहीं है क्योंकि वे भूमि के साथ नहीं चलते हैं। उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के फैसले पर भरोसा किया है।

निगम बनाम हाजी अब्दुलगफुर हाजी हुसैनभा 45 प्रस्तुत करने के लिए कि

ग

शुल्क की सूचना के बिना मूल्य के लिए हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति के खिलाफ शुल्क का प्रवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, और बिजली बकाया बस एक असुरक्षित ऋण है। दूसरी ओर, विद्युत उपयोगिताएँ प्रस्तुत करती हैं कि यह उनका मामला भी नहीं है-कानून के एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में-कि इस रूप में संपत्ति पर कोई बंधक या शुल्क है कि लाइसेंसधारी एक सुरक्षित लेनदार होगा।

डी.

94. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 में दो प्रकार के शुल्कों पर विचार किया गया है: पक्षकारों के कार्य द्वारा बनाए गए आरोप और कानून के संचालन से उत्पन्न होने वाले आरोप। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

“100. शुल्क: जहाँ एक व्यक्ति की अचल संपत्ति पक्षकारों के कार्य या कानून के संचालन द्वारा दूसरे को धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति बनाई गई है, और लेन-देन बंधक के बराबर नहीं है, तो बाद वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि

ई.

संपत्ति पर प्रभार; और इसमें पहले से निहित सभी प्रावधान 1 [जो एक साधारण बंधक पर लागू होते हैं, जहां तक हो सके, ऐसे शुल्क पर लागू होंगे]।

च

इस धारा में कुछ भी न्यास संपत्ति के निष्पादन में उचित रूप से किए गए खर्चों के लिए न्यासी के प्रभार पर लागू नहीं होता है।

उसका न्यास, [और, कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, उस व्यक्ति के हाथों में किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई आरोप लागू नहीं किया जाएगा जिसे ऐसी संपत्ति विचार के लिए और आरोप की सूचना के बिना हस्तांतरित की गई है।”

जी.

(जोर दिया गया)

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

95. बोझ का अर्थ है संपत्ति पर बोझ या प्रभार या किसी संपत्ति या भूमि पर दावा या ग्रहणाधिकार। देनदारी संपत्ति पर एक शुल्क होना चाहिए, जो संपत्ति के साथ चलना चाहिए। धारा 100 के पहले पैराग्राफ के संदर्भ में, जब एक पक्ष की अचल संपत्ति को दूसरे को धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जाता है, और लेनदेन एक बंधक का गठन नहीं करता है, तो बाद वाला संपत्ति पर शुल्क प्राप्त करेगा। साधारण बंधक पर लागू होने वाले सभी प्रावधान शुल्क पर लागू होते हैं। शुल्क न तो बिक्री है और न ही बंधक क्योंकि यह किसी अचल संपत्ति में या उस पर कोई ब्याज पैदा नहीं करता है, बल्कि यह केवल धन के भुगतान के लिए एक प्रतिभूति है। 46 दूसरे शब्दों में, एक शुल्क के परिणामस्वरूप केवल ऋण या संबंधित दायित्व की संतुष्टि के लिए संपत्ति से भुगतान का अधिकार पैदा होता है।

ग

96. धारा 100 का दूसरा पैराग्राफ इस सामान्य प्रस्ताव के लिए एक अपवाद प्रदान करता है कि भूमि के साथ एक शुल्क चलता है और इसे लागू किया जा सकता है, भले ही संपत्ति किसी तीसरे पक्ष के हाथों में चली गई हो। इसमें प्रावधान है कि हस्तांतरणकर्ता के हाथों में किसी संपत्ति के खिलाफ बिना किसी सूचना के आरोप लागू नहीं किया जा सकता है। शब्द "अन्यथा बचाएँ"

डी.

उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है "इंगित करें"

कि कानून का एक स्पष्ट प्रावधान मौजूद होने पर बिना किसी सूचना के हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए, किसी हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ आरोप तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई हो, जब तक कि इस तरह की सूचना की आवश्यकता को कानून द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया हो। 47

ई.

97. ए. आई. चम्पदानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक, 48

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानून के इस तरह के प्रावधान को केवल एक आरोप नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे आरोप की सूचना के बिना हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति के खिलाफ मूल्य के लिए आरोप को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करना चाहिए।

च

98. हाजी अबदुलगफुर हाजी हुसैनभाई (ऊपर) में, यह न्यायालय

धारा 100 के तहत प्रदान किए गए रचनात्मक सूचना के सिद्धांत पर विचार किया। उस मामले में, नगर निगम के पास एक व्यक्ति की संपत्ति पर शुल्क था जो संपत्ति कर के बकाया में था। एक नीलामी खरीदार, जो संपत्ति का मालिक बन गया, ने अपने शुल्क का प्रयोग करते हुए लंबित करों के बकाया की वसूली के नगर निगम के प्रयास का इस आधार पर विरोध किया कि उन्हें पिछली नगरपालिका के बारे में जानकारी नहीं थी

जी.

46 दत्तात्रेय शंकर मोटे बनाम आनंद चिंतामन दातार और अन्य, (1974) 2 एस. सी. सी. 799 47 दत्तात्रेय शंकर मोटे बनाम आनंद चिंतामन दातार, (1974) 2 एस. सी. सी. 799; कर्नाटक राज्य बनाम श्रेयस पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2006 (1) एस. सी. सी. 615

एच.

696

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

कर बकाया। निगम ने तर्क दिया कि हस्तांतरणकर्ता पर बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1949 की धारा 141 के कारण संपत्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप की रचनात्मक जानकारी के साथ आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने नगर निगम के खिलाफ इस आधार पर निर्णय दिया कि मामले के तथ्यों में, वादी के पास नगर पालिका के बकाया की रचनात्मक सूचना नहीं थी।

99. धारा 100 के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 100 का उत्तरार्ध एक सामान्य निषेध लागू करता है और आरोप की सूचना के बिना विचार के लिए हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति के खिलाफ कोई आरोप लागू नहीं किया जा सकता है। धारा 100 के संदर्भ में, इस नियम के लिए एक अपवाद कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्या अंतरिती के पास वास्तविक या रचनात्मक सूचना है जो धारा 100 के परंतुक में सूचना की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: “4. यह धारा असंदिग्ध भाषा में यह बताती है कि आरोप की सूचना के बिना विचार के लिए हस्तांतरणकर्ता के हाथों में किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई आरोप लागू नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां यह उस समय लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो। कानून के बचत प्रावधान को स्पष्ट रूप से हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति के खिलाफ शुल्क की सूचना के बिना मूल्य के लिए आरोप को लागू करने का प्रावधान करना चाहिए और न कि केवल आरोप बनाना चाहिए।..... कानून के बचत प्रावधान का वास्तविक मूल केवल आरोपित संपत्ति के खिलाफ आरोप की प्रवर्तनीयता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आरोप की सूचना के बिना विचार के लिए हस्तांतरणकर्ता के हाथों में उक्त संपत्ति के खिलाफ आरोप की प्रवर्तनीयता होनी चाहिए। बम्बई नगरपालिका अधिनियम की धारा 141 स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान नहीं है। दूसरा विवाद विफल हो जाता है और खारिज कर दिया जाता है।”

ग

डी.

ई.

च

100. विद्युत उपयोगिताओं के वकील ने 2003 के अधिनियम के पूर्ण कानून में किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके द्वारा बिजली बकाया परिसर पर शुल्क का गठन करेगा। 1910 के अधिनियम, 1948 के अधिनियम और 2003 के अधिनियम के प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि बिजली बकाया का बकाया संपत्ति पर शुल्क होगा या यह कि ऐसा शुल्क बिना किसी सूचना के हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ लागू किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने दोहराया है कि बिजली का बकाया ए में परिसर पर शुल्क या बोझ नहीं बन सकता है।

जी.

एच.

697

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

1910 अधिनियम, 1948 अधिनियम या 2003 अधिनियम में कानून के स्पष्ट प्रावधान का अभाव। 49.

101. ईशा मार्बल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि 1948 अधिनियम के साथ पठित 1910 अधिनियम के प्रावधानों के तहत, बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क नहीं लगाता है। यह देखा गया:

“56. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने विद्युत अधिनियम की धारा 24 का सही अर्थ निकालने का विकल्प चुना है। वहाँ कोई नहीं है

संपत्ति पर शुल्क। जहाँ वह परिसर नीलामी-खरीदार के स्वामित्व या कब्जे में आता है, जब ऐसा खरीदार बिजली की आपूर्ति चाहता है तो उसे आपूर्ति की पूर्व शर्त के रूप में पिछले बकाया का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जो मायने रखता है वह पूर्व उपभोक्ता द्वारा बोर्ड के साथ किया गया अनुबंध है। बोर्ड उनके खिलाफ संविदात्मक दायित्व के प्रवर्तन की मांग नहीं कर सकता है।

ग

तीसरा पक्ष। बेशक, बिक्री के प्रामाणिक विचार प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।”

डी.

102. इसी तरह, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (ऊपर) में,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसके विपरीत किसी अनुबंध के अभाव में, बिजली की आपूर्ति के लिए देय राशि परिसर में शुल्क नहीं है।

103. नतीजतन, सामान्य कानून में, परिसर के हस्तांतरणकर्ता को पिछले मालिक के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि बिजली बकाया स्वचालित रूप से परिसर पर शुल्क नहीं बन जाता है। ऐसी कार्रवाई केवल तभी अनुमत है जब आपूर्ति की वैधानिक शर्तें बिजली के नए कनेक्शन का दावा करने वाले बाद के खरीदार से बकाया बिजली की वसूली को अधिकृत करती हैं, या यदि हस्तांतरणकर्ता पर वैधानिक शुल्क के निर्माण के लिए कानून का कोई स्पष्ट प्रावधान है।

ई.

च

104. अगला मुद्दा जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या 2003 के अधिनियम में अपनी नियम बनाने की शक्ति के तहत एक नियामक आयोग द्वारा अधिनियमित वैधानिक नियमों या नियमों के माध्यम से बिजली शुल्क लागू किया जा सकता है।

जी.

105. नीलामी खरीदारों के वकील ने डिप्टी पर भरोसा किया है

वाणिज्यिक कर अधिकारी, पार्क टाउन डिवीजन बनाम शा सुखराज पीराजी, **50** और भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद बनाम बार

49 1995 एस. सी. सी. (2) 648; ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2; (2010) 9 एस. सी. सी. 145 50 ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 67

एच.

698

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

भारतीय परिषद, 51 का तर्क है कि किसी आरोप को विनियमों के माध्यम से पेश नहीं किया जा सकता है क्योंकि विषय वस्तु 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत नहीं आती है। यह भी तर्क दिया गया कि भूमि पर केवल वैधानिक अधिभार के माध्यम से राजकोषीय शुल्क लगाया जा सकता है। बिजली के संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि एक राज्य कानून केवल बिजली की खपत या बिक्री पर शुल्क लगाने का प्रावधान करके संपत्ति पर शुल्क का प्रावधान कर सकता है।

इंडिया सीमेंट लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 52 और अल चंपदानी इंडस्ट्रीज बनाम आधिकारिक परिसमापक 53 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है

कि केवल इस तरह का राजकोषीय अधिभार ही भूमि से जुड़ा होगा। 106. राज्य के भीतर बिजली की खपत या बिक्री पर कर का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 53, सूची II के तहत आता है। कई राज्यों ने बिजली की खपत या आपूर्ति पर बिजली शुल्क लगाने के लिए कानून बनाए हैं। इन मामलों में, विधायिका विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि राज्य के कानून के तहत देय शुल्क आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के लिए लाइसेंसधारी द्वारा वसूल की जाने वाली राशि पर पहला शुल्क होगा। इसके अलावा, जिस तरीके से उपभोक्ता से इस तरह के शुल्क की वसूली की जानी है, वह राज्य के कानून और प्रासंगिक अधीनस्थ कानून में प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए, केरल विद्युत शुल्क अधिनियम 1963 और केरल विद्युत शुल्क नियम 1963 में प्रावधान किया गया है कि बिजली शुल्क के प्रति उपभोक्ता का बकाया खपत की गई ऊर्जा के लिए वसूली योग्य राशि पर पहला शुल्क बनाता है। 107. हालाँकि, सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 53 का मामलों के इस समूह में शामिल मुद्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न तो संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत कोई कर लगाया जाता है और न ही कोई कर लगाया जाता है। यह वितरण लाइसेंसधारियों का मामला नहीं है कि 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत राज्य आयोग के पास राजकोषीय व्यय का प्रावधान करने की शक्ति है।

ग

डी.

ई.

च

108. एक अधीनस्थ नियम या विनियमन, जैसा कि एक नियामक आयोग द्वारा बनाए गए विद्युत आपूर्ति संहिता के मामले में, उस परिसर में एक वैधानिक शुल्क लगाने का प्रावधान कर सकता है जिसके भीतर बिजली की खपत प्रभावित हुई थी। 2003 के अधिनियम की धारा 50 के संदर्भ में, एक राज्य आयोग को बिजली शुल्क की वसूली, बिजली शुल्क के बिलिंग के लिए अंतराल, भुगतान न करने पर बिजली की आपूर्ति को काटने, बिजली की आपूर्ति की बहाली और अन्य संज्ञानात्मक मामलों का प्रावधान करने का अधिकार है। 2003 के अधिनियम की धारा 181 के अनुसार,

जी.

51 1995 (1) एससीसी 732 52 (1990) 1 एससीसी 12 53 (2009) 4 एससीसी 486 ए

एच.

699

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

राज्य आयोग को अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाने का अधिकार है जो अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करते हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में कहा गया है, धारा 50 के साथ पठित धारा 181 के तहत निहित नियम बनाने की शक्ति इतनी व्यापक है कि नियामक आयोग को ऐसे शुल्क के निर्माण के लिए प्रावधान करने वाले पूर्ण कानून में प्रावधान के अभाव में वैधानिक शुल्क का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। राज्य आयोग को पिछले मालिक के बिजली बकाया की वसूली के लिए बिजली आपूर्ति संहिता में विभिन्न तंत्र प्रदान करने के लिए वैधानिक ढांचे के तहत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। बिजली बकाया की वसूली या तो बिजली कनेक्शन के लिए एक शर्त के रूप में बकाया भुगतान का भुगतान करने के लिए परिसर के बाद

के मालिक की आवश्यकता से प्रभावी हो सकती है, या यह मानते हुए कि लाइसेंसधारी को देय कोई भी राशि परिसंपत्तियों पर पहला शुल्क होगी, या किसी अन्य उचित शर्त से।

ग

109. इस तरह की शक्ति का उपयोग करते हुए, महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के विनियम 10.5 में प्रावधान है कि बिजली या किसी अन्य राशि के लिए कोई भी शुल्क जो किसी पूर्व मालिक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, संपत्ति पर शुल्क का गठन करता है और हस्तांतरणकर्ता से उसमें निर्दिष्ट अनुमत अवधि के अधीन वसूल किया जा सकता है। वर्तमान निर्णय में वर्णित यह प्रावधान केवल एक अधीनस्थ नियम का एक उदाहरण है जिसमें अवैतनिक बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क का गठन करता है और बाद में हस्तांतरणकर्ता से वसूल किया जा सकता है।

डी.

ई.

110. नीलामी खरीदारों द्वारा भारत में लिए गए निर्णयों पर भरोसा

सीमेंट लिमिटेड (ऊपर) या भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद

(उपर्युक्त) उनके उद्देश्य के लिए बहुत कम सहायता प्रदान करते हैं। इंडिया सीमेंट लिमिटेड (ऊपर) में सवाल यह था कि क्या राज्य विधानमंडल को सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी पर उपकर लागू करने की क्षमता थी। भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के भाग VI के अध्याय III में नियम 9 पर विचार किया, जो 45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने से रोकता है। ये दोनों निर्णय वर्तमान अपीलों में उत्पन्न हुए मुद्दे के लिए बहुत कम प्रासंगिक हैं।

च

जी.

111. नीलामी खरीदारों ने भी शा सुखराज पीराजी (ऊपर) के निर्णय पर भरोसा किया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 की धारा 19 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम 21-ए अधिकार से बाहर है। नियम 21-ए के संदर्भ में, एक 'विक्रेता' द्वारा किए गए व्यवसाय के खरीदार को बकाया राशि के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

एच.

700

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

हस्तांतरण से पहले हुए बिक्री के लेन-देन के संबंध में विक्रेता से देय बिक्री कर। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 19 के तहत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग अधिनियम के तहत 'विक्रेता' के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कर की वसूली और भुगतान के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। 1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 10 में प्रावधान किया गया था कि चूक की तारीख को बकाया राशि को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की संपत्ति पर शुल्क लगाया गया था। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10 के महत्व पर विचार नहीं किया क्योंकि संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले व्यवसाय हस्तांतरित किया गया था। मामले का अनुपात न तो सहायक है और न ही तत्काल मामले में लागू होता है, क्योंकि यह न्यायालय मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1939 के विशिष्ट प्रावधानों पर विचार कर रहा था।

112. कानून के प्रावधानों और आपूर्ति की वैधानिक शर्तों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या आपूर्ति की शर्तें संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 100 के संदर्भ में शुल्क के निर्माण के लिए प्रदान करती हैं। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि एक वैधानिक शुल्क बनाया गया है और आवश्यक सूचना दी गई थी, तो शुल्क संपत्ति से जुड़ा होता है और लाइसेंसधारी परिसर के खिलाफ कार्यवाही करके अवैतनिक बिजली बकाया की वसूली करने का हकदार होता है। बनाए गए आरोप के परिणामस्वरूप, भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 62 लागू होगा। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 62 अचल संपत्ति पर गिरवी या अन्यथा प्रभारित धन के भुगतान को लागू करने से संबंधित है। बिजली उपयोगिताओं को देय राशि देय होने की तारीख से अचल संपत्ति पर देय राशि की वसूली के लिए बारह साल की अवधि मिलेगी।

डी.

ई.

113. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी राय है कि बिजली उपयोगिताएँ अधीनस्थ कानून या आपूर्ति की वैधानिक शर्तों को तैयार करके एक शुल्क बना सकती हैं जो बाद में हस्तांतरणकर्ता से बिजली बकाया की वसूली को संक्षम बनाती हैं। ऐसी स्थिति बिजली की रक्षा के महत्व में निहित है जो एक सार्वजनिक वस्तु है। सार्वजनिक उपयोगिताएँ बिजली आपूर्ति प्रदान करने में भारी मात्रा में पूंजी और बुनियादी ढांचे का निवेश करती हैं। परिसर के बकाया बिजली की वसूली करने में विफलता या असमर्थता ऐसी सार्वजनिक उपयोगिताओं और लाइसेंसधारियों के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। व्यापक लोक हित में, अधीनस्थ कानून में शर्तों को शामिल किया गया है जिसके तहत विद्युत उपयोगिताएँ बिजली के बकाया की भरपाई कर सकती हैं। नई अवसंरचना तैयार करने और मौजूदा अवसंरचना को बनाए रखने के लिए धन और निवेश प्रदान करने के लिए बिजली बकाया की भरपाई आवश्यक है। इस तरह के प्रावधान के अभाव में, विद्युत उपयोगिताओं को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाएगा और ए देने के लिए मजबूर किया जाएगा।

च

जी.

एच.

701

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

बिजली का नया कनेक्शन, तब भी जब बिजली का भारी बकाया हो। उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने के अलावा, यह उपभोक्ताओं के व्यापक निकाय को भी प्रभावित करेगा।

VI. विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिजली बकाया की वसूली पर धारा **56 (2)** का प्रभाव

114. विद्युत उपयोगिताओं ने प्रस्तुत किया है कि 2003 के अधिनियम की धारा 56 केवल आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लाइसेंसधारी के अधिकार से संबंधित है। प्रासंगिक प्रावधान के दायरे को स्पष्ट करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 56 अलग-अलग समयसीमा निर्धारित करती है, अर्थात् (ए) कब डिस्कनेक्शन किया जा सकता है, यानी, जब आवश्यक सूचना देने के बाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है; (बी) डिस्कनेक्शन कब तक बनाए रखा जा सकता है, यानी, जब तक बकाया बकाया रहता है; और (सी) जब इसे बहाल किया जाना है, यानी तुरंत जब बकाया भुगतान किया जाता है। रिलायंस रहा है

ग

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम रहमतुल्लाह खान, 54 और मैसर्स प्रेम कॉर्टेक्स बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

यह तर्क देने के लिए सीमित 55 कि धारा 56 (2) में "इस धारा के तहत" अभिव्यक्ति के उपयोग का अर्थ है कि सीमा अवधि के बाद धन की वसूली के लिए संपर्क विच्छेद करने का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा 56 कानून के अनुसार वसूली के अन्य तरीकों के माध्यम से लंबित शुल्कों की वसूली पर रोक नहीं लगाती है। लाइसेंसधारियों का आग्रह है कि बिजली की वसूली के लिए नागरिक उपचार और वैधानिक शक्ति का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया था कि धारा 56 लाइसेंसधारी के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती है कि वह उसी परिसर में नए कनेक्शन के लिए बाद के आवेदक से परिसर में किए गए शुल्क के बकाया भुगतान पर जोर दे।

डी.

ई.

115. धारा 56 (2) के तहत दो साल की सीमा अवधि के निहितार्थ पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि (i) सीमा लाइसेंसधारक द्वारा डिस्कनेक्ट करने पर प्रतिबंध के संदर्भ में है; (ii) बकाया का भुगतान न करने के लिए बिजली बंद होने के बाद धारा 56 के तहत कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है; (iii) परिसर के पूर्व मालिक के खिलाफ बिजली बोर्ड के पक्ष में एक वैध और मौजूदा धन डिक्री दो साल की सीमा अवधि से प्रभावित नहीं होगी; (iv) परिसर को नया कनेक्शन देने के लिए पिछले बकाया की मांग करने के लिए लाइसेंसधारक के अधिकार की समाप्ति के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है; और (v) जब तक कनेक्शन नहीं दिया जाता है, तब तक कनेक्शन नहीं देने का लाइसेंसधारक का अधिकार।

च

जी.

54 (2020) 4 एससीसी 650

55 निर्णय डीटी। 5.10.2021 2009 के सीए 7235 में

एच.

702

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

116. दूसरी ओर नीलामी खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आग्रह किया है कि (i) धारा 56 (2) के तहत सीमा की अवधि, जो एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है, लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सफल नीलामी खरीदारों से बकाया बिजली की वसूली पर रोक लगाती है; (ii) किसी भी उपभोक्ता से देय राशि की वसूली पर प्रतिबंध से उबरने के लिए दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद जब ऐसी राशि पहली देय हो गई है, अर्थात् (क) ऐसी राशि को आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य दिखाया गया है, और (ख) लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा; (iii) आपूर्ति की शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। 56 117. उपभोक्ता को आपूर्ति बंद करने की शक्ति 2003 के अधिनियम की धारा 56 में दी गई है। प्रावधान नीचे निकाला गया है:

ग

डी.

“धारा 56: भुगतान की चूक में आपूर्ति का डिस्कनेक्शन

(1) जहां कोई व्यक्ति बिजली के लिए किसी भी शुल्क या बिजली के लिए शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने में लापरवाही करता है, जो उसे बिजली की आपूर्ति, संचरण या वितरण या पहियों के संबंध में किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन

करने वाली कंपनी को देय है, तो लाइसेंसधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी, कम से कम पंद्रह स्पष्ट दिनों की लिखित सूचना देने के बाद, ऐसे व्यक्ति को और उसके बिना।

ई.

इस तरह के शुल्क या अन्य राशि की वसूली के उसके अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह

वाद द्वारा, बिजली की आपूर्ति काट दी जाए और उस प्रयोजन के लिए किसी भी बिजली आपूर्ति लाइन या अन्य कार्यों को काट दिया जाए या काट दिया जाए जो ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी की संपत्ति है जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति, संचरण, वितरण या पहिया किया गया हो और आपूर्ति तब तक बंद कर दी जाए जब तक कि ऐसा शुल्क या अन्य राशि, आपूर्ति में कटौती करने और फिर से जोड़ने में उसके द्वारा किए गए किसी भी खर्च के साथ, भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन अब नहीं:

च

जी.

बशर्ते कि बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति विरोध के तहत जमा करता है, -

56 (1999) 3 एससीसी 657 ए

एच.

703

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

((क) उससे दावा की गई राशि के बराबर राशि, या

(ख) प्रत्येक महीने के लिए उससे देय बिजली शुल्क की गणना पिछले छह महीनों के दौरान उसके द्वारा भुगतान किए गए बिजली के लिए औसत शुल्क के आधार पर की जाती है, जो भी कम हो, उसके और लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद का निपटारा होने तक।

(2) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी।

उस तारीख से जब ऐसी राशि पहले देय हो गई है, जब तक कि ऐसी राशि को आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया है और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा।"

ग

(जोर दिया गया) 118। धारा 56 भाग VI के अंतर्गत आती है जिसका शीर्षक "बिजली का वितरण" है। धारा 56 में बिजली शुल्क के भुगतान में चूक होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति को काटने का प्रावधान है।

डी.

119. डिस्कनेक्ट करने की शक्ति एक कठोर कदम है जिसका सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब उपभोक्ता की ओर से बिजली शुल्क या लाइसेंसधारी या किसी उत्पादन कंपनी के बकाया का भुगतान करने में लापरवाही हो, जैसा भी मामला हो। धारा 56 (1) में प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति बिजली के लिए किसी भी शुल्क या बिजली के लिए शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने में लापरवाही करता है, तो लाइसेंसधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी पंद्रह दिनों की लिखित सूचना देने के बाद बिजली की आपूर्ति तब तक बंद कर सकती है, जब तक कि खर्च सहित ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। बिजली काटने की शक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्धारित की जाती है। कटौती या डिस्कनेक्शन, वसूली के

अन्य अनुमेय तरीकों से इस तरह के शुल्क या अन्य राशियों की वसूली के लिए वितरण लाइसेंसधारी के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। धारा 56 (1) के प्रावधान में एक अपवाद यह प्रावधान किया गया है कि बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं की जाएगी यदि उपभोक्ता, "विरोध के तहत", या तो दावा की गई राशि जमा करता है या पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए औसत शुल्क जमा करता है। 120. बिजली की आपूर्ति को काटने के लिए लाइसेंसधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी का वैधानिक अधिकार धारा 56 (2) द्वारा प्रदान की गई दो साल की सीमा की अवधि के अधीन है। धारा 56 (2) में प्रावधान है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, "इस धारा के तहत" किसी भी उपभोक्ता से देय कोई राशि नहीं होगी।

ई.

च

जी.

एच.

704

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य जब तक कि ऐसी राशि को आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया है और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा। दो साल की सीमा धारा 56 के तहत राशि की वसूली तक सीमित है। यह "इस खंड के तहत" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट होता है।

121. पहला मुद्दा बिजली बकाया की वसूली के लिए लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा वैधानिक और नागरिक उपचारों के एक साथ अभ्यास से संबंधित है। बिजली शुल्क का भुगतान करने का दायित्व एक वैधानिक दायित्व है और धारा 56 उन परिणामों का प्रावधान करती है जब कोई उपभोक्ता बिजली के लिए किसी भी शुल्क या उससे देय बिजली शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने की उपेक्षा करता है। धारा 56 (1) में प्रावधान किया गया है कि जब कोई उपभोक्ता भुगतान करने में विफल रहता है तो बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने की लाइसेंसधारी की शक्ति "इस तरह के शुल्क या अन्य राशि की वसूली के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" है। इसका मतलब है कि लाइसेंसधारी उपभोक्ता के खिलाफ वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए अपने वैधानिक उपाय के साथ-साथ एक नागरिक उपाय दोनों का प्रयोग कर सकता है क्योंकि लाइसेंसधारी आपूर्ति को काटकर उपभोक्ता से देय राशि प्राप्त नहीं करेगा। अपने फैसले में

ग

डी.

बिहार एस. ई. बी. बनाम आइसबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 57 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

धारा 56 के तहत आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने की शक्ति एक सूट स्थापित करके वसूली के सामान्य तरीके के अलावा आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली एक विशेष शक्ति है। बकाया राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप और बकाया राशि की वसूली के लिए एक विधि के रूप में बिजली की आपूर्ति को काटने की शक्ति बिजली शुल्क के कारण बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू करने के लिए लाइसेंसधारी के अधिकार के पूरक है। 122. 2003 के अधिनियम की धारा 56 (1) 1910 के अधिनियम की धारा 24 के समान है। 1910 के अधिनियम की धारा 24 ने विद्युत बोर्ड को एक मांग जारी करने और उन उपभोक्ताओं को आपूर्ति बंद करने का अधिकार दिया, जिन्होंने शुल्क का भुगतान करने की उपेक्षा की, बिना किसी मुकदमे के माध्यम से ऐसे शुल्क या अन्य राशियों की वसूली के अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव के। इस न्यायालय द्वारा धारा 24 के आयात पर ईशा मार्बल्स (ऊपर) में विचार किया गया था, जहां यह देखा गया था कि धारा 24 के तहत निर्धारित

नोटिस की सेवा के बाद बिजली की आपूर्ति में कटौती की कार्रवाई वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के सामान्य उपाय के अलावा थी।

ई.

च

जी.

123. मेसर्स स्वास्टिक इंडस्ट्रीज बनाम महाराष्ट्र राज्य

विद्युत बोर्ड, 58 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपूर्ति बंद करने का अधिकार

57 (2020) 20 एससीसी 745 58 (1997) 9 एससीसी 465 ए

एच.

705

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

1948 के अधिनियम की धारा 60 ए द्वारा धारा 24 के तहत बिजली की राशि को नहीं लिया गया था, जिसने बिजली बोर्ड को वहां निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर मुकदमा दायर करने का विकल्प प्रदान किया था। इस न्यायालय ने कहा कि:

“5. इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि शुल्क की वसूली का अधिकार इसका एक हिस्सा है और शुल्क का भुगतान करने की उपेक्षा करने वाले उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति बंद करने का अधिकार इसका दूसरा हिस्सा है। मुकदमा दायर करने का अधिकार लाइसेंसधारी, विद्युत बोर्ड को दिए गए विकल्प का विषय है। इसलिए, केवल यह तथ्य कि बोर्ड को मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया गया है और मुकदमा दायर करने के लिए सीमा निर्धारित की गई है, यह दिए गए अधिकार को नहीं छीनता है।

ग

बोर्ड धारा 24 के तहत शुल्क के भुगतान की मांग करने के लिए और उसी का भुगतान करने में लापरवाही करने पर उनके पास आपूर्ति को बंद करने या आपूर्ति में कटौती करने की शक्ति है, जैसा भी मामला हो, जब उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करने में लापरवाही करता है। द.

ऐसा प्रतीत होता है कि दायित्व पारस्परिक हैं।”

डी.

(आपूर्ति पर जोर) इसलिए, चूक करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करके वसूली की कार्यवाही शुरू करने की शक्ति वसूली के साधन के रूप में बिजली की आपूर्ति को काटने की शक्ति से स्वतंत्र है।

ई.

124. दूसरा मुद्दा बिजली बकाया की वसूली के लिए उपयोगिताओं के नागरिक उपचारों पर धारा 56 (2) में प्रदान की गई दो साल की अवधि के निहितार्थ से संबंधित है। धारा 56 (2), जो एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है, बिजली की आपूर्ति को काटने के माध्यम से लाइसेंसधारी द्वारा बकाया की वसूली के लिए दो साल की सीमा प्रदान करती है। यह धारा 56 के तहत उपभोक्ता से किसी भी देय राशि की वसूली करने के लिए लाइसेंसधारी के अधिकार पर उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद प्रतिबंध लगाता है जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई थी। यदि यह प्रावधान किसी उपभोक्ता के खिलाफ दो साल के बाद लागू किया जाता है, तो कार्रवाई की अनुमति तब दी जाएगी जब राशि, जो पहले देय थी, को आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य दिखाया गया है। धारा 56 के तहत, भुगतान करने का दायित्व बिजली की खपत पर

उत्पन्न होता है और भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब पहली बार लाइसेंसधारी द्वारा बिल जारी किया जाता है। तदनुसार, दो साल की सीमा की अवधि बिल जारी होने के बाद ही शुरू होती है।¹²⁵ इससे पहले कि हम किसी लाइसेंसधारी के लिए उपलब्ध नागरिक उपचारों पर धारा 56 (2) के निहितार्थ से निपटें, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि कब

च

जी.

एच.

706

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

उपभोक्ता द्वारा वहन किया गया दायित्व उस अवधि से पहले का है जब 2003 का अधिनियम लागू हुआ था, तो धारा 56 (2) के तहत सीमा का प्रतिबंध नहीं है

लागू होता है।कुसुमम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य बिजली

बोर्ड, 59 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 56 (2) 2003 के अधिनियम के लागू होने के बाद लागू होती है और धारा 56 (2) के तहत सीमा का प्रतिबंध अधिनियम के प्रवर्तन से पहले उपभोक्ता द्वारा किए गए दायित्व पर लागू नहीं होगा। सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के संदर्भ में, पिछले अधिनियम के तहत किया गया दायित्व जारी रहेगा और बिजली की वसूली के लिए लाइसेंसधारी का दावा नियामक ढांचे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो 2003 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले मौजूद था।

ग

126. 19 दिसंबर 2002 की अपनी रिपोर्ट में, ऊर्जा की स्थायी समिति ने राय दी कि धारा 56 के तहत बकाया की वसूली के लिए प्रतिबंध उपभोक्ता को मनमाने बिलिंग से बचाने के लिए आवश्यक माना गया था।⁶⁰ दूसरे शब्दों में, धारा 56 (2) का अधिनियमन मनमाने बिलिंग की शरारत को दूर करने के लिए था।इसलिए, धारा 56 (2) को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था कि कोई लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति को काटने की अपनी विशेष शक्ति का दुरुपयोग न करे।धारा 56 (2) यह सुनिश्चित करती है कि एक लाइसेंसधारी को लंबी अवधि के बाद मनमाने ढंग से बिल लगाने और फिर बिजली की आपूर्ति को काटने के कठोर कदम के माध्यम से इतनी बड़ी राशि की वसूली करने की स्वतंत्रता नहीं है।

डी.

127. रहमतुल्लाह खान (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने लाइसेंसधारी द्वारा उठाई गई अतिरिक्त या पूरक मांग पर धारा 56 (2) द्वारा प्रदान की गई सीमा की अवधि के लागू होने पर विचार किया।एक उपभोक्ता को एक विशेष टैरिफ के तहत बिल दिया जाता था, लेकिन एक ऑडिट के बाद यह पता चला कि एक अलग टैरिफ कोड लागू किया जाना चाहिए था।इसके बाद 2014 में जुलाई 2009 से सितंबर 2011 की अवधि के लिए एक अतिरिक्त विधेयक पेश किया गया।धारा 56 (2) की व्याख्या किसी गलती या प्रामाणिक त्रुटि के मामले में धारा 56 (2) के तहत सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद लाइसेंसधारी को पूरक मांग उठाने से रोकने के लिए नहीं की गई थी।हालांकि, यह लाइसेंसधारी को अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए बिजली आपूर्ति को काटने के दंडात्मक उपाय का सहारा लेने का अधिकार नहीं देता है।इस न्यायालय ने कहा कि दो साल की सीमा का प्रतिबंध लाइसेंसधारी को बिजली बकाया की वसूली के अन्य तरीकों का सहारा लेने से नहीं रोकता है।अदालत ने कहा:

ई.

च

जी.

59 (2008) 12 एससीसी213

60 ऊर्जा की स्थायी समिति-तेरहवीं लोकसभा, बिजली विधेयक 2001-प्यासी पहली रिपोर्ट, बिजली मंत्रालय (2002)

एच.

707

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

क.

“ 7.4 धारा 56 की उप-धारा (1) लाइसेंसधारी कंपनी को बिजली की आपूर्ति बंद करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है, यदि उपभोक्ता बिजली बकाया का भुगतान करने में लापरवाही करता है। यह वैधानिक अधिकार अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई दो साल की सीमा की अवधि के अधीन है।

7.5 दो साल की सीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन धारा **56** की उप-धारा **(2)** के तहत बिजली शुल्क "पहले देय" हो गए थे। यह प्रावधान

उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण बिजली आपूर्ति काट देने के लिए लाइसेंसधारी कंपनी के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, जब तक कि पिछली अवधि के लिए उठाए गए बिलों में आपूर्ति की गई बिजली की बकाया राशि के रूप में ऐसी राशि को लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया है। यदि लाइसेंसधारी कंपनी को राशि "पहले देय" होने के बाद दो साल की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद बिजली की आपूर्ति बंद करने की अनुमति दी जाती है, तो यह धारा 56 (2) के उद्देश्य को विफल कर देगा।

ग

डी.

8. हालांकि, धारा **56 (2)** लाइसेंसधारी कंपनी को अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद पूरक मांग करने से नहीं रोकती है।

दो साल की सीमा अवधि। यह केवल दो साल की सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद बकाया का भुगतान न करने के कारण बिजली आपूर्ति को काटने के लाइसेंसधारी के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, और न ही यह वसूली के अन्य तरीकों को प्रतिबंधित करता है जो लाइसेंसधारी कंपनी द्वारा पूरक मांग की वसूली के लिए शुरू किए जा सकते हैं।

ई.

9. वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ उपरोक्त अनुपात को लागू करते हुए, लाइसेंसधारी कंपनी ने जुलाई 2009 से सितंबर 2011 की अवधि के लिए 18-3-2014 पर एक अतिरिक्त मांग उठाई। लाइसेंसधारी कंपनी ने 18-3-2014 पर गलत टैरिफ कोड के तहत बिलिंग की गलती का पता लगाया। तब तक धारा 56 (2) के तहत दो साल की सीमा अवधि समाप्त हो चुकी थी।

च

9.1. धारा **56 (2)** लाइसेंसधारी कंपनी को गलती या वास्तविक त्रुटि के मामले में धारा **56 (2)** के तहत सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त या पूरक मांग करने से नहीं रोकती है। हालांकि, इसने लाइसेंसधारी कंपनी को अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए बिजली की आपूर्ति को काटने के दंडात्मक उपाय का सहारा लेने का अधिकार नहीं दिया।”

जी.

एच.

(जोर दिया गया)

128. इस न्यायालय द्वारा रहमतुल्लाह खान (ऊपर) में कानून की व्याख्या पर प्रेम कोर्टेक्स (ऊपर) में एक समन्वय पीठ द्वारा विचार किया गया था। एक उपभोक्ता को एक संक्षिप्त मूल्यांकन सूचना दी गई थी और न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या छोटी बिलिंग और बाद में अतिरिक्त मांग को बढ़ाना सेवा की कमी के समान होगा। इस न्यायालय ने कहा कि धारा 56 में अनुध्यात प्रतिबंध लाइसेंसधारी के दो अलग-अलग अधिकारों पर काम करता है, अर्थात्, वसूली का अधिकार और संपर्क विच्छेद का अधिकार। इस न्यायालय ने कहा कि सीमा कानून के तहत, उपचार समाप्त हो जाता है न कि अधिकार। डिस्कनेक्शन के उपचार के संदर्भ में बार को सीमा के कानून का अपवाद माना गया था। इस न्यायालय ने आगे धारा 56 (2) पर धारा 56 (1) के प्रभाव पर विचार किया और कहा:

ग

“15. इसलिए, बार वास्तव में लाइसेंसधारी के दो अलग-अलग अधिकारों पर काम करता है, अर्थात्, (i) वसूली का अधिकार; और (ii) डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। डिस्कनेक्ट करने के अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में प्रतिबंध, वास्तव में सीमा कानून का एक अपवाद है। सीमा कानून के तहत, जो बुझ जाता है वह उपचार है न कि अधिकार। सटीक रूप से, सीमा कानून द्वारा जो समाप्त किया जाता है, वह अदालत के माध्यम से उपचार है न कि अदालत के माध्यम से उपलब्ध उपचार, यदि कोई हो। हालांकि, धारा 56 (2) न केवल ठीक होने के सामान्य उपचार को प्रतिबंधित करती है, बल्कि डिस्कनेक्शन के उपचार को भी प्रतिबंधित करती है। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि धारा 56 (2) का दूसरा भाग सीमा कानून का अपवाद है।

डी.

ई.

....

23. दूसरे पहलू पर आते हुए, अर्थात्, धारा 56 की उप-धारा (2) पर उप-धारा (1) का प्रभाव, यह देखा जाता है कि उप-धारा (1) की मुख्य बात किसी भी व्यक्ति द्वारा बिजली के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने में लापरवाही है। उप-धारा (1) शब्दों से शुरू होती है

च

“ जहाँ कोई व्यक्ति बिजली के लिए कोई शुल्क देने की उपेक्षा करता है या

उससे देय बिजली के शुल्क के अलावा कोई अन्य राशि। 24. उप-धारा (2) में “इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से कोई राशि देय नहीं” शब्दों का उपयोग किया गया है। इसलिए, उप-धारा (2) के तहत प्रतिबंध धारा 56 के तहत देय राशि से संबंधित है। यह स्वाभाविक रूप से हमें उप-धारा (1) की ओर ले जाता है जो विशेष रूप से संबंधित है।

जी.

किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति की ओर से लापरवाही

बिजली या शुल्क ए के अलावा किसी अन्य राशि के लिए

एच.

बिजली के लिए।उप-धारा (1) के तहत धारा 56 में किसी व्यक्ति की ओर से बिजली के लिए भुगतान करने में लापरवाही शामिल है, न कि किसी और चीज के लिए और न ही लाइसेंसधारी की ओर से कोई लापरवाही।"

(जोर दिया गया) 129।धारा 56 (2) के तहत सीमा की अवधि धारा 56 के तहत देय राशि से संबंधित है।धारा 56 के तहत देय राशि बिजली के लिए भुगतान करने में किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण देय राशि से संबंधित है।धारा 56 (2) में प्रावधान है कि ऐसी देय राशि दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई थी।धारा 56 के तहत प्रदान किए गए वसूली के साधन बिजली की आपूर्ति के विच्छेदन के उपचार से संबंधित हैं।पुनर्प्राप्त करने का अधिकार अभी भी बना हुआ है।130. हम नीलामी खरीदारों की इस आपत्ति पर भी संक्षेप में विचार कर सकते हैं कि आपूर्ति की शर्तों का उपयोग समयबद्ध ऋणों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।वकील ने वी. टी. कल्लियानिकुट्टी (उपरोक्त) पर भरोसा व्यक्त किया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केरल राजस्व वसूली Act.This निर्णय के प्रावधानों का सहारा लेकर समयबद्ध ऋण की वसूली नहीं की जा सकती है, जो वर्तमान मामलों में नीलामी खरीदारों के लिए सहायक नहीं है।उस मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने केरल वित्त निगम द्वारा दिए गए कृषि ऋणों पर विचार करते हुए कहा कि चूंकि केरल राजस्व वसूली अधिनियम एक नया अधिकार नहीं बनाता है, इसलिए कोई व्यक्ति उन राशियों की वसूली का दावा नहीं कर सकता है जो कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं हैं।हालाँकि, अपने निर्णय पर पहुँचते हुए, इस न्यायालय ने तर्क दिया कि सीमा का कानून ऋण की वसूली के अधिकार को छुए बिना, एक निश्चित समय अवधि से परे मुकदमे के माध्यम से उपचार को प्रतिबंधित करता है।अधिकार अछूता रहता है और इसका उपयोग किसी भी अन्य उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

131. इसलिए हम नीलामी खरीदारों की इस दलील को खारिज करते हैं कि बकाया बिजली की वसूली या तो पूर्व उपभोक्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करके या बाद में हस्तांतरणकर्ता से आपूर्ति की प्रासंगिक शर्तों के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके 2003 के अधिनियम की धारा 56 (2) के तहत सीमा के आधार पर वर्जित है। तदनुसार, जबकि धारा 56 (2) के तहत सीमा का प्रतिबंध धारा 56 के तहत डिस्कनेक्शन के उपचार को प्रतिबंधित करता है, लाइसेंसधारी नागरिक उपचार के माध्यम से या आपूर्ति की शर्तों के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बिजली बकाया की वसूली करने का हकदार है।

जी.

एच.

710 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

VII. परिसर के बिजली बकाया के संदर्भ में या उसके बिना, "जैसा है, जहां है" के आधार पर परिसर की बिक्री का प्रभाव।

132. विद्युत उपयोगिताओं ने आग्रह किया है कि (i) नीलामी खरीदारों को बकाया भुगतान की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था; (ii) परिसरों की सार्वजनिक नीलामी-बिक्री "जैसा है वैसा ही" आधार पर आयोजित की गई थी; (iii) इसमें बिजली बकाया के भुगतान के एक विशिष्ट संदर्भ के साथ या उसके बिना परिसर के संबंध में सभी देनदारियों को स्वीकार करने की शर्त शामिल होगी; और (iv) वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न बिक्री में, नीलामी खरीदार को बकाया बकाया का उचित परिश्रम करना आवश्यक है जो परिसर विशिष्ट हैं।दूसरी ओर, नीलामी खरीदारों ने प्रस्तुत किया कि (i) "जैसा है जहां है" जैसी शर्त भौतिक संपत्ति की एक विशेषता है और उन दावों तक विस्तारित नहीं होती है जो भूमि के साथ चलने वाले शुल्क या अन्य बोझ नहीं हैं; (ii) तर्क पाता है

ग

पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण बनाम रघु नाथ गुप्ता **61** और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड **62** में निर्णयों में समर्थन; **(iii)** बिजली

डी.

देय राशि का निर्धारण केवल किसी संपत्ति को देखकर नहीं किया जा सकता है और **(iv)** ईशा संगमरमर (उपरोक्त) के फैसले को देखते हुए देय बिजली बकाया का पता लगाने के लिए आवेदकों पर कोई दायित्व नहीं था।**133.** वर्तमान मामलों के समूह में, परिसरों को नीलामी बिक्री में बेचा गया था जो आम तौर पर "जैसा है जहां है" के आधार पर आयोजित किया जाता था। "जैसा है जहां है" के आधार पर एक बिक्री यह मानती है कि खरीदार अपने सभी मौजूदा अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों के साथ संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। जब किसी संपत्ति को "जैसा है, जहां है" के आधार पर बेचा जाता है, तो बिक्री पर संपत्ति पर बोझ खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ई.

134. यू. टी. चंडीगढ़ प्रशासन बनाम अमरजीत सिंह **63,**

च

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उपभोक्ता शिकायत की रखरखाव के संदर्भ में सार्वजनिक नीलामी की विशेषताओं को समझाया। इस न्यायालय ने कहा कि जहां मौजूदा स्थलों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री या पट्टे के लिए रखा जाता है और बिक्री की पुष्टि सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पक्ष में की जाती है, परिणामी अनुबंध अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे से संबंधित है, न कि माल की सेवा या बिक्री के प्रावधान से। इस न्यायालय ने सार्वजनिक नीलामी की प्रकृति पर गौर किया और "जैसा है जहां है" आधार पर आयोजित नीलामी के निहितार्थ पर राय दी, जहां एक नीलामी खरीदार है।

जी.

61 (2012) 8 एससीसी 197 62 (2016) 13 एससीसी 561 63 (2009) 4 एससीसी 660 ए

एच.

711

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

किसी स्थल की स्थिति के संबंध में उचित परिश्रम करने की अपेक्षा। न्यायालय ने टिप्पणी की:

"19. साइटों की सार्वजनिक नीलामी में स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। इच्छुक व्यक्ति प्रस्तावित साइटों का निरीक्षण कर सकता है और उस साइट का चयन कर सकता है जिसे वह हासिल करना चाहता है और केवल ऐसी साइट के संबंध में नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी में बोली लगाने से पहले,

वह स्थल की स्थिति और स्थिति को जानता है या पता लगाने की स्थिति में है। वह सुविधाओं के अस्तित्व या कमी के बारे में जानता है। नीलामी 'जैसा है, जहां है' के आधार पर होती है। इस तरह के ज्ञान के साथ, वह नीलामी में भाग लेता है और एक विशेष बोली की पेशकश करता है। कोई मजबूरी नहीं है कि उसे पेश करना चाहिए।

ग

एक विशेष कीमत। जब नीलाम की गई साइटें मौजूदा साइटें हैं, तो सुविधाओं से संबंधित किसी भी आश्वासन/प्रतिनिधित्व के बिना, सेवा की कमी या सेवा से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां बोली लगाने वाले के पास साइट और कीमत के

संबंध में कोई विकल्प और विकल्प होता है और जब किसी सुविधा या सुविधा का कोई आश्वासन नहीं होता है, तो साइट के मालिक के सेवा प्रदाता बनने का सवाल ही नहीं उठता है।

डी.

20. जहां किसी विशिष्ट या विशेष सुविधाओं का आश्वासन दिए बिना सार्वजनिक नीलामी होती है, और संभावित खरीदार/पट्टेदार साइट की जांच करने का अवसर मिलने के बाद नीलामी में भाग लेता है, वहां नीलामी में बोली मौजूदा स्थिति, स्थिति और शर्तों को ध्यान में रखते हुए लगाई जाती है।

ई.

स्थल की स्थिति। यदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वह अधिक राशि की पेशकश करेंगे। यदि कोई सुविधा नहीं है, या यदि साइट को कोई नुकसान होता है, तो वह कम राशि की पेशकश करेगा, या नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति खुली आँखों से नीलामी में भाग लेता है, तो उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह कीमत/प्रीमियम की शेष राशि या विलंबित भुगतान पर निर्धारित ब्याज, या जमीनी किराए का भुगतान इस आधार पर नहीं करेगा कि साइट कुछ नुकसान से ग्रस्त है या इस आधार पर कि सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।"

च

जी.

(जोर दिया गया) 135। रघु नाथ गुप्ता (ऊपर), 64 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक भूखंडों की एक सफल नीलामी खरीदार को "जैसा है जहां है" आधार की अधिरोपित शर्त के साथ बेचा जाता है, जिसे बाद में यह तर्क देते हुए रद्द कर दिया जाता है कि

64 (2012) 8 एससीसी 197

एच.

712

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

वह नीलामी सूचना के नियमों और शर्तों से बाध्य नहीं है या विक्रेता ने बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। अदालत ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्धारित नियमों और शर्तों, विशेष रूप से खंड 25 पर भरोसा किया और कहा कि नीलामी नोटिस का विवाद को हल करने में काफी प्रभाव पड़ेगा। नीलामी सूचना के खंड 25 में प्रावधान किया गया है कि साइट को "जैसा है वैसा ही है" के आधार पर पेश किया गया था और प्राधिकरण साइट को समतल करने या संरचनाओं, यदि कोई हो, को हटाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वाक्यांश "जैसा है जहाँ है" को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था:

"14. हम देखते हैं कि उत्तरदाताओं ने उपरोक्त शर्तों के अधीन, खुली आँखों से वाणिज्यिक भूखंडों को स्वीकार किया था। जाहिर है, वाणिज्यिक भूखंडों का आवंटन "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर किया गया था। आवंटनकर्ताओं ने नीलामी के समय उपलब्ध सुविधाओं का पता लगा लिया होगा और वाणिज्यिक भूखंडों को "जैसा है वैसा ही है" के आधार पर स्वीकार करने के बाद, उन्हें यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि पुडा ने पार्किंग, रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की थीं।

ग

डी.

सड़कें, पानी, सीवर आदि। यदि आबंटित व्यक्ति वाणिज्यिक भूखंडों को "जैसा है, जहां है" के आधार पर लेने में रुचि नहीं रखते थे, तो उन्हें आबंटन स्वीकार नहीं करना चाहिए था और "जैसा है, जहां है" के आधार पर आबंटन स्वीकार करने के बाद, उन्हें यह तर्क देने से रोक दिया जाता है कि भूखंडों के आबंटन के समय पुडा द्वारा पार्किंग, रोशनी, सड़क, पानी, मलजल निकासी आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं।"

ई.

(जोर दिया गया)

136. केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (ऊपर) में,

च

उस विशेष मामले में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने "जैसा है वैसा ही है" शर्त पर विक्रेता की निर्भरता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 65 द्वारा नीलामी खरीदार को अनुमति देने से इनकार करने से, विक्रेता, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 66 और बिल्डर के बीच किए गए विकास समझौते में निराशा हुई। डी. ए. ने एक परियोजना भूमि के विकास के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए "जैसा है वैसा ही है" आधार पर नीलामी आयोजित की थी। बोली स्वीकार कर ली गई और डी. डी. ए. और बिल्डर के बीच एक विकास समझौता किया गया। हालाँकि, जब बिल्डर ने इसे पूरा करने का प्रयास किया

जी.

65 "डी. पी. सी. सी. "66" डी. डी. ए.

एच.

713

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

निर्माण गतिविधि, इसे डी. पी. सी. सी. द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था जिससे विकास गतिविधि में गतिरोध पैदा हो गया था। नीलामी के नियमों और शर्तों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि एक धारणा थी कि इच्छुक खरीदार ने साइट का निरीक्षण किया था और बोली लगाने से पहले उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सहित सभी मामलों में प्रचलित शर्तों से खुद को परिचित कराया था। विकास समझौते के खंड 6 के तहत, सरकारी विभागों से विभिन्न अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करना विकासकर्ता की जिम्मेदारी थी। विकास समझौते के खंड 11 में आगे यह निर्धारित किया गया कि बिल्डर ने स्थल और उसके आसपास का निरीक्षण किया और उपलब्ध जानकारी की जांच की। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जैसा है वैसा ही" आधार पर नीलामी बिक्री और विकास समझौते के विशेष खंड "केवल परियोजना भूमि से संबंधित भौतिक मुद्दों और वास्तविक निर्माण गतिविधि से संबंधित सहायक या परिधीय कानूनी मुद्दों से संबंधित हैं। यह देखा गया:

ग

"34. जब डी. डी. ए. ने केनेथ बिल्डर्स को सूचित किया कि परियोजना की भूमि "जैसा है, जहां है" के आधार पर उपलब्ध है और यह विकासकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह सभी मंजूरी प्राप्त करे, केवल परियोजना की भूमि से संबंधित भौतिक मुद्दों और वास्तविक निर्माण गतिविधि से संबंधित सहायक या परिधीय कानूनी मुद्दों से संबंधित शर्तें, जैसे कि भवन उप-कानूनों, पर्यावरण मंजूरी आदि का अनुपालन। के नियम और शर्तें

डी.

ई.

"डी. डी. ए. के लिए विद्वान वकील द्वारा जोर दी गई पर्यावरणीय मंजूरी निश्चित रूप से रिज प्रबंधन बोर्ड और इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद के अलावा कानून द्वारा निषिद्ध निर्माण गतिविधि के प्रारंभ तक नहीं फैली। इसके विपरीत, यह

सुनिश्चित करना डी. डी. ए. का दायित्व था कि निर्माण शुरू करने का प्रारंभिक मार्ग स्पष्ट हो, बाकी जिम्मेदारी विकासकर्ता की हो। डी. डी. ए. की अपने विचार से परे एक मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करने में विफलता केनेथ बिल्डर्स के साथ अनुबंध के कार्यान्वयन की नींव पर गई और यही कारण है कि इसके कार्यान्वयन को निराश किया।

च

जी.

35. डी. डी. ए. के विद्वान वकील द्वारा "जैसा है जहाँ है" पर भरोसा

इस संदर्भ में विकास समझौते की अवधारणा के साथ-साथ खंड **6** और **11** गलत है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह मुख्य रूप से स्थल पर शारीरिक समस्याओं से संबंधित है।"

एच.

(जोर दिया गया)

714

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

137. नीलामी खरीदारों द्वारा रघु नाथ पर रिलायंस रखा गया

गुप्ता (ऊपर) और केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (ऊपर) को

यह तर्क देते हुए कि "जैसा है वैसा ही है" भौतिक संपत्ति की एक विशेषता है, जो भूमि के साथ चलने वाले बोझ या शुल्क तक सीमित है, गलत धारणा है। नीलामी खरीदारों द्वारा जिन दोनों मामलों पर भरोसा किया गया था, उनमें विशिष्ट तथ्यों पर निर्णय दिए गए थे। रघु नाथ गुप्ता (उपरोक्त) मामले में यह न्यायालय पार्किंग, रोशनी, सड़कें, पानी और मल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर विचार कर रहा था, लेकिन "जैसा है जहाँ है" के सिद्धांत का अनुप्रयोग केवल संपत्ति की भौतिक विशेषताओं तक ही सीमित नहीं था।

इसके अलावा, केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (ऊपर) में

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि "जैसा है जहाँ है" पर बिक्री की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि नीलामी खरीदार निर्माण के प्रारंभिक प्रारंभ के लिए अनुमति लेने के लिए जिम्मेदार होगा, जो डीडीए का दायित्व था। इस न्यायालय का यह मत कि "यह मुख्य रूप से स्थल पर भौतिक मुद्दों से संबंधित है" विकास समझौते के विशिष्ट खंडों तक सीमित था।

ग

138. इस प्रकार, "जैसा है जहाँ है" या "जैसा है जो आधार है" या "जैसा है जहाँ है, जो कुछ भी है और बिना किसी सहायता के आधार के" अभिव्यक्ति का निहितार्थ संपत्ति की भौतिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व की शर्त और संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी दावे, अधिकार और बकाया की सीमा और स्थिति तक फैला हुआ है, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा नहीं कहा गया हो। इस अभिव्यक्ति का निहितार्थ यह है कि प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता इस बात पर ध्यान देता है कि विक्रेता बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में अनुमति प्राप्त करने या पानी/सेवा शुल्क, बिजली कनेक्शन के लिए बिजली बकाया और स्थानीय अधिकारियों के करों जैसे बकाया के भुगतान के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।

डी.

ई.

च

139. हम जो दृष्टिकोण लेते हैं, वह निर्णयों में समर्थन पाता है

पैरामाउंट पॉलिमर (ऊपर) और श्रीघधा बेवरेजेज में यह न्यायालय

(ऊपर) पैरामाउंट पॉलिमर (उपरोक्त) में, पूर्व मालिक के परिसर को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत "जैसा है, जहां है" के आधार पर बेचा गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक नीलामी खरीदार को एक अज्ञानी पक्षकार नहीं माना जा सकता है और एक उचित जांच ने इसे इस तरह के दायित्व के निर्वाह के नोटिस पर रखा होगा। यह देखा गया: "9. वित्तीय निगम को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले पहले प्रतिवादी ने निश्चित रूप से परिसर का निरीक्षण किया होगा और उसे पता चल सकता था कि परिसर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था और इस जानकारी को ए पर डाल दिया जाना चाहिए था।

जी.

एच.

715

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

बिजली कटौती के कारणों के बारे में उचित पूछताछ से यह जानकारी मिलती है कि उपक्रम का पिछला मालिक या उपभोक्ता चूक में था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने वित्तीय निगम को उसके द्वारा बिक्री का विज्ञापन दिए जाने से पहले ही स्पष्ट रूप से लिखा था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि अपीलार्थी को बिजली शुल्क के लिए 23,695/- की राशि देय थी और उपक्रम को बेचते समय, उस राशि को प्रदान किया जाना था या ध्यान में रखा जाना था। इसलिए, एक विवेकपूर्ण खरीदार के रूप में प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा की गई किसी भी उचित जांच ने उसे इस तरह के दायित्व के निर्वाह के बारे में सूचित किया होगा। बिक्री 'जैसा है, जहां है' के आधार पर भी थी। 140. श्रीघधा बेवरेजेज (उपरोक्त) मामले में, यह न्यायालय वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत नीलामी बिक्री पर विचार कर रहा था। 6 7 न्यायालय ने नीलामी सूचना के खंड 24 और 26 का विश्लेषण किया, जिसमें सभी वैधानिक बकाया के संबंध में "जैसा है वैसा" बिक्री निर्धारित की गई थी और बिजली बकाया सहित किसी भी शुल्क, बोझ और बकाया के लिए अधिकृत अधिकारी को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया था। इसने निष्कर्ष निकाला कि नीलामी खरीदार को "स्पष्ट रूप से नोटिस में रखा गया था" क्योंकि बिजली बकाया सहित विभिन्न खातों के बकाया की मात्रा का एक विशिष्ट उल्लेख था। बिजली बकाया वहन करने के लिए पिछले मालिकों के दायित्व पर जब बिक्री "जैसा है वैसा ही है" और बिजली बकाया के अस्तित्व का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलामी खरीदार परिसर का निरीक्षण करने और सभी मामलों में बकाया राशि प्रदान करने के लिए बाध्य थे। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

ग

डी.

ई.

" 16.2. जहां, विचाराधीन ई-नीलामी सूचना के मामलों की तरह, बिजली बकाया का अस्तित्व, चाहे उसकी मात्रा निर्धारित की गई हो या नहीं, विशेष रूप से खरीदार के दायित्व के रूप में उल्लेख किया गया है और बिक्री "जैसा है वैसा ही है, जो कुछ भी है और बिना आमदनी के" पर है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बिजली बकाया का भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी (खरीदार) पर मौजूद है।"

च

141. निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी संभावित नीलामी खरीदारों को बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्व के बारे में सूचित किया जाता है जब नीलामी बिक्री समझौते में एक उपयुक्त "जैसा है वैसा ही" खंड शामिल किया जाता है। यह इच्छुक

नीलामी खरीदार के लिए है कि वह जिस संपत्ति को खरीदने का प्रस्ताव करता है, उसके संबंध में स्वामित्व, बोझ और लंबित वैधानिक बकाया जैसी परिस्थितियों के बारे में हर तरह से खुद को संतुष्ट करे।सार्वजनिक नीलामी में

जी.

67 "सरफेसी अधिनियम "

एच.

716

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

बिक्री, नीलामी खरीदारों के पास परिसर का निरीक्षण करने और उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने का अवसर होता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या परिसर में बिजली की आपूर्ति की जाती है।बिजली के विच्छेदन के बारे में जानकारी उचित परिश्रम के साथ आसानी से खोजी जा सकती है, जो एक विवेकपूर्ण नीलामी खरीदार को विच्छेदन के कारणों के बारे में उचित पूछताछ पर रखता है।जब किसी परिसर में बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है, तो खरीदार के लिए यह कहना असंभव होगा कि वे बकाया बिजली के अस्तित्व से अनजान थे।

142. कैविएट एम्प्टर के कानूनी सिद्धांत के संदर्भ में, खरीदार का कर्तव्य बन जाता है कि वह उचित परिश्रम करे।एक विक्रेता पेटेंट दोषों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसके बारे में एक खरीदार को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के संदर्भ में वास्तविक या रचनात्मक सूचना है।हालांकि, धारा 55 (1) (ए) के संदर्भ में, इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, विक्रेता संपत्ति में या विक्रेता के स्वामित्व में भौतिक दोषों का खुलासा करने के लिए बाध्य है, जिसके बारे में वह जानता है और जिसे एक खरीदार सामान्य सावधानी के साथ अपने लिए नहीं खोज सकता है।143. "जैसा है जहां है" खंड के प्रभाव की जांच करते समय, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ नीलामी बिक्री को नियंत्रित करने वाले खंडों की शब्दावली को एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग

डी.

जी. आवेदन:व्यक्तिगत मामलों के तथ्य

ई.

144. उपरोक्त विश्लेषण को अलग-अलग मामलों के तथ्यों पर लागू करने से पहले, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक मामले में, किसी न किसी तरह से, आपूर्ति या बिजली आपूर्ति संहिता की शर्तों का अनुप्रयोग शामिल है।शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं कि आपूर्ति या बिजली आपूर्ति संहिता की शर्तों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह तारीख है जिस पर नीलामी खरीदार ने नए कनेक्शन या परिसर में बिजली की आपूर्ति के लिए फिर से कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होता है जब नीलामी खरीदार द्वारा एक नया कनेक्शन या पुनः कनेक्शन मांगा जाता है। पैरामाउंट पॉलिमर (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले में भी इसे दोहराया गया है।इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

च

जी.

"11. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं कि प्रासंगिक तिथि वित्तीय निगम द्वारा पहले प्रतिवादी को उपक्रम की बिक्री की तारीख है।खंड 21-ए का सम्मिलन दिनांक 27 11-2001 के संचार द्वारा प्रसारित किया गया था और इसके बाद ए की धारा 79 (जे) के साथ आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 के संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी की गई थी।

एच.

717

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

वह अधिनियम। पहले उत्तरदाता ने केवल 1-1-2002 पर नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, आवेदन नियम और शर्तों द्वारा शासित होगा, जिसमें 27-11-2001 पर डाला गया शब्द भी शामिल है, जैसा कि बाद में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।

उस ओर से 27-2-2002 पर दायर रिट याचिका में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि पहले प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन खंड 21-ए thereof. On सहित आपूर्ति के संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित नहीं था, जैसा कि उप-खंड (बी) और (सी) के विशेष संदर्भ के साथ जोड़े गए आपूर्ति के नियमों और शर्तों के खंड 21-ए की हमारी व्याख्या, हमारा विचार है कि उक्त उप-खंड स्पष्ट रूप से पहले प्रतिवादी पर लागू होते हैं जब उसने 1-1-2002 पर परिसर के लिए नए कनेक्शन की मांग करते हुए आवेदन किया था।” (जोर दिया गया) उन्नीस मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित तरीके से अपीलों का फैसला करते हैं:

ग

डी.

आई. केरल

145. के. एस. ई. बी. ने 1948 के अधिनियम की धारा 49 और धारा 79 (जे) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों से संबंधित नियम बनाए। ये विनियम 15 दिसंबर 1989 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और 1 जनवरी 1990 से लागू हुए थे। खंड 15 सेवा कनेक्शन के लिए समझौते से संबंधित है। प्रासंगिक खंड, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, नीचे निकाला गया है:

ई.

“15. सेवा कनेक्शन के लिए समझौता

च

15((ग): जब परिसर के स्वामित्व या अधिभोग के अधिकार का हस्तांतरण होता है तो पंजीकृत उपभोक्ता 7 दिनों के भीतर संबंधित सहायक अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता को परिसर के अधिभोग के अधिकार के हस्तांतरण की सूचना देगा। इस तरह की सूचना मिलने पर सेवा काट दी जाएगी। यदि हस्तांतरणकर्ता सेवा कनेक्शन का आनंद लेना चाहता है, तो वह बोर्ड को बकाया का भुगतान करेगा और 15 दिनों के भीतर सेवा कनेक्शन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा और नए समझौते को निष्पादित करेगा और अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करेगा। ऐसे मामलों में पिछले नंबर को रद्द करते हुए नया उपभोक्ता नंबर आवंटित किया जाएगा।

जी.

एच.

718

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

15((घ)):उपभोक्ता से बोर्ड को देय सभी राशि उपभोक्ता की परिसंपत्तियों पर पहला शुल्क होगा।जुर्माने सहित सभी देय राशि का भुगतान भूमि पर देय सार्वजनिक राजस्व के रूप में किया जाएगा।

15(ई):किसी भी परिसर में पुनर्संयोजन या नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, जब तक कि भुगतान लंबित होने पर बोर्ड के किसी भी खाते में बकाया है, जब तक कि जुर्माना, यदि कोई हो, सहित बकाया का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है (यदि नया मालिक/अधिभोगकर्ता/आवंटनकर्ता पिछले उपभोक्ता से देय राशि भेजता है, तो बोर्ड इस बात के आधार पर पुनः कनेक्शन या नया कनेक्शन प्रदान करेगा कि क्या सेवा डिस्कनेक्ट/विघटित रहती है, जैसा भी मामला हो।यदि बोर्ड आर. आर. कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही के माध्यम से पिछले उपभोक्ता से पूरा बकाया प्राप्त करता है तो इस तरह से प्रेषित राशि को पिछले उपभोक्ता के बकाया के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।लेकिन उसके द्वारा पहले से ही प्रेषित राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा) "146. खंड 15 (सी) के संदर्भ में, जब परिसर के स्वामित्व या अधिभोग के अधिकार का हस्तांतरण होता है, तो पंजीकृत उपभोक्ता सात दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को परिसर के अधिभोग के अधिकार के हस्तांतरण की सूचना देगा। इस तरह की सूचना मिलने पर सेवा काट दी जाएगी।यदि हस्तांतरणकर्ता सेवा कनेक्शन चाहता है, तो वह बकाया का भुगतान करेगा और सेवा कनेक्शन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा।खंड 15 (डी) के संदर्भ में, उपभोक्ता से के. एस. ई. बी. को सभी बकाया उपभोक्ता की परिसंपत्तियों पर पहला शुल्क होगा।खंड 15 (ई) के संदर्भ में, किसी भी परिसर में एक नया कनेक्शन या पुनर्संयोजन नहीं दिया जाएगा जहां किसी भी खाते पर बकाया है जब तक कि उन्हें पहले से मंजूरी नहीं दी जाती है।

ग

डी.

ई.

च

147. खंड 15 (ई) की वैधता को सूरज बनाम के. एस. ई. बी. मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था। 68 उच्च न्यायालय ने उक्त विनियम की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा कि पिछले मालिक या कब्जाधारक के बकाया भुगतान के बिना बोर्ड को उसी परिसर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:

जी.

“8. विनियम बिजली की आपूर्ति के मामले में नीलामी खरीदार और अन्य के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।विनियम 15 (डी) और (ई) को एक उद्देश्य के साथ शामिल किया गया है, या अन्यथा

एच.

68 2005 (3) के. एल. टी 856 ए

719

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

पिछले उपभोक्ताओं के साथ-साथ परिसंपत्तियों से राशि की वसूली करने के बोर्ड के अधिकार को उसी समय प्रभावी रूप से विफल किया जा सकता है जब बोर्ड को उसी परिसर में बिजली प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

विनियमन 15 (ई) का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है, जो सार्वजनिक संपत्ति को बचाना है ताकि समुदाय के सामान्य हित को कम किया जा सके।एक बार बिजली काट दिए जाने और उपकरणों को नष्ट कर दिए जाने के बाद, किसी तीसरे पक्ष के कहने पर बोर्ड को उसी परिसर में बिजली कनेक्शन देने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण है, जो सार्वजनिक हित में नहीं होगा, खासकर जब बिजली को सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है।इसके अलावा

याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में विनियम 15 (डी) और 15 (ई) की वैधता को भी चुनौती नहीं दी है।"

(जोर दिया गया) 148। दो मामले-के. सी. निनान बनाम के. एस. ई. बी. 69 और के. जे. डेनिस बनाम के. एस. ई. बी., 70 केरल राज्य से उत्पन्न होते हैं। इन दोनों मामलों में, केरल उच्च न्यायालय ने खंड 15 (ई) की वैधता को बरकरार रखा और निर्देश दिया कि उन परिसरों के लिए नए बिजली कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए जहां बकाया है, नीलामी खरीदारों को उक्त शर्त के अनुपालन में पिछले उपभोक्ता के बकाया का भुगतान करना होगा।

डी.

ई.

वस्तु **101.9: के. जे. डेनिस बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड; 2004** की सिविल अपील **2108**

149. के. एस. ई. बी. ने 1992 में अवैतनिक बिजली शुल्क के कारण पर्लाइट वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का बिजली कनेक्शन काट दिया। इस बीच, केरल उच्च न्यायालय ने बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, 71 के तहत कंपनी को बंद करने का आदेश दिया क्योंकि मूल मालिक सिंडिकेट बैंक और केरल वित्तीय निगम को अपने बकाया का भुगतान करने में विफल रहा। 20 अप्रैल 1997 को, के. एस. ई. बी. ने आधिकारिक परिसमापक को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें बिजली शुल्क के बकाया और दंडात्मक ब्याज के रूप में 66 लाख रुपये के भुगतान की मांग की गई। 27 जनवरी 1999 को, पर्लाइट वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की संपत्तियों को खरीदने के लिए अपीलार्थी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 4 मार्च 1999 को केरल उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई बिक्री की शर्तों में प्रावधान किया गया है कि:

च

जी.

69 CA 2109-2110/2004 70 CA 2108/2004 71 "SICA"

एच.

720

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

"7. सामान्य नियम और शर्तें:- ***

(ग) परिसंपत्तियों को "जैसा है और जो कुछ भी है" की शर्त पर बेचा जाता है।

(घ) परिसंपत्तियों को इस धारणा पर बेचा जाता है कि निविदाकर्ता ने परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया है, जानते हैं कि वे किस लिए निविदा दे रहे हैं, क्या उन्होंने निरीक्षण किया है या नहीं और 'कैविएट एम्प्टर' का सिद्धांत लागू होगा।"

150. अपीलार्थी ने 4 जून 1999 के एक पत्र द्वारा संपत्ति में बिजली कनेक्शन के लिए तारों के लिए के. एस. ई. बी. से अनुमति मांगी। पूर्ववर्ती मालिक के बकाया के कारण के. एस. ई. बी. द्वारा तारों की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था और यह कहा गया था कि यदि अपीलकर्ता पिछले उपभोक्ता से देय राशि भेजने के लिए तैयार है तो एक नया कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

151. मध्यावधि में, के. एस. ई. बी. ने कंपनी अदालत के समक्ष एक कंपनी याचिका 72 में दावा याचिका दायर की, जिसमें पर्लाइट वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड से 86,54,711 की राशि का दावा किया गया था, जो परिसमापन में थी। दावा याचिका को 63 लाख रुपये में स्वीकार किया गया था। अपीलार्थी ने एक कंपनी आवेदन 73 दायर किया जिसमें के. एस. ई. बी. को नीलामी खरीदार द्वारा बिजली शुल्क के बकाया भुगतान पर जोर नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई, जो परिसमापन में कंपनी से देय थे। 18 सितंबर 2000 को, एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि के. एस. ई. बी. कनेक्शन दिए जाने से पहले बकाया राशि का भुगतान करने पर जोर दे सकता है। आदेश से व्यथित, अपीलार्थी ने खंड 15 (ई) की वैधता को उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 18 जुलाई 2001 को डिवीजन बेंच ने चुनौती को खारिज कर दिया। अंत में, 14 सितंबर 2001 को, विवादित आदेश पारित किया गया जिसमें डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई।

डी.

ई.

च

152. 18 जुलाई 2001 के अपने फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने खंड 15 (ई) की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि के. एस. ई. बी. उस परिसर को फिर से जोड़ने या नया कनेक्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, जहां बोर्ड के किसी भी खाते में बकाया है, जब तक कि जुर्माने सहित बकाया का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है। इसने पाया कि धारा 79 (जे) के साथ पढ़ा जाता है

जी.

72 1994 की कंपनी याचिका 15

73 1994 क कंपनी याचिका 15 मे 1999 क कंपनी आवेदन 349 क

एच.

721

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

1948 के अधिनियम की धारा 49 ने बोर्ड को बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले विनियम बनाने के लिए काफी छूट दी, और बोर्ड ऐसे नियमों और शर्तों पर बिजली की आपूर्ति कर सकता है जो वह उचित समझता है, यानी खंड 15 (ई) के अनुसार। न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही 1910 के अधिनियम की अनुसूची के खंड VI के अनुसार एक संभावित उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया हो, बोर्ड बिजली की सुरक्षा के लिए उचित विनियम निर्धारित करने की शक्ति रखता है, जो सार्वजनिक संपत्ति है और बोर्ड के सर्वोत्तम हित में कार्रवाई करता है। न्यायालय ने अपने निर्णय तक पहुँचने के लिए ए. रामचंद्रन बनाम के. एस. ई. बी. 74 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

ग

153. पुनरीक्षण याचिका में 14 सितंबर 2001 के विवादित फैसले में, अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि कार्यवाहियों को समाप्त करने में खंड 15 (ई) का भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि जिस तरह से नया व्यक्ति संपत्ति का मालिक, आवंटनकर्ता या अधिभोगकर्ता बना, वह महत्वहीन है। अंत में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि बिजली बोर्ड पिछले मालिक के खिलाफ समापन कार्यवाही से पहले एक सुरक्षित लेनदार के रूप में देय राशि की वसूली करने का प्रयास कर रहा था, खंड 15 (ई) की प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

डी.

154. इस न्यायालय द्वारा 25 जनवरी 2002 को नोटिस जारी किया गया था। 28 फरवरी 2007 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने पक्षों को एक समझौते पर बातचीत करने और दोनों पक्षों के लिए सहमत राशि की वसूली के लिए एक सूत्र पर पहुंचने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

ई.

“वर्तमान मामले में इक्विटी को संतुलित करना एक नाजुक काम होगा, और जिस भी तरह से हम इस मामले का फैसला करते हैं, हारने वाले पक्ष को लग सकता है कि उसे न्याय से वंचित कर दिया गया है। साथ ही, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अपीलकर्ताओं ने भारी निवेश किया है जैसा कि उन्होंने दावा किया है, और ऐसे निवेश पर केवल ब्याज घटक ही अपीलार्थी के खिलाफ एक बड़ा दायित्व पैदा कर सकता है। दूसरी ओर, यदि उद्योग काम करना शुरू कर देता है, तो शायद बिजली बोर्ड को भी लाभ होगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमेबाजी करने के बजाय, यदि दोनों पक्ष विवाद को सुलझा सकते थे, तो दोनों को काफी हद तक लाभ होता।”

च

जी.

लेकिन, कोई समझौता नहीं हो सका।

74 2000 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 75

एच.

722

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

155. हमारा विचार है कि केरल उच्च न्यायालय खंड 15 (ई) की वैधता को बरकरार रखने में सही था। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों का खंड 15, जो चरित्र में वैधानिक है, स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि बोर्ड उस परिसर में फिर से कनेक्शन या नया कनेक्शन देने के लिए बाध्य नहीं है जहां पिछले उपभोक्ता से बिजली शुल्क का कोई बकाया है, जब तक कि नए मालिक/अधिभोगकर्ता/आवंटनकर्ता द्वारा जुर्माना सहित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में नीलामी बिक्री की शर्तों में यह प्रावधान किया गया है कि परिसंपत्तियों को "जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा गया था। स्पष्ट तथ्यों के आलोक में, प्रत्यर्थी अपीलार्थी-खरीदार से बकाया बिजली की मांग करने के अपने अधिकार के भीतर होगा। चूंकि के. एस. ई. बी. की दावा याचिका रुपये 63,94,298 के लिए स्वीकार की गई थी, इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रेषित राशि, यदि कोई हो, जिसे कनेक्शन दिया गया है, खंड 15 (ई) के अनुसार समायोजित की जाएगी।

ग

156. हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है।

डी.

मद 101: के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड; 2004 की सिविल अपील सं. 2109-2110

157. अपीलार्थी ने 31 अक्टूबर 1989 को एक अदालती नीलामी में यूनाइटेड इंडस्ट्रीज कोचीन लिमिटेड की संपत्ति खरीदी। परिसर का बिजली कनेक्शन पहले 1980 में काट दिया गया था और बिजली शुल्क का भुगतान न करने के कारण 1985 में बिजली आपूर्ति लाइन को तोड़ दिया गया था। 1 दिसंबर 1989 को, अपीलार्थी ने कथित तौर पर खरीदे गए परिसर में बिजली कनेक्शन के लिए के. एस. ई. बी. को आवेदन किया। इसके बाद, 1 जनवरी 1990 को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों का खंड 15 लागू किया गया। 12 जून 1990 को, के. एस. ई. बी. ने अपीलार्थी को एक संचार भेजा, जिसमें बिजली कनेक्शन देने

से इनकार कर दिया गया, जब तक कि अपीलार्थी परिसर की बिजली के बकाया का भुगतान नहीं करता। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने स्थायी विद्युत कनेक्शन की मांग करते हुए और आपूर्ति की शर्तों के खंड 15 (ई) को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

ई.

च

158. उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी 2003 के फैसले में के. जे. डेनिस (ऊपर) और ए. रामचंद्रन (ऊपर) पर भरोसा किया और नीलामी खरीदार की के. एस. ई. बी. को पिछले मालिक के बकाया का भुगतान किए बिना बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने 13 फरवरी 2003 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की। यह अपीलार्थी का तर्क था कि रामचंद्रन (ऊपर) और ए में निर्णय

जी.

एच.

723

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

के. जे. डेनिस (ऊपर) मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि "समीक्षाधीन निर्णय इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना दिया गया था कि शर्त 15 (ई) को केवल 1.1.1990 से प्रभावी विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों में शामिल किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने अदालत की नीलामी में 31.10.1989 पर संपत्ति खरीदी थी और बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन 1.12.1989 पर किया गया था।" अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रामचंद्रन (ऊपर) में उच्च न्यायालय के फैसले ने ईशा मार्बल्स (ऊपर) में अनुपात को ध्यान में रखा और उसके बाद प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई को बरकरार रखा।

159. इस न्यायालय ने 7 जनवरी 2004 को नोटिस जारी किया और 2 अप्रैल 2004 को छुट्टी दे दी। वसूली की कार्यवाही पर 5 मई 2006 को रोक लगा दी गई थी।

ग

160. अपीलार्थी ने लिखित प्रस्तुतियों के दौरान प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित विनियमन संभावित रूप से लागू होगा क्योंकि एक प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए अधीनस्थ विधान का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है जब तक कि संबंधित कानून में स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा नियम बनाने की शक्ति इस संबंध में शक्ति प्रदान नहीं करती है। 75 यह आगे कहा गया कि अपीलार्थी ने आपूर्ति की शर्तें लागू होने से पहले 1 दिसंबर 1989 को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। यह आग्रह किया गया है कि किसी भी मौजूदा वैधानिक विनियमों के अभाव में, अपीलार्थी को बिजली आपूर्ति की पूर्व शर्त के रूप में पूर्व उपभोक्ता द्वारा किए गए पिछले बकाया को चुकाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 161. आपूर्ति की शर्तों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह तारीख है जिस पर नीलामी खरीदार परिसर के लिए बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, न कि उपक्रम की खरीद की तारीख। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने की तारीख को चूक की गई राशि की वसूली के मुद्दे को नियंत्रित करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान था।

डी.

ई.

च

162. प्रत्यर्थी ने अपने जवाबी हलफनामे में बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन की तारीख के तथ्य पर विवाद उठाया है। प्रतिवादी प्रस्तुत करता है कि अदालत की बिक्री 31 अक्टूबर 1989 को आयोजित की गई थी, जिसकी पुष्टि 22 जनवरी 1990 को की गई थी और बिक्री प्रमाण पत्र पर 6 अप्रैल 1990 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह तर्क दिया जाता है कि इन परिस्थितियों में, यह संभावना नहीं है कि अपीलार्थी को प्राप्त हुआ होगा

जी.

75 मध्य प्रदेश राज्य बनाम टीकमदास, (1975) 2 एस. सी. सी. 100

एच.

724

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

परिसर का कब्जा या 1 दिसंबर 1989 को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया होगा, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है।

163. हालांकि, किसी भी पक्ष ने बिजली कनेक्शन देने के लिए आवेदन की तारीख को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री जमा नहीं की है। भौतिक तथ्यात्मक विवाद और अभिलेख पर अपर्याप्त साक्ष्य को देखते हुए, हम यह निर्धारित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं कि क्या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों की शर्त 15 अपीलार्थी के मामले में लागू होगी, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो इस निर्णय में निर्धारित किए गए हैं।

II. महाराष्ट्र

ग

164. महाराष्ट्र राज्य में, जिन नियमों और शर्तों के तहत एम. एस. ई. बी. ने विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की थी, वे एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तों में प्रदान किए गए थे। एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तों को 1 जनवरी 1976 से प्रभावी बनाया गया था। एम. एस. ई. बी. ने विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, बिलों के भुगतान, विद्युत ऊर्जा के प्रतिकूल उपयोग के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तों के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 में असाइनमेंट और समझौते के हस्तांतरण का प्रावधान है। 165. नई औद्योगिक विकास नीति 1993 के आलोक में, जिसका उद्देश्य बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करना था, एमएसईबी ने 18 जून 1993 को परिपत्र 518 जारी किया, जिसका शीर्षक था "बंद और बीमार औद्योगिक इकाई को बिजली की आपूर्ति"। परिपत्र 518 का उद्देश्य राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1957 की धारा 29 के तहत संभावित उद्यमियों को बीमार औद्योगिक इकाइयों को संभालने के लिए प्रोत्साहित करना था। परिपत्र ने नीलामी में बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों को खरीदने वाले संभावित मालिकों को दो विकल्पों के साथ प्रस्तुत किया-या तो बिजली आपूर्ति को फिर से जोड़ने के लिए न्यूनतम शुल्क सहित बकाया का भुगतान करें, या पिछले मालिक के बकाया के लिए उत्तरदायी हुए बिना आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नए कनेक्शन के लिए आवेदन करें। परिपत्र में आगे कहा गया है कि एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 (बी) 1 अप्रैल 1993 से संभावित उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी।

डी.

ई.

च

जी.

166. 19 दिसंबर 1998 के परिपत्र 607 द्वारा परिपत्र को वापस ले लिया गया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि बिजली बोर्ड के बकाया भुगतान के बाद ही पुनः कनेक्शन या नया कनेक्शन जारी किया जाएगा। यह परिपत्र आपूर्ति की शर्तों की शर्त 23 (बी) से निकला है, जैसा कि एमएसईबी द्वारा तैयार किया गया है। इस परिपत्र को तत्काल और संभावित प्रभाव से लागू किया गया था।

एच.

725

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

167. बॉम्बे उच्च न्यायालय के विवादित फैसलों के आलोक में, जो हमारे समक्ष अपील में हैं, एमएसईबी ने 25 सितंबर 2003 के अपने परिपत्र 684 द्वारा बंद/बीमार औद्योगिक इकाइयों के नीलामी खरीदारों को 18 जून 1993 के परिपत्र 518 द्वारा निर्धारित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करने की अनुमति दी। हालाँकि, आने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक वचन की आवश्यकता थी कि वे पिछले मालिकों के बकाया का भुगतान करने के लिए बिना शर्त सहमत हों, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने एमएसईबी के पक्ष में निर्णय लिया हो।

168. 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद, महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 को 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत बनाया गया था। ये नियम 20 जनवरी 2005 से लागू हुए और संभावित रूप से लागू होते हैं। महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता के विनियम 10.5 में प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारी को देय बकाया संपत्ति पर शुल्क है और एक वैधानिक प्रभाव के रूप में, बिजली बकाया के भुगतान का दायित्व परिसर के नए मालिक/अधिभोगियों को दिया जाता है, हालांकि एक निश्चित समय प्रतिबंध के लिए। विनियम 10.5 निम्नलिखित प्रावधान करता है: “ 10.5: वितरण अनुज्ञप्तिधारक के कारण बिजली के लिए कोई शुल्क या बिजली के लिए शुल्क के अलावा कोई अन्य राशि, जो किसी मृत उपभोक्ता या किसी भी परिसर के पूर्व मालिक/अधिभोगकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की जाती है, कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों को प्रेषित या परिसर के नए मालिक/अधिभोगकर्ता को हस्तांतरित परिसर पर शुल्क होगा, जैसा भी मामला हो, और वही शुल्क वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ऐसे कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों या परिसर के नए मालिक/अधिभोगियों से, जैसा भी मामला हो, वसूल किया जाएगा।

ग

डी.

ई.

बशर्ते कि, किसी कानूनी उत्तराधिकारी को कनेक्शन के हस्तांतरण के मामले को छोड़कर, इस विनियमन 10.5 के तहत हस्तांतरित देनदारियां ऐसे परिसरों में आपूर्ति की गई बिजली के लिए अवैतनिक शुल्क की अधिकतम छह महीने की अवधि तक सीमित होंगी।

च

169. वर्तमान में, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और बिजली की गुणवत्ता सहित वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन के अन्य मानक) विनियम 2021 76 को महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 को निरस्त करते हुए अधिनियमित किया गया है। 2021 के विनियमों के खंड 12 में दोहराया गया है कि बिजली के लिए कोई भी अवैतनिक शुल्क परिसर में एक शुल्क होगा।

जी.

76 “2021 नियम ”

एच.

170. महाराष्ट्र राज्य से, बॉम्बे उच्च न्यायालय के छह निर्णय हैं जो हमारे समक्ष अपील में हैं।

169. अपीलार्थी-बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत भास्मे ने निम्नलिखित सामान्य कानूनी प्रस्तुतियों का आग्रह किया: क. एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तें, जो उस समय 1910 के अधिनियम और 1948 के अधिनियम के तहत प्रचलित थीं, वैधानिक प्रकृति की हैं, जैसा कि -

हैदराबाद वनस्पति (ऊपर) में यह न्यायालय। शर्तें

आपूर्ति के अलावा हैं और वसूली के अन्य तरीकों के बदले में नहीं हैं;

ख. एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तें उपभोक्ता और बिजली कंपनी के बीच किए गए मानक समझौते का एक हिस्सा हैं। विद्युत बोर्ड और उपभोक्ता के बीच मानक समझौते के खंड 14 में समझौते के एक भाग के रूप में आपूर्ति की शर्तों को शामिल किया गया है।

ग

ग. ईशा मार्बल्स (ऊपर) के फैसले पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ईशा मार्बल्स (ऊपर) का मामला तथ्यों पर अलग है। घ. खंड 2 में एस. आई. सी. ओ. एम. की बिक्री की सामान्य नीलामी शर्तों में कहा गया है कि बिक्री "जैसा है और क्या है" के आधार पर है। नीलामी खरीदारों को बोलियां आमंत्रित करते समय मानक नीलामी घोषणा (खंड 6) को शामिल करने के कारण पिछले बिजली बकाया के लिए उनके दायित्व के बारे में सूचित किया गया था। ई. महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के विनियम 10.5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी अवैतनिक बिजली बकाया हस्तांतरित परिसर पर एक शुल्क होगा; और

डी.

ई.

च

च. सभी छह मामले 2005 से पहले की अवधि से संबंधित हैं, यानी महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अधिनियमन से पहले। 1976 की एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तें 2005 में महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता के अधिनियमन तक जारी रहीं।

जी.

171. महाराष्ट्र में, विद्युत उपयोगिताओं का बकाया राशि की मांग करने का अधिकार अलग-अलग समय अवधि के प्रावधानों से पता लगाया जा सकता है:

ए। 10 जून 2003 को 2003 के अधिनियम के अधिनियमन तक: द.

शासी कानून 1910 अधिनियम और 1948 अधिनियम हैं। एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तें ए की धारा 49 के तहत तैयार की गई थीं।

एच.

1948 एक्ट करें। एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तें जो 1 जनवरी 1976 से प्रभावी की गई थीं, लागू होंगी।

बी। 10 जून 2003 से 20 जनवरी 2005 तक: प्रावधान

2003 का अधिनियम 10 जून 2003 से लागू किया गया था। 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद 1910 के अधिनियम और 1948 को निरस्त कर दिया गया। महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 20 जनवरी 2005 से लागू हुई। मध्यावधि में, एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तें तब तक लागू रहतीं जब तक कि वे 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह निम्नलिखित कारणों से होता है:

ग

आई. 2003 के अधिनियम की धारा 185 (2) (ए) के आधार पर, निरस्त कानून के तहत किसी भी नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या नोटिस आदि सहित कुछ भी किया गया या की गई या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई कार्रवाई के बावजूद, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह माना जाएगा कि इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया है या किया गया है। धारा 185 (2) (5) में आगे यह प्रावधान है कि सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 धारा 185 (2) में निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में निर्धारित मामलों के संबंध में लागू होगी।

डी.

ई.

ii. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के विनियम 19 (1) में प्रावधान है कि आपूर्ति के कोई भी नियम और शर्तें जो महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, उन तारीख से अमान्य मानी जाएंगी जिस दिन ये विनियम लागू होते हैं; और

च

ग. 20 जनवरी 2005 से 2021 के अधिनियमन तक

नियम: महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005, जो 20 जनवरी 2005 से लागू हुई, लागू होगी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 किसी विशेष मामले के तथ्यों को नियंत्रित करेगी, प्रासंगिक तिथि वह होगी जब नीलामी खरीदार ने बिजली बोर्ड से बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था।

जी.

172. महाराष्ट्र से शुरू हुए छह मामलों में, प्रतिवादी नीलामी के सफल खरीदार थे जिन्होंने अदालत में परिसर खरीदा था

एच.

728

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

नीलामी बिक्री। अपीलकर्ता-बोर्ड ने एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 पर भरोसा किया ताकि एक नया बिजली कनेक्शन प्रदान करने से पहले पूर्ववर्ती उपभोक्ता के बिजली बकाया का भुगतान करने की पूर्व शर्त लागू की जा सके। उच्च न्यायालय ने सभी मामलों में अपीलकर्ता-बोर्ड को बकाया भुगतान पर जोर दिए बिना उत्तरदाताओं को फिर से संपर्क या नया संपर्क प्रदान करने का निर्देश दिया।

173. ये विवादित निर्णय शर्त 23 की प्रयोज्यता और दायरे पर एक सामान्य सवाल उठाते हैं। यह न्यायालय मामलों के विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स में जाने से पहले, आपूर्ति की एम. एस. ई. बी. शर्तों की शर्त 23 की प्रयोज्यता और इसकी व्याख्या पर समग्र तर्क पर विचार करेगा।

ग

174. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुपर एंड

स्टेनलेस हाई अलॉयज लिमिटेड, 77 बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर 1998 के विवादित परिपत्र को अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण रद्द करने के लिए ईशा मार्बल्स (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया क्योंकि इसे 1910 के अधिनियम की धारा 24 के तहत बिजली बोर्ड की शक्तियों से परे माना गया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आपूर्ति का अनुबंध केवल बिजली बोर्ड और पिछले उपभोक्ता के बीच था, और चूंकि बाद वाला खरीदार एक तीसरा पक्ष था, इसलिए इसे पूर्व उपभोक्ता की पिछली देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

डी.

175. सुपुर्द में।इंग.महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम

ई.

मेसर्स उमंग एंटरप्राइजेज, 78 उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-बोर्ड के तर्क को अस्वीकार करने के लिए ईशा मार्बल्स (ऊपर) और गुजरात इंस (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले उपभोक्ता के पिछले बकाया की निकासी पर जोर दिए बिना, अपीलार्थी को परिसर में बिजली कनेक्शन देने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने अपने तर्क में एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तों और नीलामी खरीदारों के दायित्व पर शर्त 23 के आयात का उल्लेख नहीं किया।

च

176. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम एक्टो स्पिनर्स, 79 और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

जी.

बनाम मेसर्स जिया आयरन स्टोर, 80 उच्च न्यायालय ने एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 के उद्देश्य पर विचार किया। यह निष्कर्ष निकाला कि

77 2005 की सिविल अपील 5312-5313 2005 की 78 सिविल अपील संख्या 5314 2005 की 79 सिविल अपील संख्या 6587 2005 की 80 एसएलपी (सिविल) संख्या 6068 2006 ए

एच.

729

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

शर्त 23 अनैच्छिक स्थानान्तरणों पर लागू नहीं थी, जैसे कि कानून के संचालन या किसी सक्षम अदालत की डिक्री के अनुसरण में। तदनुसार, इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी-खरीदारों को नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में पूर्व मालिकों के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

177. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई 2005 को एक्टो स्पिनर्स में दिए गए विवादित फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित कारणों से सहायता की:

ए। शर्त 23 (बी) एक अनैच्छिक हस्तांतरण को संदर्भित नहीं करती है, हालांकि यह मालिक की मृत्यु के कारण स्वैच्छिक हस्तांतरण या हस्तांतरण को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति में "उत्तराधिकारी" शब्द "कोई भी व्यक्ति जो उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, हस्तांतरणकर्ता, असाइनी या चूक करने वाले उपभोक्ता का उत्तराधिकारी होने का दावा करता है" को एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करके समझना होगा। तदनुसार, "उत्तराधिकारी" शब्द से पहले के शब्द स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ का खुलासा करते हैं जो स्वैच्छिक हस्तांतरण या मालिक की मृत्यु के कारण संपत्ति का अधिकार प्राप्त करता है; और

ग

डी.

बी। सार्वजनिक नीलामी में खरीदी गई संपत्ति का हस्तांतरण मालिक द्वारा एक अनैच्छिक हस्तांतरण है। इसलिए, शर्त 23 सार्वजनिक नीलामी या गैर-स्वैच्छिक हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके से अधिकार प्राप्त करने के कारण पूर्ववर्ती उपभोक्ता के परिसर में रहने वाले हस्तांतरणकर्ता पर कोई दायित्व नहीं लगाती है। 178. बिजली बोर्ड दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करने पर बिजली के पुनः कनेक्शन या नए कनेक्शन की मांग करने वाली संपत्ति के खरीदार से परिसर में बिजली की आपूर्ति के संबंध में पूर्व चूक करने वाले उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि की मांग कर सकता है:

ई.

च

ए। कानून में एक स्पष्ट प्रावधान मौजूद है जो यह प्रदान करता है कि बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क का गठन करता है। एक व्यक्ति के हाथों में संपत्ति के खिलाफ वैधानिक आरोप लागू करने के लिए, जिसे ऐसी संपत्ति विचार के लिए हस्तांतरित की गई है, हस्तांतरणकर्ता के पास आरोप की वास्तविक या रचनात्मक सूचना होनी चाहिए; और

जी.

बी। वैधानिक विनियम या आपूर्ति के नियम और शर्तें जो वैधानिक हैं, बिजली के आपूर्तिकर्ता को ऐसी मांग करने के लिए अधिकृत करती हैं।

एच.

730

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

179. सामान्य कानून में, बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क का गठन नहीं करता है। 1948 के अधिनियम के साथ पठित 1910 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत, बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क नहीं लगाता है। हमारे समक्ष 1948 के अधिनियम के साथ पठित 1910 के अधिनियम द्वारा शासित मामलों में बिजली बोर्ड के पक्ष में बिजली बकाया के भुगतान के लिए संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। बिजली बकाया का बकाया परिसर के खिलाफ नहीं लगाया गया था, बल्कि पूर्व उपभोक्ता के खिलाफ लगाया गया था।

180. हमारी राय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ईशा मार्बल्स (ऊपर) में अनुपात की व्याख्या सुपर और स्टेनलेस में की है।

हाय अलॉयज लिमिटेड और मेसर्स उमंग एंटरप्राइजेज गलत हैं क्योंकि

ग

यह कारण कि उच्च न्यायालय इस बात की जांच करने में विफल रहा कि क्या कोई वैधानिक विनियमन या आपूर्ति के वैधानिक नियम और शर्तें मौजूद हैं जो किसी तीसरे व्यक्ति के दायित्व से संबंधित हैं जो पूर्ववर्ती उपभोक्ता की संपत्ति का अधिग्रहण करता है।

181. महाराष्ट्र से संबंधित मामलों में, एमएसईबी या उसके उत्तराधिकारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने आपूर्ति की वैधानिक शर्तों की शर्त 23 पर विशिष्ट निर्भरता रखी। वैधानिक प्रावधानों में शर्त 23 एकमात्र खंड है जो उस व्यक्ति के दायित्व से संबंधित है जो उसके तहत निर्दिष्ट परिस्थितियों में पूर्व उपभोक्ता की संपत्ति का अधिग्रहण करता है। 19 दिसंबर 1998 का परिपत्र 607 आपूर्ति की शर्तों की शर्त 23 (बी) से निकला है। ईशा मार्बल्स (ऊपर) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी जिसका प्रभाव शर्त 23 के समान था।

डी.

ई.

182. हैदराबाद वनस्पति (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1948 के अधिनियम की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित आंध्र प्रदेश राज्य में आपूर्ति की शर्तें वैधानिक हैं। न्यायालय ने कहा कि 1948 के अधिनियम की धारा 79 (जे) के तहत कोई विनियमन नहीं बनाया गया है।

च

183. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-बोर्ड ने विद्युत आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपूर्ति की एम. एस. ई. बी. शर्तें तैयार कीं। तदनुसार, एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तें वैधानिक प्रकृति की हैं।

जी.

184. जब विद्युत उपयोगिताओं द्वारा किसी तीसरे पक्ष पर पूर्ववर्ती उपभोक्ता के बकाया भुगतान के दायित्व को लागू करने के लिए एक वैधानिक बल और प्रभाव वाले प्रावधान पर भरोसा किया जाता है, तो यह ए के लिए होता है।

एच.

731

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उक्त वैधानिक प्रावधान लागू होता है

उसके सामने मामले के तथ्य। विशेष अधिकारी, वाणिज्य, उड़ीसा की उत्तर पूर्वी विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम रघुनाथ पेपर

मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 81 इस न्यायालय ने कहा कि उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग वितरण (आपूर्ति की शर्तें), संहिता, 2004 का विनियमन 13 (10) (बी) मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था क्योंकि नीलामी खरीदार ने नए कनेक्शन के लिए अनुरोध किया था, जबकि संबंधित विनियमन के संदर्भ में, पिछले बकाया को केवल पूर्ववर्ती उपभोक्ता के नाम से पुनः कनेक्शन या सेवा कनेक्शन के हस्तांतरण के संबंध में ही चुकाया जाना था।

185. शर्त 23 की प्रयोज्यता पर अपीलार्थी का प्रस्तुत करना उस व्यक्ति के दायित्व के संबंध में शर्त 23 के अर्थ और दायरे पर निर्भर करता है जो पूर्व उपभोक्ता के परिसर का नया मालिक या अधिभोगकर्ता बन जाता है, जिसे बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। शर्त 23 नीचे दी गई है:

ग

“खंड 23: समझौते का समनुदेशन या हस्तांतरण

डी.

क) उपभोक्ता बोर्ड की लिखित पूर्व सहमति के बिना, बोर्ड के साथ अपने समझौते के लाभ के साथ असाइन, ट्रांसफर या भाग नहीं करेगा और न ही उपभोक्ता किसी भी तरह से इसके तहत कोई आंशिक या अलग ब्याज देगा या बनाएगा।

बी) एक उपभोक्ता जो उपरोक्त शर्त 23 (ए) का उल्लंघन करता है और बोर्ड को ऊर्जा के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने या बोर्ड के साथ प्रतिभूति जमा या मुआवजे की राशि जमा करने की उपेक्षा करता है और ऐसे उपभोक्ता की आपूर्ति भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 24 के तहत या शर्त संख्या के तहत काट दी जाती है। 31 (ए)

ई.

इन शर्तों में से मर जाता है, या हस्तांतरण, असाइन या अन्यथा उपक्रम या परिसर का वितरण जिस पर ऊर्जा है

च

उपभोक्ता को आपूर्ति की जा रही थी, कोई भी व्यक्ति जो होने का दावा करता है

उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, हस्तांतरणकर्ता, नियुक्तकर्ता या उत्तराधिकारी

किसी भी तरह से विचार के साथ या बिना विचार के चूक करने वाले उपभोक्ता को उपभोक्ता द्वारा देय बिजली शुल्क, प्रतिभूति जमा या मुआवजे के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा और बोर्ड के लिए आपूर्ति करने या आपूर्ति को फिर से जोड़ने से इनकार करना या ऐसे व्यक्ति को नया कनेक्शन देना वैध होगा जो ऐसे परिसर के चूक करने वाले उपभोक्ता का उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, हस्तांतरणकर्ता, समनुदेशक या उत्तराधिकारी होने का दावा करता है।

जी.

81 (2012) 13 एस. सी. सी. 479

एच.

732

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

जब तक कि इस तरह के शुल्क की देय राशि और/या चूक करने वाले उपभोक्ता से मांगे गए मुआवजे की राशि, जैसा भी मामला हो, बोर्ड को विधिवत भुगतान या जमा नहीं की जा सकती है।"

(जोर दिया गया) 186। शर्त 23 (ए) के संदर्भ में, एक उपभोक्ता बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना बिजली बोर्ड के साथ अपने समझौते के तहत लाभ हस्तांतरित करने का हकदार नहीं है। शर्त 23 (बी) के संदर्भ में, यदि उपभोक्ता शर्त 23 (ए) का उल्लंघन करता है और बोर्ड को ऊर्जा के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने में लापरवाही करता है और इसके परिणामस्वरूप, ऐसे उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति काट दी जाती है, तो तीसरा पक्ष जिस पर ऐसा हस्तांतरण किया गया था, वह बिजली के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो चूक करने वाले उपभोक्ता ने भुगतान नहीं किया है। पूर्ववर्ती उपभोक्ता के बकाया का भुगतान करने के लिए किसी तीसरे पक्ष की देयता तब जुड़ी होती है जब शर्त 23 (ए) और शर्त 23 (बी) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है।

ग

187. "इजसडेम जेनरिस" का नियम निर्माण का एक सिद्धांत है। नियम यह है कि जब सामान्य शब्द एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं, तो सामान्य शब्द उसी प्रकार की चीजों तक सीमित होने चाहिए जो निर्दिष्ट हैं। यह तब लागू होता है जब निम्नलिखित सामग्री मौजूद होती है: (i) कानून में विशिष्ट शब्दों की गणना होती है; (ii) गणना के विषय एक वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं; (iii) वह श्रेणी गणना से समाप्त नहीं होती है; (iv) एक सामान्य शब्द गणना का अनुसरण करता है; और (v) एक अलग विधायी इरादे का कोई संकेत नहीं है। 82

डी.

ई.

188. इजसडेम जेनरिस नियम के अनुप्रयोग के लिए, यह आवश्यक है कि सामान्य शब्दों से पहले गिनाई गई चीजों को एक अलग श्रेणी या एक जीनस या एक परिवार का गठन करना चाहिए जो कई सदस्यों को स्वीकार करता है।⁸³

च

एडोनी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत

बोर्ड, 84 इस न्यायालय को 1948 के अधिनियम की धारा 49 (3) की व्याख्या करनी थी, जिसने विद्युत बोर्ड को किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया था। इस न्यायालय ने व्यापकता को सीमित करने से इनकार कर दिया

जी.

82 अमर चंद्र बनाम आबकारी कलेक्टर, त्रिपुरा, (1972) 2 एस. सी. सी. 442; ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (2002) 4 एस. सी. सी. 297

83 लोकमत न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम शंकरप्रसाद, (1999) 6 एस. सी. सी. 275; जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम टिहरी पनबिजली विकास निगम

पीएन। (इंडिया) लिमिटेड, (2019) 17 एससीसी 786 84 (1976) 4 एससीसी 68 ए

एच.

733

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

"अन्य प्रासंगिक कारकों" के लिए क्योंकि गणना किए गए कारकों का कोई वंश नहीं था। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और आपूर्ति की प्रकृति और उद्देश्य को किसी भी सामान्य वंश से संबंधित नहीं माना गया था।

189. विवादित फैसले एक्टो स्पिनर्स में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि "उत्तराधिकारी" शब्द, अन्य शब्दों "उत्तराधिकारी", "कानूनी प्रतिनिधि", "हस्तांतरणकर्ता" और "असाइनी" के संयोजन में आता है, और इसका अर्थ उन पिछले शब्दों से रंग लेना चाहिए जिनके साथ इसका उपयोग किया जाता है। इसने माना कि "उत्तराधिकारी" शब्द को स्वैच्छिक हस्तांतरण के माध्यम से या विरासत के अधिकार के कारण अधिकार प्राप्त करने वाले मालिक को संदर्भित करने के लिए समझा जाना चाहिए।

190. हम उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों का शब्दकोश अर्थ, जिसका इस मामले से संबंध है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: "वारिस: एक व्यक्ति जो निर्वसीयता के कानूनों के तहत, एक निर्वसीयत मृतक की संपत्ति प्राप्त करने का हकदार है ⁸⁵

ग

डी.

कानूनी प्रतिनिधि: एक कानूनी उत्तराधिकारी; या एक निष्पादक, प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि

हस्तांतरणकर्ता: एक जिसे संपत्ति का ब्याज दिया जाता है ⁸⁷ नियुक्तकर्ता: एक जिसे संपत्ति के अधिकार दूसरे द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं ⁸⁸

ई.

191. इन शब्दों के स्पष्ट अर्थ से यह स्पष्ट है कि "उत्तराधिकारी", "कानूनी प्रतिनिधि", "हस्तांतरणकर्ता" और "नियुक्तकर्ता" शब्द एक ही विशेष श्रेणी में नहीं आते हैं। विवादित निर्णय में तर्क के अनुसार, शर्त 23 में स्वयं एक से अधिक वंश या हस्तांतरण की श्रेणी शामिल है-स्वैच्छिक हस्तांतरण के कारण या मालिक की मृत्यु के कारण संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना। "उत्तराधिकारी" शब्द, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सीमित तरीके से व्याख्या की गई थी, अपने आप में व्यापक आयाम का है और इसका एक स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "उत्तराधिकारी" अभिव्यक्ति को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अन्य के पद, अधिकारों, जिम्मेदारियों या स्थान पर सफल होता है; जो किसी पूर्ववर्ती की जगह लेता है या उसका अनुसरण करता है।" 89 "सार्वभौमिक उत्तराधिकारी" की श्रेणी आगे है

च

जी.

85 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (वेस्ट: थॉमसन रॉयटर्स 9 वां संस्करण), पेज 791 86 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (वेस्ट: थॉमसन रॉयटर्स 9 वां संस्करण), पेज 1416 87 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (वेस्ट: थॉमसन रॉयटर्स 9 वां संस्करण), पेज 136 88 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (वेस्ट: थॉमसन रॉयटर्स 9 वां संस्करण), पेज 1636 89 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (वेस्ट: थॉमसन रॉयटर्स 9 वां संस्करण), पेज 1569

एच.

734

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

समझा जाता है कि इसका अर्थ है "कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पूर्व मालिक के सभी अधिकारों और शक्तियों में सफल होता है, जैसे कि एक निर्वसीयत संपत्ति या दिवालियापन में एक संपत्ति के साथ।" 90

192. "कोई भी व्यक्ति जो चूक करने वाले उपभोक्ता का उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, हस्तांतरणकर्ता, समनुदेशक या उत्तराधिकारी होने का दावा करता है" अभिव्यक्ति के व्यापक दायरे को पूर्व संबंधित वाक्यांश "मृत्यु, या हस्तांतरण, असाइन या अन्यथा उपक्रम या परिसर के वितरण" के संबंध में समझा जा सकता है।

193. हाथ में मामले में, वाक्यांश "ए consumer.dies" में "अन्यथा वितरण", या हस्तांतरण, असाइन या अन्यथा उपक्रम या परिसर के वितरण "का उपयोग, पूर्ववर्ती शब्दों "डाईज़", "ट्रांसफर", "असाइन" के लिए इजस्टेम जेनरिस के नियम को लागू नहीं करता है जो एक सीमित जीनस से संबंधित नहीं हैं।

ग

194. "स्थानांतरण" शब्द को आम तौर पर एक व्यापक अर्थ माना जाता है, जो इसके भीतर स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों को समझता है।

स्थानांतरण। मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, 91 तीन-न्यायाधीशों की पीठ

डी.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण भारतीय आयकर अधिनियम 1962 की धारा 12 बी (1) के अर्थ के भीतर "हस्तांतरण" का गठन कर सकता है। इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि "स्थानांतरण" शब्द का अर्थ पूर्ववर्ती शब्दों "बिक्री", "विनिमय", "त्याग" के साथ एजस्टेम जेनरिस होना चाहिए। "स्थानांतरण" शब्द के व्यापक आयाम पर, इस न्यायालय ने कहा:

ई.

“8. हम इस निवेदन को स्वीकार करना असंभव पाते हैं। सबसे पहले, यदि यह इरादा था कि केवल स्वैच्छिक हस्तांतरण धारा के अर्थ के भीतर आना चाहिए, तो विधायिका के लिए "स्थानांतरण" अभिव्यक्ति का उपयोग करना अनावश्यक था, एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसे कानून में व्यापक अर्थ और आयाम के रूप में स्वीकार किया गया था। अर्ल जोविट, "द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लॉ" में कहते हैं:

च

“ संपत्ति के कानून में, एक हस्तांतरण वह है जहाँ एक अधिकार पारित होता है।

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, या तो (1) उस इरादे से हस्तांतरणकर्ता द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, जैसा कि बिक्री या उपहार आदि के माध्यम से हस्तांतरण या असाइनमेंट के मामले में; या (2)

जी.

कानून के संचालन द्वारा, जैसे कि ज़ब्त, दिवालियापन, वंश, या अंतर्वर्ती के मामले में।”

90 आईडी

91 (1978) 3 एससीसी 248 ए

एच.

735

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

"शब्द और वाक्यांश" पर रोलैंड बरोज, खंड V, में पी पर "बिक्री पर हस्तांतरण" शीर्षक के तहत एक बयान है।³³¹ कि अनिवार्य शक्तियों के तहत भूमि का हस्तांतरण भी "बिक्री पर" हस्तांतरण है। हमारे लिए इस प्रश्न पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण धारा 12-बी (1) के अर्थ के भीतर एक "बिक्री" है और वास्तव में, वर्तमान उद्देश्य के लिए इतना दूर जाना आवश्यक नहीं है। हम इस संकीर्ण प्रश्न से चिंतित हैं कि क्या संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण धारा 12-बी (1) के अर्थ के भीतर "हस्तांतरण" के बराबर हो सकता है और उस प्रश्न पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "हस्तांतरण" शब्द व्यापक है और इसे आम तौर पर इसके दायरे में स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के हस्तांतरण के रूप में माना जाता है। इसलिए, अधिक के बिना, "हस्तांतरण" शब्द के संचालन को हस्तांतरण के स्वैच्छिक कार्यों तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है ताकि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण को बाहर रखा जा सके।"

ग

(जोर दिया गया) 195। एजुस्टेड जेनरिस का नियम तब लागू नहीं किया जा सकता जब कोई अलग श्रेणी या जीनस न हो। जीनस के अभाव में, 'स्थानांतरण' या 'अन्यथा वितरण' शब्द, जो अपने अर्थ में व्यापक हैं, केवल इजस्टेड जेनरिस सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा स्वैच्छिक हस्तांतरण के अर्थ तक सीमित नहीं हो सकते हैं।

डी.

ई.

196. इजस्टेड जेनरिस का शासन कानून का एक अलंघनीय शासन नहीं है।⁹² जहां वैधानिक अधिनियम के संदर्भ और शरारत के लिए सामान्य महत्व के शब्दों के साथ एक सीमित अर्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अदालत को शब्दों को उनका सादा और सामान्य अर्थ देना होगा।⁹³ एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 पूर्ववर्ती उपभोक्ता के बिजली बकाया की वसूली का एक तरीका है, जिसे उत्तराधिकारी से भी वसूल किया जा सकता है। एमएसईबी, हमारी राय में, पूर्ववर्ती उपभोक्ता के उपक्रम या परिसर के हस्तांतरण के सभी संभावित मामलों को शामिल करने का इरादा रखता है, चाहे वह स्वैच्छिक हो, उपभोक्ता की मृत्यु के कारण हो, या कानून के संचालन द्वारा हो। एम. एस. ई. बी. द्वारा जारी 18 जून 1993 का परिपत्र 518 और 19 दिसंबर 1998 का परिपत्र 607, एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 से निकला है। इनमें उन संपत्ति

मालिकों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के संबंध में निर्देश शामिल थे जिन्होंने बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों को खरीदा था। वैधानिक नियमों और शर्तों का संदर्भ और उद्देश्य

च

जी.

92 वालपाराइसो कोट्टाराथिल कोचुनी बनाम मद्रास और केरल राज्य, (1960) 3 एससीआर 887 93 बीएचईएल बनाम ग्लोब हाई-फैब्स लिमिटेड, (2015) 5 एससीसी 718

एच.

736

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

आपूर्ति की मांग है कि एक व्यापक निर्माण को अपनाया जाना चाहिए, और इजस्टेम जेनरिस के नियम के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है।

197. उपखंड (बी) के विशेष संदर्भ के साथ आपूर्ति की एम. एस. ई. बी. शर्तों की शर्त 23 की हमारी व्याख्या पर, हमारा विचार है कि उक्त उपखंड अनैच्छिक हस्तांतरणों पर लागू होता है, जैसे कि अदालत की नीलामी।

198. उपरोक्त विचारों को अपीलों पर लागू करते हुए हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

वस्तु **101.1:** महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुपर एंड स्टेनलेस हाई अलॉयज लिमिटेड; **2005** की सिविल अपील **5312-5313**

ग

199. पहले प्रतिवादी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत एस. आई. सी. ओ. एम. से नीलामी में एक बीमार औद्योगिक इकाई खरीदी। इसने एक रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलकर्ता-बोर्ड के नए बिजली कनेक्शन से इनकार करने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। 19 दिसंबर 1998 के परिपत्र 607 के अधिकारों को चुनौती देते हुए एस. आई. सी. ओ. एम. द्वारा एक बाद की रिट याचिका दायर की गई थी। 19 दिसंबर 2002 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा किया और विवादित परिपत्र 607 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि एमएसईबी के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है क्योंकि परिपत्र 1910 अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड की शक्तियों से परे था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ईशा मार्बल्स (उपरोक्त) पर भरोसा किया कि हालांकि धारा 24 आपूर्ति बंद होने के बाद पुनः कनेक्शन के लिए बकाया के भुगतान का प्रावधान करती है, यह केवल उस उपभोक्ता को संदर्भित करती है जो बकाया का भुगतान करने में विफल रहा और परिसर के नए मालिक या अधिभोगियों के साथ खुद को संबंधित नहीं करता है।

डी.

ई.

200. अपीलार्थी ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय ने 6 मई 2003 को नोटिस जारी किया और 25 अगस्त 2005 को छुट्टी दे दी गई। 24 अगस्त 2006 के एक आदेश द्वारा, यह प्रश्न कि क्या बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क है, जहां तक हस्तांतरणकर्ता और इकाई के हस्तांतरणकर्ता का संबंध है, एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

च

201. हमारे सुविचारित विचार में, ईशा मार्बल्स (उपर्युक्त) और विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 24 में निर्णय अपने आप में इस बात का जवाब नहीं है कि क्या अपीलार्थी-बोर्ड के पास परिपत्र 607 जारी करने की शक्ति थी। श्रीगधा बेवरेजेज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि बिजली बकाया, जहां वे बिजली अधिनियम के तहत वैधानिक हैं और आपूर्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए माफ नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से ए की धारा 56

जी.

एच.

737

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

2003 अधिनियम (1910 अधिनियम की धारा 24 के साथ समान सामग्री), और विशुद्ध रूप से संविदात्मक बकाया के रूप में भाग नहीं ले सकता है। अपीलार्थी-बोर्ड की इस शर्त को लागू करने की शक्ति कि किसी उपक्रम के खरीदार को पूर्व उपभोक्ता के बिजली बकाया का भुगतान करने का दायित्व होगा, 1948 के अधिनियम की धारा 49 के तहत बनाई गई एम. एस. ई. बी. आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 से प्राप्त होती है।

202. यह उत्तरदाताओं का निवेदन था कि विवादित परिपत्र राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों को खरीदने वाले नीलामी खरीदारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि बिक्री "स्वैच्छिक नहीं" थी। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, शर्त 23 व्यापक महत्व की है, जिसमें अदालत की नीलामी में की गई संपत्ति की बिक्री शामिल है। इसके अलावा, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 (2) में प्रावधान है कि धारा 29 के तहत एक बिक्री जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का हस्तांतरण होता है, उत्तराधिकारी को हस्तांतरित संपत्ति में सभी अधिकार निहित करेगा जैसे कि हस्तांतरण संपत्ति के मालिक द्वारा किया गया हो। तदनुसार, निगम द्वारा की गई बिक्री को संपत्ति के मालिक द्वारा की गई बिक्री माना जाता है, जो एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 को आकर्षित करती है।

ग

डी.

203. एस. आई. सी. ओ. एम. द्वारा बिक्री पर रखी गई संपत्तियों की "बिक्री की सामान्य नीलामी शर्तों" के कुछ प्रासंगिक खंडों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है। खंडों को नीचे निकाला गया है:

ई.

"खंड 4: खरीदार संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है

बेचा जाता है। यदि खरीदार निरीक्षण नहीं भी करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने खरीद के लिए प्रस्ताव देने से पहले, उसकी शर्त के संबंध में "जैसा है और जो आधार है" पर बिक्री के लिए रखी गई सभी संपत्तियों का निरीक्षण किया है।

एक ही। एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से सहमति और घोषणा की जाती है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों या उस ओर से लागू किसी अन्य अधिनियम के बावजूद, एस. आई. सी. ओ. एम. खरीदार को किसी भी दोष का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, चाहे वह सामग्री हो या अन्यथा संपत्ति में, चाहे एस. आई. सी. ओ. एम. को इस तरह के दोष के बारे में पता हो या न हो और क्या खरीदार सामान्य सावधानी और परिश्रम के साथ ऐसे दोषों का पता नहीं लगा सका।

च

जी.

खंड 6: खरीदार आवश्यक बिजली कनेक्शन, पानी और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने और उक्त संपत्ति की दरों और करों के बकाया भुगतान के लिए अपनी व्यवस्था खुद करेगा और उसमें जो भी प्रकृति का खर्च आएगा, उसे पूरा करेगा।

की ओर से। एस. आई. सी. ओ. एम. बिजली, पानी या किसी अन्य वस्तु के संबंध में किसी भी बकाया शुल्क और लागत/व्यय, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अन्य आवश्यक सुविधाएँ। खरीदार बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, के बारे में खुद पूछताछ करेगा और इसे अकेले खरीदार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।"

(जोर दिया गया) 204। एस. आई. सी. ओ. एम. द्वारा निर्धारित नीलामी के उपरोक्त नियमों और शर्तों से संकेत मिलता है कि संपत्ति को "जहां है और जो आधार है" के आधार पर बेचा जा रहा था। नीलामी खरीदार हर समय इस तथ्य के स्पष्ट नोटिस पर था कि संपत्ति को "जैसा है वैसा ही है" के आधार पर बेचा जा रहा था और एस. आई. सी. ओ. एम. ने बकाया के भुगतान के लिए कोई दायित्व नहीं लिया था। यह खंड खंड 6 में एक अन्य प्रावधान के अधीन था, जिसमें खरीदार बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए बकाया के बारे में अपनी पूछताछ करने के लिए उत्तरदायी था और नीलामी खरीदार को ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तों के अलावा, जिनका वैधानिक प्रभाव है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत आयोजित नीलामी में संपत्ति खरीदने वाले खरीदार को नीलामी में बोली लगाते समय परिसर की बिजली के पिछले बकाया के लिए अपने दायित्व के बारे में भी जानकारी थी। बिक्री विलेख में दी गई शर्तों के आधार पर, जहां तक प्रथम प्रतिवादी का संबंध है, वह पूर्ववर्ती उपभोक्ता द्वारा विद्युत बोर्ड को देय बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 205. हमने ऊपर जो कहा है, उसके आलोक में, हम खंड पीठ के फैसले को दरकिनार करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं।

ग

डी.

ई.

वस्तु **101.10**: सुपदी। इंग. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मेसर्स उमंग एंटरप्राइजेज; **2005** की सिविल अपील सं. **5314**

च

206. पहला प्रतिवादी मेसर्स क्रीके यार्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपत्ति का एक सफल नीलामी खरीदार था, जिसे एक मध्यस्थ निर्णय के परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखा गया था। प्रत्यर्थी-खरीदार ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमे में न्यायाधीशों का आदेश 94 निकालकर स्पष्टीकरण मांगा कि वह नीलामी बिक्री के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के पिछले बकाया और देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं था। बंबई उच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2003 के अपने आदेश में घोषणा की कि प्रत्यर्थी-खरीदार पूर्व मालिक द्वारा देय किसी भी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। अपीलार्थी का आरोप है कि यह आदेश पारित किया गया था

जी.

94 सिविल वाद सं. 2003 में न्यायाधीशों का आदेश सं. 10। 1991 का 2978 ए

एच.

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

पूर्व-पक्ष। 29 जनवरी 2003 के न्यायाधीशों के आदेश में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। 207. प्रत्यर्थी-खरीदार ने अपीलार्थी से एक नए बिजली कनेक्शन के लिए अनुरोध किया, जिसे 6 जून 2003 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी नए कनेक्शन के लिए तब तक पात्र नहीं था जब तक कि पूर्व उपभोक्ता के बकाया का भुगतान एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 के संदर्भ में नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें एक अंतरिम प्रार्थना के साथ एक नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश की मांग की गई। रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि बिजली बोर्ड द्वारा बकाया भुगतान करने की मांग कानून में निराधार थी। बंबई उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2004 के अपने विवादित फैसले में रिट याचिका का निपटारा करते हुए अपीलार्थी को पिछले उपभोक्ता के पिछले बकाया की निकासी पर जोर दिए बिना एक महीने के भीतर परिसर में बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

ग

ईशा मार्बल्स (ऊपर) और गुजरात इंस (ऊपर) में।

डी.

208. अपीलार्थी ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय ने 6 जनवरी 2005 को नोटिस जारी किया।

209. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस न्यायालय ने ईशा मार्बल्स (ऊपर) और गुजरात इंस (ऊपर) दोनों में नीलामी खरीदार को पिछले मालिकों द्वारा किए गए बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया क्योंकि उस संबंध में कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं था, या बिजली बकाया के मुद्दे से संबंधित कोई खंड नहीं था। वर्तमान मामले में, एम. एस. ई. बी. ने नीलामी खरीदारों को उत्तरदायी ठहराने के लिए एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 पर विशिष्ट निर्भरता रखी। एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तों को विद्युत बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच किए गए व्यक्तिगत अनुबंधों में शामिल किया गया था। एम. एस. ई. बी. और उपभोक्ताओं के बीच किए गए मानक समझौतों में खंड 14 में प्रावधान है कि समय-समय पर संशोधित आपूर्ति की शर्तों को समझौते का हिस्सा माना जाएगा। पूर्ववर्ती उपभोक्ता आपूर्ति की वैधानिक एम. एस. ई. बी. शर्तों से अवगत थे। संबंधित खंड नीचे निकाला गया है:

ई.

च

जी.

“खंड 14 (ए): महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वर्तमान में लागू और समय-समय पर आपूर्तिकर्ता द्वारा संशोधित शर्तों और विविध शुल्कों को समझौते का हिस्सा माना जाएगा और जहां तक लागू हो, यहां के पक्षों को नियंत्रित करेगा। की एक प्रति

एच.

740

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

आपूर्ति के लिए वर्तमान शर्तें और विविध शुल्क यहां दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं।”

210. हमारा विचार है कि विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है।

वस्तु **101.11**:महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम एक्टो स्पिनर्स; **2005** की सिविल अपील सं. **6587**

211. 1999 में, मेसर्स प्रभावती स्पिनिंग मिल, एक सहकारी कताई मिल की इकाई को बंद कर दिया गया था। मेसर्स प्रभावती स्पिनिंग मिल को आपूर्ति की गई बिजली को पहले अपीलार्थी द्वारा उपभोग शुल्क के भुगतान में चूक के कारण काट दिया गया था। 2004 में, पहले प्रतिवादी ने मेसर्स प्रभावती स्पिनिंग मिल को खरीदा, जिसे महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। बिक्री के समझौते को 26 जुलाई 2004 को पहले प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया था और तब से, पहले प्रतिवादी के पास संपत्ति का कब्जा था। असाइनमेंट का अंतिम विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया था। पहले प्रतिवादी ने परिसर में संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत के लिए 4 करोड़ रुपये का खर्च किया, और उसके बाद परिसर के लिए उच्च तनाव उपभोक्ता के रूप में नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। इस बीच, भूखंडों को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा 4 फरवरी 2005 को पहले प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि, अपीलार्थी ने एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तों और पूर्ववर्ती उपभोक्ता के बकाया भुगतान तक बिजली कनेक्शन देने से इनकार करने के लिए पूर्ववर्ती उपभोक्ता के साथ किए गए समझौते पर भरोसा किया। प्रत्यर्थी ने बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अपीलार्थी को अपने परिसर में प्रत्यर्थी को बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश देने की मांग की गई।

ग

डी.

ई.

च

212. 20 जुलाई 2005 के विवादित फैसले से बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी को नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पूर्व मालिक के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि बिजली बकाया के संबंध में न तो कोई वैधानिक प्रावधान था और न ही संपत्ति पर कोई शुल्क लगाने का कोई समझौता था।

जी.

213. इस न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2005 को अनुमति दे दी। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तों की शर्त 23 एक विशिष्ट प्रावधान है जो पहले प्रतिवादी के मामले में लागू होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, और उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

एच.

741

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

वस्तु **101.12**:महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स जिया आयरन स्टोर; **2006** का एस. एल. पी. (सिविल) सं. **6068**

214. मूल उपभोक्ता, मेसर्स सुमित री-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर ने नागपुर नागरिक सहकारी बैंक से लिए गए ऋण के भुगतान में चूक की। बैंक ने नागपुर में सहकारी अदालत के समक्ष एक विवाद दायर किया। नागपुर की सहकारी अदालत के न्यायाधीश ने 23 फरवरी 2005 के एक आदेश द्वारा मेसर्स सुमित री-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के काल्पनिक संयंत्र और मशीनरी और गिरवी रखी गई भूमि और भवन को बेचने की अनुमति दी। पुरस्कार के निष्पादन में, मेसर्स सुमित री-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित संपत्ति पहले प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई थी।

215. बैंक के अधिकृत अधिकारी ने 21 मार्च 2005 को प्रत्यर्थी को पूरे चल संयंत्र और मशीनरी और अचल भूमि और भवन का भौतिक कब्जा सौंप दिया, जो बैंक के साथ गिरवी रखा गया था।

216. नागपुर नागरिक सहकार बैंक लिमिटेड और प्रतिवादी के बीच 17 फरवरी 2006 को असाइनमेंट और बिक्री का एक विलेख दर्ज किया गया था। इन्डेन्चर के खंड 2 में कहा गया है कि बैंक बिजली बकाया और नए बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क जैसे किसी भी बकाया के लिए कोई दायित्व नहीं लेगा। संबंधित खंड नीचे निकाला गया है:

डी.

“स्थानीय प्राधिकरणों के बकाया और राजस्व प्राधिकरण, एम. आई. डी. सी. प्राधिकरण और बिक्री कर आदि के बकाया के संबंध में और विचाराधीन संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली देनदारियां, यदि कोई हों और देनदारियां, खरीदार द्वारा देय होंगी। संपत्ति एतद्द्वारा "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है वही है" के आधार पर निर्दिष्ट की गई है। बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या एम. आई. डी. सी. के पानी/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बकाया और नए बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क, स्थानीय प्राधिकरण, या नजुल/एन. आई. टी. बकाया जैसे किसी भी बकाया के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए बैंक कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं लेता है और यह पूरी तरह से और विशेष रूप से खरीदार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।”

ई.

च

जी.

217. प्रथम उत्तरदाता ने परिसर के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी-एमएसईडीसी ने 9 सितंबर 2005 के एक पत्र द्वारा पहले प्रतिवादी के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पहले के मालिक के बिजली शुल्क के बकाया लंबित थे, और

एच.

742

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

प्रथम प्रतिवादी एम. एस. ई. बी. आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 के आलोक में उन्हें साफ़ करने के लिए उत्तरदायी था। बंबई उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर 2005 के अपने विवादित फैसले में कहा कि शर्त 23 लागू नहीं होती है और अपीलार्थी को निर्देश दिया कि यदि वह अन्यथा पात्र है तो पहले प्रतिवादी को एक नया संबंध प्रदान करें। उच्च न्यायालय ने कहा कि शर्त 23 का उद्देश्य मूल उपभोक्ता के स्वैच्छिक कार्यों पर लागू होना है जिसके द्वारा वह बोर्ड के साथ अपने समझौते का लाभ हस्तांतरित करता है।

218. अपीलार्थी ने विवादित फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि स्वैच्छिकता की अवधारणा एम. एस. ई. बी. आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 के लिए अनिवार्य नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाब में, यह आग्रह किया गया है कि यह वर्तमान याचिका का एक आवश्यक पक्ष नहीं है क्योंकि उसने 29 मार्च 2006 को असाइनमेंट के एक विलेख द्वारा विवादग्रस्त परिसर को राजाराम स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था।

219. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में अपने फैसले को एम. एस. ई. बी. आपूर्ति की शर्तों 1976 पर आधारित किया है। 20 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता के अधिनियमन के बाद नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले प्रतिवादी के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था। बिजली की आपूर्ति की शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर नीलामी खरीदार बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है।

डी.

ई.

220. प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन जिसमें उसने नए बिजली कनेक्शन की मांग की थी, उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। उसी समय, अभिलेख पर रखे गए असाइनमेंट और बिक्री के विलेख से यह पता चलता है कि परिसर की बिक्री और कब्जा 20 जनवरी 2005 के बाद दिया गया था। बैंक को बेचने की अनुमति केवल 23 फरवरी 2005 को दी गई थी। परिसर का भौतिक कब्जा केवल 21 मार्च 2005 को प्रतिवादी को दिया गया था। प्रत्यर्थी के पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने से पहले भी बिजली आपूर्ति के नए कनेक्शन का अनुरोध नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, इस मामले को नियंत्रित करने वाला प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 है।

च

जी.

221. विनियमन 10.5 के संदर्भ में, बिजली के लिए कोई भी शुल्क या वितरण लाइसेंसधारक के कारण बिजली के लिए शुल्क के अलावा कोई भी राशि जो किसी मृत उपभोक्ता या किसी भी परिसर के पूर्व अधिभोगकर्ता/मालिक द्वारा भुगतान नहीं की जाती है, वह परिसर पर कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों को प्रेषित या नए ए को हस्तांतरित शुल्क होगा।

एच.

743

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

जैसा भी मामला हो, परिसर का मालिक/अधिभोगकर्ता, और यह वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों या परिसर के नए मालिक/अधिभोगियों से वसूल किया जाएगा। हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि किसी कानूनी उत्तराधिकारी को कनेक्शन के हस्तांतरण के मामले को छोड़कर, विनियमन 10.5 के तहत हस्तांतरित की जाने वाली देनदारियां परिसर में आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए अवैतनिक शुल्क की अधिकतम छह महीने की अवधि तक सीमित हैं। तदनुसार, मेसर्स सुमित री-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर द्वारा बकाया राशि सार्वजनिक नीलामी में पहले प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर ली जाती है। 222. बिक्री "जैसा है जहां है" के आधार पर की गई थी और तदनुसार प्रत्यर्थी को शुल्क की पर्याप्त सूचना दी गई थी। इसलिए, वितरण लाइसेंसधारी विनियमन 10.5 के परंतुक में निर्दिष्ट अनुमत अवधि के अधीन पहले प्रतिवादी से अवैतनिक देय राशि की वसूली करने का हकदार है।

ग

223. उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, जो सामने आई है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपील की अनुमति प्रदान की जाती है।

डी.

वस्तु **101.13:** महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मेसर्स जय तीरथ फाइनेंसर प्राइवेट लिमिटेड; **2006** की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या **10732**

224. 1999 में, मैसर्स हरिंगंगा अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ परिसमापन की कार्यवाही शुरू की गई थी। 2 मई 2001 के एक बिक्री नोटिस द्वारा, मैसर्स हरिंगंगा अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों की खरीद के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से "जैसा है वैसा ही है" और "जैसा है वैसा ही है" आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। पहले प्रतिवादी ने नीलामी बिक्री में परिसंपत्तियों को सफलतापूर्वक खरीदा और 2002 में खरीदी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया। 225। 17 जून 2005 को, प्रत्यर्थी ने नीलामी में खरीदे गए परिसर में एक नए बिजली कनेक्शन के लिए अपीलार्थी को आवेदन दिया। 22 जून 2005 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि पूर्ववर्ती मालिक के 83 लाख रुपये के बिजली शुल्क का बकाया लंबित था और जब तक पूर्ण बकाया का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक स्थायी बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी ने अस्थायी कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी। प्रत्यर्थी ने मैसर्स हरिंगंगा अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड के परिसमापन के मामले में 1999 की कंपनी याचिका संख्या 6 में 2005 का कंपनी आवेदन संख्या 106 दायर किया, जिसमें बकाया राशि की निकासी के बिना एक नया बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग की गई थी।

ई.

च

जी.

226. प्रत्यर्थी के आवेदन को 10 फरवरी 2006 के विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था

एच.

744

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता भूखंड के पूर्व मालिक के बकाया की वसूली के आधार पर प्रतिवादी को बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता सुरक्षित लेनदारों में से एक था और उसे कानून के अनुसार आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपना दावा करने का निर्देश दिया।

227. अपीलार्थी ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी। 17 जुलाई 2006 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

228. अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने मैसर्स अंकुश शिक्षा सांथा को संपत्ति बेच दी थी और नए मालिक ने 9 अगस्त 2007 को अपीलकर्ता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि वह मैसर्स हरिंगंगा अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड के बकाया को बारह किश्तों में निपटाने के लिए तैयार है। 22 अक्टूबर 2007 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर प्रत्यर्थी द्वारा पहली दो किश्तों की प्राप्ति के बाद बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया कि वह 9 अगस्त 2007 के प्रस्ताव के संदर्भ में 83 लाख रुपये का पूरा बकाया जमा करेगा। अदालत को सूचित किया गया है कि आदेश के अनुसार, मैसर्स अंकुश शिक्षण सांथा ने 83 लाख रुपये के बकाया का भुगतान किया था और अपीलार्थी ने एक नया बिजली कनेक्शन दिया है।

ग

डी.

ई.

229. इस बीच, प्रतिवादी द्वारा याचिका को इस आधार पर निपटाने के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन 95 दायर किया गया था कि यह निष्फल हो गया था। उत्तर शपथपत्र में अपीलार्थी ने आई. ए. को इस आधार पर चुनौती दी है कि भले ही बकाया राशि के लिए 83 लाख रुपये की मूल राशि का भुगतान किया गया है, लेकिन मूल राशि पर लगभग 2 करोड़ रुपये का ब्याज शुल्क अभी भी वसूल किया जाना बाकी है।

च

230. चूंकि प्रतिवादी ने 17 जून 2005 को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, इसलिए महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005, जो 20 जनवरी 2005 से लागू हुई, तत्काल मामले में लागू है। तदनुसार, विनियमन 10.5 के संदर्भ में बिजली बकाया पर शुल्क लगाया गया था। साथ ही, न्यायालय उन वाणिज्यिक आवश्यकताओं से अनजान नहीं हो सकता है जिनके मद्देनजर निपटान प्रस्ताव का पालन किया गया था। अपीलार्थी ने 83 लाख रुपये की राशि बरामद की है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस स्तर पर ब्याज के भुगतान का निर्देश देना अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए हम बंद करने का निर्देश देते हैं।

जी.

95 2007 ए का आई. ए. सं. 2

एच.

745

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उपरोक्त शर्तों में विवाद का।

231. इन परिस्थितियों में, इस स्तर पर अपील पर विचार करना संभव नहीं है। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

वस्तु **101.14:** महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गरीब नवाज स्क्रेप मर्चेन्ट; **2006** की सिविल अपील सं. **10732**

232. 2002 में, मेसर्स आर एंड जे अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की बिजली आपूर्ति अपीलार्थी द्वारा स्थायी रूप से काट दी गई थी। 13 अक्टूबर 2005 को, पहले प्रतिवादी ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र के प्रवर्तन के लिए आयोजित बिक्री के अनुसार आयोजित नीलामी में मेसर्स आर एंड जे अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को सफलतापूर्वक खरीदा। प्रत्यर्थी ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और 8 दिसंबर 2005 के वसूली अधिकारी के आदेश द्वारा बिक्री की पुष्टि की गई। मेसर्स आर एंड जे अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी बिक्री की शर्तों में कहा गया है कि बिक्री "जहां है उसी आधार पर" की गई थी।

ग

डी.

233. 30 दिसंबर 2005 को, प्रतिवादी ने एक नए बिजली कनेक्शन के लिए अपीलार्थी को आवेदन दिया। इसके बाद 2 जनवरी 2006 को एक पत्र लिखा गया। 12 जनवरी 2006 के पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने तब तक नया बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर दिया जब तक कि संपत्ति के पूर्व मालिक के 11 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान नहीं किया जाता। प्रत्यर्थी ने बिजली कनेक्शन की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 13 अक्टूबर 2006 को, उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी को अंतरिम राहत देते हुए विवादित आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को कानूनी मुद्दे के लंबित रेफरल पर ध्यान दिया। इसने पाया कि नीलामी खरीदारों से बकाया का दावा करने का विद्युत बोर्ड का अधिकार उक्त जारी किए गए निर्णय पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय ने विद्युत बोर्ड को पक्षों के अधिकारों के अंतिम निर्णय के अधीन अंतरिम बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया। 234. इसमें अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी। 9 जुलाई 2007 को, इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और

मामले को 2005 की सिविल अपील संख्या 5312-5313 के साथ टैग किया गया था। अंतरिम बिजली कनेक्शन देने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

ई.

च

जी.

एच.

746

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

235. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत भास्मे द्वारा जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि पहले प्रतिवादी ने जानबूझकर पिछले बकाया का भुगतान करने के दायित्व के साथ परिसर खरीदा था, जो नीलामी बिक्री की शर्तों के खंड 3 और खंड 4 से स्पष्ट है। तदनुसार, यह आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी एम. एस. ई. बी. आपूर्ति शर्तों की शर्त 23 (बी) को देखते हुए बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश वकील श्री एम. वाई. देशमुख ने आग्रह किया है कि महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अधिनियमन के बाद एम. एस. ई. बी. की आपूर्ति की शर्तें 1976 लागू नहीं हैं। 236. प्रत्यर्थी ने अपनी लिखित दलीलों में पूर्व मालिक के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा शुरू किए गए 96 की वसूली के मुकदमे को इस न्यायालय के ध्यान में लाया है। वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, निचली अदालत ने 30 सितंबर 2009 के एक आदेश द्वारा बिजली बिलों के बकाया के संबंध में पूर्व उपभोक्ता और उसके मालिक से देय ऋण के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में एक डिक्री पारित की। प्रथम प्रत्यर्थी ने आग्रह किया है कि डिक्री को देखते हुए, अपीलार्थी को मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाय वर्तमान अपील को वापस लेना चाहिए था। 237. शुरुआत में, हम 2003 के अधिनियम की प्रयोज्यता पर प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे। 2002 में बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया था, और पहले प्रतिवादी ने 2005 में परिसर में स्वामित्व अधिकार हासिल कर लिए थे। पहले प्रतिवादी ने 30 दिसंबर 2005 को एक नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। इसलिए, 20 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 लागू होने के बाद पहले प्रतिवादी ने अपीलार्थी से बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। तदनुसार, महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 वर्तमान मामले में तथ्यों को नियंत्रित करेगी। महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के विनियम 10.5 के संदर्भ में, कोई भी अवैतनिक बिजली बकाया परिसर पर एक शुल्क का गठन करता है, और उस परिसर के नए मालिक या कब्जाधारी से वसूली योग्य होगा जिसे परिसर हस्तांतरित किया गया है।

ग

डी.

ई.

च

238. इसके अलावा, नीलामी बिक्री की शर्तों ने पहले प्रतिवादी को नोटिस पर रखा कि यह "जैसा है वैसा ही है" के आधार पर बिक्री थी और यदि बिक्री आय में अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं थी, तो खरीदार एमएसईबी सहित विभिन्न प्राधिकरणों के बकाया के लिए उत्तरदायी होगा। प्रासंगिक खंडों को नीचे निकाला गया है:

जी.

96 स्प्ल. 2003 ए की सिविल सं. 104

एच.

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

“3. अब तक इस कार्यालय को पता है कि नगरपालिका कर, एमएसईबी या निगम कर या दोनों करों का (कोई) बकाया नहीं है। हालांकि, उस ओर से किए गए किसी भी वैध दावे का भुगतान बिक्री आय से किया जाएगा यदि वह इसमें उल्लिखित राशि से अधिक है।

पुनर्प्राप्ति प्रमाणपत्र। यदि ऐसी अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं है तो दायित्व खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, संभावित खरीदार से जांच करने की उम्मीद है।

एम. आई. डी. सी., सी. आई. डी. सी. ओ., एम. एस. ई. बी., नगर निगम आदि से संपत्ति पर बकाया, यदि कोई हो।

4. संपत्तियों को "जैसा है, जहां आधार है" पर बेचा जाएगा।"

(जोर दिया गया)

ग

239. तदनुसार, मेसर्स आर एंड जे अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमएसईबी को देय बकाया सार्वजनिक नीलामी में पहले प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर एक शुल्क है। शुल्क संपत्ति से जुड़ा होता है और एक वितरण लाइसेंसधारी विनियमन 10.5 के परंतुक में निर्दिष्ट अनुमत अवधि के अधीन पहले प्रतिवादी से अवैतनिक बकाया की वसूली करने का हकदार होता है।

डी.

240. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा 2003 में पूर्ववर्ती मालिक के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने का संबंध है, वह कानून द्वारा प्रदान किया गया एक वैकल्पिक उपाय है जिसे अपीलार्थी पूर्ववर्ती उपभोक्ता से बिजली बकाया वसूलने के लिए कर सकता है। बिजली का कनेक्शन काटने के अलावा, एम. एस. ई. बी. के पास पूर्ववर्ती उपभोक्ता से बकाया की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे दायर करने और उसके बाद निष्पादन याचिकाएं दायर करने का उपाय है। दीवानी मुकदमा दायर करने से अपीलार्थी को उस व्यक्ति से बिजली के लिए किसी भी बकाया शुल्क की वसूली करने से नहीं रोका जाएगा जिसे संपत्ति हस्तांतरित की गई है या उक्त परिसर के अधिभोगियों से जहां विनियमन 10.5 के संदर्भ में नया बिजली कनेक्शन मांगा गया है।

ई.

च

241. प्रत्यर्थी के वकील ने आग्रह किया है कि हालांकि दीवानी मुकदमे में डिक्री 30 सितंबर 2009 को अपीलार्थी के पक्ष में पारित की गई थी, लेकिन अपीलार्थी आज तक इसे निष्पादित करने में विफल रहा है। वितरण लाइसेंसधारक को बकाया राशि को बढ़ने नहीं देना चाहिए और बिजली की आपूर्ति को तुरंत बंद करना चाहिए और उसके बाद धन/बकाया की वसूली के लिए मुकदमा दायर करके अपने उपाय को आगे बढ़ाना चाहिए। यह वितरण लाइसेंसधारी का बाध्यकारी कर्तव्य बन जाता है कि वह दिए गए आदेश का लगन से पालन करे और वास्तविक चूककर्ता से राशि की वसूली करे। डिक्री के निष्पादन में जो भी राशि प्राप्त हुई होगी, उसे प्रत्यर्थी द्वारा देय राशि निर्धारित करने के लिए उचित श्रेय दिया जाना चाहिए।

जी.

एच.

242. उन कारणों को ध्यान में रखते हुए जो पहले प्रस्तुत किए गए हैं, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर देते हैं।

III. गुजरात

243. गुजरात में, विद्युत उपयोगिताओं का बकाया राशि की मांग करने का अधिकार निम्नलिखित प्रावधानों से पता लगाया जा सकता है:

ए। 10 जून 2003 को 2003 के अधिनियम के अधिनियमन तक:

शासी विधान में 1910 का अधिनियम और 1948 का अधिनियम शामिल हैं। गुजरात विद्युत बोर्ड की आपूर्ति की शर्तों का खंड 2 (जे) 10 अगस्त 2001 की एक अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया था। इसमें लिखा है:

ग

“ 2(जे) पुराने बकाया की वसूली:

किसी भी परिसर के लिए पुनर्संयोजन या नया कनेक्शन, जहां उपभोक्ता/अधिभोगकर्ता से बोर्ड के बकाया लंबित हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा। बिजली की आपूर्ति के लिए उत्तराधिकारी/अधिभोगियों के आवेदन को संसाधित करने से पहले नए उत्तराधिकारी/अधिभोगियों को पिछले उपभोक्ता के इन बकाया का भुगतान करना होता है। यदि बोर्ड, बाद की तारीख में, पिछले उपभोक्ता से इन बकाया राशि का पूरा या कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तो इस तरह के बकाया की वसूली के लिए कानूनी खर्चों सहित लागतों को समायोजित करने के बाद राशि उत्तराधिकारी/अधिभोगियों को वापस कर दी जाएगी और धनवापसी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।”

डी.

ई.

बी। 10 जून 2003 से 31 मार्च 2005 तक: अनुभाग के अनुसार

185(2)(क) 2003 के अधिनियम के अनुसार, आपूर्ति की मौजूदा शर्तें लागू होती रहीं।

ग. 31 मार्च 2005 से जब आपूर्ति संहिता लागू हुई।

च

बल: खंड 4.1.11 को आपूर्ति संहिता के तहत अधिसूचित किया गया था। प्रासंगिक विनियमन इस प्रकार है:

“विनियमन 4.1.11

नया कनेक्शन, पुनः कनेक्शन, लोड को जोड़ना या कम करना, नाम बदलना या सर्विस लाइन को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वितरण लाइसेंसधारी के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी उसके नाम पर रखे गए किसी अन्य सेवा कनेक्शन के संबंध में वितरण लाइसेंसधारी को आवेदक का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाता है।”

जी.

एच.

क.

घ. 20 अगस्त 2010 से जब आपूर्ति संहिता थी

संशोधित किया गया: आपूर्ति संहिता के खंड 4.1.11, 4.1.16 और 4.8 को धारा 50 के साथ पठित धारा 43 के तहत अधिसूचित किया गया था। 2010 में संशोधन के बाद खंड 4.1.11 इस प्रकार है:

“खंड 4.1.11

किसी भी परिसर के लिए नए कनेक्शन, पुनर्संयोजन, भार को जोड़ने या कम करने, नाम बदलने या सेवा लाइन को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उस परिसर से संबंधित कोई बकाया या वितरण लाइसेंसधारी के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी उसके नाम पर रखे गए किसी अन्य सेवा कनेक्शन के संबंध में आवेदक का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाता है।

ग

बशर्ते कि यदि कनेक्शन नए आवेदक से पहले के बकाया की वसूली के बाद जारी किया जाता है और यदि लाइसेंसधारी, उचित कानूनी उपायों का लाभ उठाने के बाद, पिछले उपभोक्ता/मालिक या उस परिसर के अधिभोगियों से बकाया राशि का पूरा या कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तो राशि उस नए उपभोक्ता/मालिक या अधिभोगियों को वापस कर दी जाएगी, जिनसे ऐसे बकाया की वसूली के लिए खर्चों को समायोजित करने के बाद बकाया राशि वसूल की गई है।” गुजरात उच्च न्यायालय के पास आपूर्ति की शर्तों के खंड 2 (जे) और गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता के खंड 4.1.11 की वैधता पर विचार करने का अवसर था।

डी.

ई.

वस्तु **101.2**: मेसर्स नवयुग स्टील कास्ट और ए. एन. आर. वी. पश्चिम गुजरात विज कंपनी; **2005** की सिविल अपील सं. **7303**

244. 10 अगस्त 1998 को अनिक स्टील लिमिटेड को बंद करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कंपनी को बंद करने का आदेश पारित किया गया था और एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया था। 21 दिसंबर 2001 के एक विज्ञापन द्वारा, आधिकारिक परिसमापक ने पिछले मालिक की संपत्ति की नीलामी बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। अपीलार्थी ने रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। “जैसा है, जहां है” के आधार पर संपत्ति की खरीद के लिए 35.50 लाख रुपये। प्रस्ताव पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता “

च

जी.

गुजरात विद्युत बोर्ड, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, बिक्री कर और आयकर विभाग और किसी भी बाहरी व्यक्ति के पिछले किसी भी बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह सरकारी, अर्ध-सरकारी निगम और/या बोर्ड, बैंक या किसी निजी कंपनी का हो।

पार्टियाँ “। आपस में बोली लगाने के बाद, अपीलार्थी का रुपये का प्रस्ताव। 45. 5 लाख सबसे अधिक पाए गए। 23 जुलाई 2022 को आधिकारिक परिसमापक ने प्रस्तुत किया

एच.

750

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री की पुष्टि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट। 45. 5 लाख। उच्च न्यायालय ने कुछ नियमों और शर्तों के अधीन अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री को स्वीकार कर लिया। ऐसी ही एक शर्त थी:

“10. खरीदार बंद होने की तारीख के बाद की अवधि के लिए कंपनी की संपत्तियों पर देय और देय सभी वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। का भुगतान

परिसमापन पूर्व अवधि के लिए इस तरह के बकाया का निपटान कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, परिसंपत्तियों की बिक्री पर देय राशि, कर, उपकर, यदि कोई लागू होता है, तो खरीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।”

ग

(जोर दिया गया) 245। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीलामी शर्तों के अनुसार, प्रतिफल का भुगतान किया गया और संपत्ति का कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया गया। जब अपीलार्थी ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया, तो प्रतिवादी ने नए कनेक्शन देने से पहले पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने पर जोर दिया। अपीलार्थी ने आपूर्ति की शर्तों के खंड 2 (जे) को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और आपूर्ति की शर्तों के खंड 2 (जे) को मनमाना और कानून के वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण रद्द कर दिया। प्रत्यर्थी ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ खंड पीठ के समक्ष विशेष अपील को प्राथमिकता दी। डिवीजन बेंच ने 18 जुलाई 2005 के फैसले द्वारा खंड 2 (जे) की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा कि यह 1948 के अधिनियम की धारा 49 (1) के दायरे और दायरे में आता है।

डी.

ई.

246. 10 अगस्त 2001 को गुजरात विद्युत बोर्ड ने 1948 के अधिनियम की धारा 49 के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसमें 'विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शर्त और विविध शुल्क' में शर्त 2 (जे) को शामिल किया गया। शर्त 2 (जे) ने बोर्ड को पहले के कनेक्शन की बहाली या परिसर के नए मालिक/अधिभोगियों के पक्ष में नए कनेक्शन जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में पूर्व उपभोक्ता के बिजली बकाया के भुगतान पर जोर देने का अधिकार दिया। जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है, ऐसी शर्तों को 1910 के अधिनियम और 1948 के अधिनियम की समग्र योजना के आलोक में कानूनी रूप से निर्धारित किया जा सकता है। 1948 के अधिनियम की धारा 49 के अनुसार निर्धारित ऐसे नियमों और शर्तों का एक वैधानिक चरित्र है।

च

जी.

एच.

751

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

247. 23 जुलाई 2002 को, उच्च न्यायालय ने आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया। नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों से पता चलता है कि संपत्ति को अपीलार्थी को "जैसा है वैसा ही" आधार पर बेचा गया था। अपीलार्थी ने यह तर्क देने के लिए शर्त 10 पर भरोसा किया है कि वह केवल समापन आदेश की तारीख के बाद उपार्जित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि बकाया भुगतान समापन आदेश की तारीख से पहले की अवधि के लिए है, जो कि 10 अगस्त 1998 है। मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने 12 अगस्त 2002 के एक पत्र द्वारा बिजली की आपूर्ति का अनुरोध किया था। वर्तमान मामले में बिजली बकाया का भुगतान वैधानिक प्रकृति का होने के कारण माफ नहीं किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें आपूर्ति की शर्तों

की शर्त 2 (जे) के तहत की गई वैधानिक मांग के अधीन हैं। इसलिए हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखते हैं।

ग

248. अलग होने से पहले, हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि 18 नवंबर 2011 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को रु। 25 लाख उत्तरदाता के साथ और एक नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आदेश की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता के नाम पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी देकर शेष मूल राशि को सुरक्षित करें। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

डी.

“पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई मूल राशि रु। 1. 26 करोड़। आवेदक-याचिकाकर्ता ने नए बिजली कनेक्शन के अनुदान के लिए आवेदन किया है जिसे इस आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है कि ऊपर उल्लिखित बकाया, पिछले मालिक [उपभोक्ता] द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता नीलामी खरीदार है। आगे के आदेशों को लंबित रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को रुपये जमा करने का निर्देश देते हैं। उत्तरदाता संख्या 1 के साथ 25 लाख रुपये और उनके अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड-उत्तरदाता संख्या 1 के नाम पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी देकर मूल राशि सुरक्षित करें। उपरोक्त शर्तों का पालन करने पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।” 249. इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नया संबंध प्राप्त नहीं करने का फैसला किया है। एक अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से, अपीलार्थी ने संकेत दिया है कि उनके लिए कुल संचित बकाया राशि का भुगतान करना असंभव है। ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ 578 लाख। इसलिए, अपीलार्थी लाभ चाहता है

ई.

च

जी.

एच.

752

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

गुजरात सरकार द्वारा 29 मार्च 2012 को जारी माफी योजना। इसके अलावा, अपीलकर्ता प्रस्तुत करता है कि वह केवल एक लाख रुपये तक की अपनी मूल देनदारी का भुगतान कर सकता है। 126 लाख। उक्त आवेदन के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया है:

“10. आवेदक प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक गुजरात सरकार की इस माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के इरादे से इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है, केवल इस कारण से कि यदि आवेदक सफल हो जाता है, तो आवेदक को मूल बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होगी यदि आवेदक मामला हार जाता है। 126.00 लाख (मूल राशि) और आवेदक किसी अन्य विलंब भुगतान शुल्क और अन्य शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए, आवेदक इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता है कि आवेदक का दायित्व केवल मूल बकाया राशि यानी रु। 126.00 बिना किसी ब्याज और जुर्माने आदि के लाख, आवेदक ऐसी राशि जमा करने के लिए तैयार है जो इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या के साथ जमा करने के लिए आवश्यक है। 1 और शेष राशि के लिए आवेदक बैंक गारंटी जमा करने के लिए तैयार है और/या इस माननीय न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में पूरी राशि जमा करने के लिए तैयार है।”

ग

डी.

हम समानता, न्याय और निष्पक्षता के हित में उपरोक्त आवेदन को इस हद तक अनुमति देते हैं कि अपीलार्थी केवल 500 करोड़ रुपये की मूल राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 126 लाख और बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन की तारीख से पहले उपार्जित कोई भी बकाया ब्याज।

ई.

वस्तु **101.3**: टोरेंट पावर एईसी लिमिटेड बनाम मेसर्स श्रीजी (रखैल) कमर्शियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य; **2007** की एस. एल. पी. (सी) संख्या **2880**

च

250. अपीलार्थी अहमदाबाद में बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति में लगी एक विद्युत उपयोगिता है। रायपुर मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका पिछला मालिक था, रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया। चालू ब्याज सहित बिजली बकाया के लिए 12 करोड़ रुपये बकाया ऋण के कारण, अपीलार्थी ने 15 जुलाई 1999 को अहमदाबाद में कंपनी के परिसर में बिजली की आपूर्ति काट दी। 2001 में, गुजरात उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायालय के समक्ष पिछले मालिक के खिलाफ समापन कार्यवाही दायर की गई थी। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर 2002 को प्रतिवादी के पक्ष में एक आदेश द्वारा पिछले मालिक की संपत्ति की बिक्री को मंजूरी दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार थीं:

जी.

एच.

753

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

क.

"1. कंपनी की संपत्तियों की बिक्री "जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर होगी और आधिकारिक परिसमापक उस शीर्षक के अलावा स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करेगा जो कंपनी के परिसमापन से पहले था।

5. नगरपालिका बकाया, कर, उपकर आदि सहित सभी वैधानिक बकाया का भुगतान और वहन खरीदार, अजार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। खरीदार उन सभी शुल्कों, शुल्कों, दावों, बकाया आदि के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा जो किसी भी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेचे गए उक्त संपत्तियों पर किसी भी तरह से दावा करने के लिए मौजूदा या लगाए जा सकते हैं।" 251. संपत्ति पर कब्जा करने के बाद, प्रत्यर्थी ने बिजली कनेक्शन देने के लिए अपीलार्थी को 7 जनवरी 2004 को एक पत्र लिखा। हालाँकि, अपीलार्थी ने बिजली की आपूर्ति देने से इनकार कर दिया जब तक कि प्रत्यर्थी पूर्व मालिक के बकाया का भुगतान नहीं करता। प्रत्यर्थी ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलार्थी द्वारा बिजली कनेक्शन देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। एक सामान्य निर्णय के माध्यम से, एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी, एक नीलामी खरीदार होने के नाते, किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में पिछले मालिकों के पिछले बकाया का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया कि पक्षों के बीच ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को पिछले मालिकों के बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के संबंध में आपूर्ति की शर्तों की शर्त 2 (जे) के समान कोई शर्त शामिल नहीं की थी। डिवीजन बेंच ने 1 मई 2006 के विवादित फैसले में एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा।

ग

डी.

ई.

च

252. प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जिस गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता पर भरोसा किया गया है, उसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। नीलामी खरीदार के अनुसार, गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता 31 मार्च 2005 से लागू हुई, जबकि प्रत्यर्थी नीलामी खरीदार ने 13 अगस्त 2004 को बिजली के लिए आवेदन किया, जो बिजली आपूर्ति संहिता के लागू होने से बहुत पहले था।

जी.

253. विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता के विनियमन 4.1.11 के उद्देश्य पर विचार किया और कहा कि यह प्रतिवादी पर लागू नहीं होता है। इसके अनुसार

एच.

754

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

उच्च न्यायालय, एकमात्र कारण था कि गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता का विनियमन 4.1.11 लागू नहीं था क्योंकि उक्त विनियम केवल आवेदक के बिजली बकाया पर आवेदन किया, और नहीं किया

आवेदक जो पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 254. उच्च न्यायालय ने यह नोटिस देना छोड़ दिया कि गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता 31 मार्च 2005 से लागू हुई, जबकि प्रतिवादी ने 13 अगस्त 2004 को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। इसलिए, प्रतिवादी ने गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता लागू होने से पहले कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। अतः उक्त विनियम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।

255. चूंकि प्रतिवादी ने 13 अगस्त 2004 को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, इसलिए 2003 का अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम तत्काल मामले में लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के समय उत्तरदाताओं को पिछले मालिक के बकाया बिजली का भुगतान करने की कोई वैधानिक शर्त नहीं थी।

ग

डी.

256. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की पूर्ववर्ती अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, 97 ने 14 अक्टूबर 1994 को आपूर्ति की शर्तों को अधिसूचित किया था और यह लागू होगी। 10 जून 2003 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि के लिए, जब बिजली आपूर्ति संहिता लागू हुई, 1994 की आपूर्ति की शर्तें 2003 के अधिनियम की धारा 185 (2) (ए) के संदर्भ में काम करती रहीं। 1994 की आपूर्ति शर्तों की शर्त 2 में प्रावधान किया गया है कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मांग उक्त शर्तों के अनुलग्नक ए में संलग्न मांग पत्र के अनुसार की जाएगी और उस परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है। उक्त शर्तों का अनुलग्नक ए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मांग का एक रूप प्रदान करता है। मांग प्रपत्र न केवल एक नए कनेक्शन तक सीमित है, बल्कि पुनः कनेक्शन, भार के विस्तार, कनेक्शन टैप करने और नाम परिवर्तन तक भी फैला हुआ है। प्रपत्र में आवेदक को हस्तांतरण की तारीख तक ऊर्जा बिलों और अन्य शुल्कों के सभी बकाया का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है। संबंधित उपक्रम नीचे दिया गया है:

ई.

च

जी.

“मैं/हम इसके द्वारा आवेदक के नाम पर उपर्युक्त सेवा को हस्तांतरित करने के लिए सहमति देते हैं और मैं/हम हस्तांतरण की तारीख तक ऊर्जा बिलों और अन्य शुल्कों के सभी बकाया का भुगतान करने का पालन करते हैं।”

97 “ईसी ”

एच.

755

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

257. अनुलग्नक ए के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त निकाला गया उपक्रम वास्तव में एक 'वर्तमान उपभोक्ता' का उपक्रम है जो सेवा कनेक्शन को हस्तांतरित करने के लिए सहमति देता है और पिछले सभी बकाया का भुगतान करने का वचन देता है। यह किसी आवेदक का वचन पत्र नहीं है, जिसके लिए उसी प्रपत्र में अलग से प्रावधान किया गया है। इसलिए, अनुलग्नक ए एक 'वर्तमान उपभोक्ता' और बिजली कनेक्शन के लिए एक आवेदक के बीच स्पष्ट अंतर करता है। चूंकि प्रत्यर्थी ने नीलामी-खरीद के माध्यम से उक्त संपत्ति खरीदी थी, इसलिए कोई सहमति देने के लिए कोई 'वर्तमान उपभोक्ता' नहीं था। इसलिए, प्रपत्र ए के तहत उपक्रम प्रत्यर्थी के लिए लागू नहीं होगा। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अपील खारिज हो जाएगी।

ग

वस्तु **101.4:** दक्षिण गुजरात विज कं. बनाम अपूर्वा केमिकल्स, **2012** का एसएलपी (सी) संख्या **37871** और **101.17:2013** की पश्चिम गुजरात विज कंपनी बनाम अपूर्वा केमिकल्स, एसएलपी (सी) संख्या **18220**

258. पिछले मालिक अरुणेश प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बिजली कनेक्शन जारी किया गया था। ऊर्जा बिलों का भुगतान न करने के कारण, बिजली आपूर्ति कंपनी के साथ समझौता 1 फरवरी 1995 से समाप्त कर दिया गया था। 1995 में, अपीलार्थी ने रुपये की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया। सिविल जज, सीनियर डिवीजन, वलसाड के समक्ष पिछले मालिक के खिलाफ 3 लाख 41 हजार। 2002 में, गुजरात विद्युत बोर्ड के पक्ष में मुकदमा चलाया गया, जो अपीलार्थी का पूर्ववर्ती था। अरुणेश प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2002 में बंद कर दिया गया था और इसकी संपत्तियों की नीलामी बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा "जैसा है जहां है" के आधार पर की गई थी। प्रत्यर्थी ने नीलामी की कार्यवाही में भाग लिया और वापी, गुजरात में अरुणेश प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों का अधिग्रहण किया। रुपये में प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की गई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2005 को 70 लाख। इसके बाद, 12 दिसंबर 2008 को आधिकारिक परिसमापक, बॉम्बे उच्च न्यायालय और प्रतिवादी के बीच एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया था। 2010 में, अपीलार्थी ने 2002 में मुकदमे में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए 2010 का डार्कहास्ट नंबर 7 दायर किया। 259.16 दिसंबर 2010 को, प्रतिवादी ने अपीलार्थी से गुजरात के वापी में भूखंड को बिजली की आपूर्ति जारी करने का अनुरोध किया। 3 जनवरी 2011 को, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि प्लॉट पर बिजली की आपूर्ति जारी नहीं की जा सकती क्योंकि 2010 का डार्कहास्ट नंबर 7 लंबित था और पिछले मालिक से बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी। चूंकि प्रतिवादी को उक्त भूखंड पर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पिछले मालिक के बकाया रुपये का भुगतान किया। 25 फरवरी 2011 को 17 लाख। हालांकि, 17 अगस्त 2011 को, प्रतिवादी

डी.

ई.

च

जी.

एच.

756

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया। अपीलार्थी ने यह तर्क देते हुए राशि वापस करने से इनकार कर दिया कि पिछले मालिक ने अभी तक उनके दावे की प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया था। प्रत्यर्थी ने गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता के खंड 4.1.11 को 2003 के अधिनियम के साथ असंगत होने के रूप में चुनौती देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर 2012 के विवादित फैसले में कहा कि आपूर्ति की शर्तों का खंड 2003 के अधिनियम के प्रावधानों से परे है।

260. यह संदेह से परे है कि प्रतिवादी ने अपीलार्थी से 16 दिसंबर 2010 को अपने परिसर में बिजली की आपूर्ति जारी करने का अनुरोध किया था। प्रासंगिक समय पर, संशोधित खंड 4.1.11 लागू था। 3 दिसंबर 2012 के विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य आयोग बिजली की आपूर्ति करने की पूर्व शर्त के रूप में नए मालिक से पिछले मालिक या कब्जाधारक के बकाया के भुगतान के लिए 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत एक शर्त निर्धारित करने के लिए अधिकृत नहीं है। यह भी कहा गया कि 2003 के अधिनियम की धारा 43 बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने से पहले परिसर से जुड़ी बिजली बकाया के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं लगाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वाक्यांश "उस परिसर से संबंधित कोई भी बकाया" बताता है कि परिसर को बिजली बकाया और शुल्क का चूककर्ता माना गया था, और यह 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत था। उपरोक्त कारणों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि खंड का पहला भाग 2003 के अधिनियम की धारा 43, 50, 56 और 181 के प्रावधानों के अधिकार से बाहर था।

ग

डी.

ई.

261. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड को परिसर से जुड़ी बिजली बकाया की वसूली के लिए नियम और शर्तें तैयार करने का अधिकार है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि नीलामी "जहां है उसी आधार पर" आयोजित की गई थी, इसलिए नीलामी खरीदार को खरीदी जा रही संपत्ति के बकाया के संबंध में उचित परिश्रम करने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी ने आगे कहा है कि बिजली की आपूर्ति बहाल करने या परिसर को नया कनेक्शन देने से पहले विशेष परिसर से संबंधित बकाया राशि का भुगतान करने की शर्त लगाने वाले नियमों को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, अपीलार्थी ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है।

च

जी.

262. दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि 2003 के अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो वितरण लाइसेंसधारी को ए लागू करने में सक्षम बनाता है।

एच.

757

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

पूर्व स्वामी या उनके परिसर से संबंधित देय राशि के भुगतान की पूर्व शर्त। यह आगे तर्क दिया गया है कि खंड 4.1.11 परिसर में बकाया राशि को चिपकाना 2003 के अधिनियम की धारा 43 के विपरीत है, जो उपभोक्ता पर बिजली बकाया और शुल्क का भुगतान करने का दायित्व लगाता है। परिसर से संबंधित बकाया संपत्ति पर एक वित्तीय बोझ होगा, और इस तरह भूमि की बिक्री के साथ हस्तांतरित किया जाएगा।²⁶³ तत्काल मामले में, खंड 4.1.11 के पहले भाग में प्रावधान है कि किसी भी परिसर के लिए बिजली आपूर्ति के लिए आवेदन पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि परिसर से संबंधित किसी भी बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त खंड इंगित करता है कि एक वितरण लाइसेंसधारी परिसर का कनेक्शन तब तक रोक सकता है जब तक कि उक्त परिसर के संबंध में उसका बकाया भुगतान नहीं कर दिया जाता है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गलती की है कि "उस परिसर से संबंधित कोई भी बकाया" वाक्यांश 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है। उक्त वाक्यांश के उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि परिसर को चूककर्ता माना जाता है और बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, जैसा कि उच्च न्यायालय सुझाव देता है। खंड 4 के अनुसार।¹ विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार, यह आवेदक है जिसे अनुलग्नक ए के संदर्भ में आवेदन करना होता है और परिसर से संबंधित पिछले मालिक के बिजली बकाया सहित सभी आवश्यक बिजली बकाया और शुल्क का भुगतान करना होता है। इस प्रकार, विद्युत आपूर्ति संहिता के समग्र अध्ययन पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उस परिसर से संबंधित पिछले उपभोक्ता के बकाया को परिसर के नए मालिक या अधिभोगियों से वापस लेने की मांग की जाती है।

ग

डी.

ई.

264. विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने एक बहुमंजिला आवासीय भवन का उदाहरण देते हुए कहा कि

अनुज्ञासिधारी सफलतापूर्वक मांग कर सकता है कि एक अलग फ्लैट का एक नया खरीदार जिसका विक्रेता चूककर्ता नहीं था, फिर भी उसी के दूसरे फ्लैट के चूक करने वाले उपभोक्ता के बकाया का भुगतान इस आधार पर करने के लिए उत्तरदायी होगा कि वह उसी परिसर का हिस्सा है।" इस संदर्भ में हम

च

पहले से ही यह माना गया है कि उपभोक्ता और परिसर के बीच एक तालमेल है। एक नया मालिक केवल उस परिसर के संबंध में पिछले मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकता है जिसमें बिजली कनेक्शन की मांग की जा रही है। इसलिए, "उस परिसर से संबंधित कोई भी बकाया" वाक्यांश को उस परिसर में की गई बिजली की आपूर्ति के संबंध में समझा जाना चाहिए जब यह पिछले मालिक के कब्जे में था।²⁶⁵ हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिजली का बकाया अपने आप परिसर पर शुल्क नहीं बन जाता है। एक सांविधिक प्रभार केवल तभी बनाया जाता है जब कानून का एक स्पष्ट प्रावधान होता है

जी.

एच.

758

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

अंतरिती पर वैधानिक प्रभार का सृजन। खंड 4.1.11 का संपत्ति पर शुल्क लगाने का प्रभाव नहीं है क्योंकि यह विशेष रूप से वैधानिक शुल्क के निर्माण के लिए प्रावधान नहीं करता है। इसके अलावा, "उस परिसर से संबंधित किसी भी बकाया" वाक्यांश की व्याख्या परिसर पर वित्तीय दायित्व लगाने के लिए नहीं की जा सकती है।

266. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2003 का अधिनियम विद्युत उपयोगिताओं को बाद के मालिक या अधिभोगकर्ता से पिछले उपभोक्ता के बकाया की वसूली के लिए शर्तें तैयार करने में सक्षम नहीं बनाता है। हम पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे विश्लेषण को देखते हुए उच्च न्यायालय के इस तर्क से असहमत हैं, जहां हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत उपयोगिताएँ इस आवश्यकता को निर्दिष्ट कर सकती हैं कि परिसर के बाद के मालिक या अधिभोगियों को बिजली कनेक्शन देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया का भुगतान करना होगा। हालाँकि, आपूर्ति के ऐसे नियम और शर्तें 2003 के अधिनियम की समग्र योजना और उद्देश्य के अनुरूप वैध और उचित होनी चाहिए।

ग

डी.

267. नतीजतन, हमने 2 दिसंबर 2012 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया। किसी भी लंबित आई. ए. का निपटान तदनुसार किया जाता है।

वस्तु **101.5**: मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम **2014** की कृषि उपज बाजार समिति, एसएलपी (सी) सं. **8197-8198**

ई.

268. राजप्रकाश स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड. 98 1967 से गुजरात विद्युत बोर्ड का उपभोक्ता था। 31 दिसंबर 1994 को बिजली बकाया का भुगतान न करने के कारण इसकी बिजली काट दी गई थी। 18 जुलाई 1995 को, गुजरात विद्युत बोर्ड ने आर. एस. एम. एल. के खिलाफ सिविल कोर्ट, नाडियाड में बिजली शुल्क की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया। 78 लाख। इस बीच, आर. एस. एम. एल. परिसमापन में चला गया और उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। 20 अगस्त 2002 को बिजली बोर्ड के पक्ष में मुकदमा चलाया गया। 2003 में, बोर्ड ने आधिकारिक परिसमापक के समक्ष एक करोड़ रुपये के मुकदमे में डिक्री के साथ दावा दायर किया। दिसंबर 2002 तक 78 लाख रुपये और कानूनी खर्च और ब्याज, जो कुल मिलाकर रु। 1. 39 करोड़।

च

जी.

269. 17 दिसंबर 2003 को, आधिकारिक परिसमापक ने प्रतिवादी के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। बिक्री विलेख में देय राशि के बारे में खरीदार के दायित्व का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 25 फरवरी 2004 को एक संशोधित बिक्री विलेख पंजीकृत किया गया और प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया।

98 “आरएसएमएल ”

एच.

759

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

और उक्त बिक्री विलेख को आधिकारिक परिसमापक द्वारा रुपये के विचार के लिए बिक्री की पुष्टि के अनुसरण में निष्पादित किया गया था। 97 लाख।

270. 10 अप्रैल 2007 को, प्रत्यर्थी ने बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए अपीलार्थी को एक पत्र लिखा। 13 अप्रैल 2007 को, अपीलार्थी ने एक नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया जब तक कि बिजली शुल्क रु। परिसर के खिलाफ बकाया 78 लाख का भुगतान किया गया। प्रतिवादी ने बिजली कनेक्शन देने के लिए एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका को 08 सितंबर 2009 के एक आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि जिस व्यक्ति ने परिसर खरीदा

था, उसे पिछले रहने वाले के बिजली बकाया का भुगतान करना था।डिवीजन बेंच ने 16 जुलाई 2013 के विवादित फैसले में कहा कि बाद वाला खरीदार पिछले मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ग

271. नीलामी-खरीदार ने 10 अप्रैल 2007 को एक नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता को 31 मार्च 2005 को अधिसूचित किया गया था।प्रासंगिक समय पर, असंशोधित विनियमन 4.1.11 लागू था, जिसके अनुसार केवल वितरण लाइसेंसधारी को नए कनेक्शन के अनुदान या बिजली आपूर्ति के पुनः कनेक्शन के लिए आवेदक के बकाया का भुगतान किया जाना था।उक्त विनियमन नए मालिक को पिछले मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करता था।इसलिए, प्रत्यर्थी को नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था।

डी.

ई.

272. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के 16 जुलाई 2013 के विवादित फैसले को बरकरार रखते हैं।अपील खारिज हो जाएगी।

च

वस्तु **101.6:टोरेंट पावर लिमिटेड बनाम मेसर्स शाश्वत होम्स प्राइवेट लिमिटेड; 2007 का एस. एल. पी. सं. 19878**

273. गुजरात स्टील ट्यूब कंपनी 99, जो कि पिछली मालिक थी, को परिसमापन कार्यवाही के अधीन किया गया था और 5 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के लिए बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। डेढ़ करोड़।गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जी. एस. टी. सी. को समाप्त करने का आदेश दिया गया था।जी. एस. टी. सी. की भूमि का एक हिस्सा नीलामी में स्पेक्ट्रा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रु। 42.10 करोड़।2006 में, उक्त पार्सल से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्यर्थी का नाम परिवर्तित हो गया।

जी.

99 "जी एस टी सी "

एच.

760

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

भूमि से।24 जनवरी 2007 को, प्रतिवादी ने परिसर के संबंध में बिजली के लिए एक नए कनेक्शन की मांग करते हुए अपीलार्थी से संपर्क किया।अपीलार्थी ने पिछले मालिक के बकाया बिजली के भुगतान तक नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया।प्रतिवादी ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।31 जनवरी 2014 के विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि बाद वाला मालिक पिछले मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।274. प्रत्यर्थी ने 24 जनवरी 2007 को नए बिजली कनेक्शन की मांग के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया।प्रासंगिक समय में, 2005 विद्युत आपूर्ति संहिता लागू थी।2005 के विद्युत आपूर्ति संहिता के विनियमन 4.1.11 में नए कनेक्शन के लिए आवेदन के समय केवल आवेदक के बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने की आवश्यकता थी।उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि असंशोधित विनियमन 4.1.11 प्रत्यर्थी पर लागू था, जो नीलामी-खरीदार है।वर्तमान के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 24 जनवरी 2007 को, जब नीलामी-खरीदार ने बिजली के लिए आवेदन किया था, तो असंशोधित खंड 4.1.11 चालू और लागू था।इसलिए, प्रत्यर्थी को उस संबंध में किसी भी स्पष्ट वैधानिक शर्त के अभाव में पिछले मालिक के बकाया का

भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखा गया है। अपील खारिज हो जाएगी।

ग

डी.

वस्तु **101.7**: दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम अमरदीप एसोसिएशन; एसएलपी (सी) सं। **2015** का **73**

ई.

275. 1994 में, नवसरी कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड 100 को एक बीमार औद्योगिक इकाई घोषित किया गया था। एन. सी. एस. एम. एल. के बंद होने की तारीख तक, इसका बिजली बकाया रु। 416.36 लाख। 17 अक्टूबर 1994 को बिजली की आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई थी। 15 दिसंबर 1996 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 101 ने एस. आई. सी. ए. की धारा 18 के तहत एक नई पुनर्वास योजना तैयार की। उक्त योजना में पैराग्राफ 2 (जी) के तहत एन. सी. एस. एम. एल. की अधिशेष भूमि की बिक्री का प्रावधान किया गया है:

च

“(छ) बुनाई खंड और प्रक्रिया गृह के संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ इसकी इमारत और कंपनी के पास अतिरिक्त भूमि का निपटान करने का प्रस्ताव है और बिक्री से प्राप्त आय लगभग रु। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 500 लाख रुपये का उपयोग किया जाएगा।”

जी.

100 “एन. सी. एस. एम. एल. “101” बी. आई. एफ. आर ”

एच.

761

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

276. 1996 की पुनर्वास योजना के अनुसार, गुजरात सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें (i) एन. सी. एस. एम. एल. की अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति; और (ii) एन. सी. एस. एम. एल. को पांच साल के लिए बिजली कटौती से छूट इस शर्त के साथ दी गई कि बकाया के मामले में कोई भी पुनः कनेक्शन शुल्क गुजरात विद्युत बोर्ड को किश्तों में दिया जाएगा। बाद में, 1997 में, एन. सी. एस. एम. एल. के श्रमिकों ने कंपनी की इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए मोरारजी देसाई टेक्सटाइल लेबर को-ऑपरेटिव सोसाइटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 102 के नाम से एक सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया।

277. 2003 में, बी. आई. एफ. आर. ने एक परिसंपत्ति बिक्री समिति का गठन करके उक्त कंपनी की अधिशेष भूमि के निपटान का निर्देश दिया। अतिरिक्त भूमि की बिक्री के लिए सूचना 2003 में गुजरात समाचार में प्रकाशित की गई थी, जिसके तहत भूमि को “जैसा है, जहां है” के आधार पर बेचा जाना था। नोटिस का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

ग

“B.I.F.R के आदेश के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या 336/1,311,310/1,310/2,310/5,310/7,307/1,308/1 वाली विजालपुर में स्थित भूमि, जिसके पास नवसरी कपास और रेशम मिलों का स्वामित्व है, भूमि के कुल मापने वाले क्षेत्र में से 11 लाख वर्ग फुट भूमि पर कब्जा होना चाहिए, जैसा कि प्रचलित कानूनों और नियमों के अनुसार आधार है।”

डी.

278. परिसंपत्ति बिक्री समिति ने प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए रुपये के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अधिशेष भूमि के लिए 561 लाख। 29 मई 2003 के बिक्री विलेख में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त खुली भूमि ग्रहणाधिकार और शुल्क सहित सभी बाधाओं से मुक्त थी। खंड 9

ई.

आगे निर्दिष्ट किया गया कि "अब तक के सभी करों, भूमि राजस्व, शिक्षा उपकर और अन्य बकाया का भुगतान कर दिया गया है और यदि कोई बकाया बकाया रहता है तो कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना है।"

च

279. 1 दिसंबर 2004 को, प्रतिवादी ने एक नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया। हालाँकि, अपीलार्थी ने तब तक नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया जब तक कि आपूर्ति की शर्तों के खंड 2 (जे) के संदर्भ में बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। 2006 में, प्रत्यर्थी ने बिजली आपूर्ति जारी करने के निर्देश के लिए बी. आई. एफ. आर. के समक्ष एक आवेदन दायर किया। 12 जून 2006 को बी. आई. एफ. आर. ने एक संशोधित पुनर्वास योजना को मंजूरी दी जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को बिजली कनेक्शन जारी करने का निर्देश दिया गया। चूंकि बिजली की आपूर्ति जारी नहीं की गई थी, इसलिए प्रतिवादी ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 2010 में, उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश

जी.

102 "एम डी टी एल सी आई एल "

एच.

762

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

अपीलार्थी को पिछले मालिक के बकाया के भुगतान पर जोर दिए बिना अधिशेष भूमि पर आवासीय प्रतिष्ठानों को बिजली कनेक्शन जारी करने का निर्देश देकर रिट याचिका की अनुमति दी। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 2 (जे) लागू नहीं था क्योंकि श्रमिक सहकारी समिति एक चालू चिंता थी और बिजली बोर्ड उनसे बकाया वसूल कर सकता है। डिवीजन बेंच ने 21 नवंबर 2014 के विवादित फैसले में एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बी. आई. एफ. आर. योजना अपीलार्थी पर बाध्यकारी होगी, भले ही वे कार्यवाही में पक्षकार न हों। यह भी माना गया कि एस. आई. सी. ए. 2003 के अधिनियम की तुलना में एक विशेष अधिनियम है। इसलिए एस. आई. सी. ए. के तहत बनाई गई एक योजना को आपूर्ति की शर्तों के खंड 2 (जे) पर एक प्रमुख प्रभाव माना गया था।

ग

280. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि बी. आई. एफ. आर. योजना के अनुसार, बिजली कनेक्शन एम. डी. टी. एल. सी. आई. एल. को अलग से प्रदान किया गया था न कि प्रत्यर्थी को बेची गई अधिशेष भूमि को। इसलिए, प्रत्यर्थी से कोई बकाया वसूल नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि बी. आई. एफ. आर. द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजनाओं का आपूर्ति की शर्तों के खंड 2 (जे) के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है। उत्तरदाताओं ने बिक्री विलेख के खंड 3 और 9 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उत्तरदाता को एन. सी. एस. एम. एल. के पिछले बकाया के भुगतान से छूट दी गई है। उक्त खंडों को नीचे निकाला गया है:

डी.

ई.

“(3) [.....] उक्त संपत्ति पर कोई ऋण यानी ग्रहणाधिकार या किसी का आरोप नहीं है और यह किसी भी अदालत के जब्त, कुर्की या निषेधाज्ञा के तहत नहीं है।[.....] उक्त संपत्ति पर, किसी के पास रखरखाव और निवास शुल्क नहीं है, उक्त संपत्ति पर आयकर, बिक्री कर आदि जैसे सरकारी करों/शुल्कों का कोई शुल्क नहीं है।सरकार या स्थानीय निकाय का कोई अधिग्रहण, मांग या आरक्षण नहीं है या उस इरादे से कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है।संक्षेप में, बंधक, दावेदार, शेयरधारक या अन्य तरीके से या उक्त संपत्ति में किसी अन्य हित के रूप में सही स्वामित्व या दावे का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है और कंपनी के पास सभी तरह से उक्त संपत्ति के प्रबंधन के लिए सभी अधिकार और अधिकार हैं और इस तरह का विश्वास और आश्वासन देकर, कंपनी ने इस बिक्री विलेख को निष्पादित किया है।और भले ही, भविष्य में, कोई व्यक्ति संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है, तो उसका जोखिम कंपनी पर है और वह है यदि ऐसे अधिकार या अध्याय के कारण यदि आपके या आपके उत्तराधिकारियों द्वारा कोई नुकसान या व्यय हुआ है, तो उसे कंपनी द्वारा चुकाया जाना है।”

च

जी.

एच.

763

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

[.....]

(9) उक्त संपत्ति से संबंधित सभी करों, भूमि राजस्व, शिक्षा उपकर और अन्य खर्चों और अब तक के बकाया का भुगतान कर दिया गया है और यदि कोई बकाया भुगतान किया जाना बाकी है तो कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना है।अब से उक्त संपत्ति से संबंधित सभी करों आदि के भुगतान की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी।इस विलेख के समर्थन से खरीदार सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्थानीय अभिलेखों, नगर सर्वेक्षण अभिलेखों और नगरपालिका अभिलेखों में उक्त संपत्ति पर अपना नाम दर्ज कर सकता है और इसके लिए हमें अपने हस्ताक्षर, सहमति और ऐसी हस्ताक्षरित सहमति देनी होगी जिस पर विचार किया जा रहा है।”

ग

(जोर दिया गया) 281।इस मुद्दे को तय करने के लिए, हमारे सामने जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या एस. आई. सी. ए. 1910 के अधिनियम और 2003 के अधिनियम के संबंध में विशेष कानून है। एस. आई. सी. ए. को बीमार कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में किए जाने वाले निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपायों के त्वरित निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया था।धारा 18 ने बी. आई. एफ. आर. जैसी संचालन एजेंसी को योजना में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर बीमार औद्योगिक कंपनी के व्यवसाय, संपत्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अनिवार्य किया।एस. आई. सी. ए. की धारा 18 (8) के अनुसार, एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, यह बीमार औद्योगिक कंपनी के साथ-साथ बीमार औद्योगिक कंपनी के शेयरधारकों, लेनदारों और गारंटर्स के लिए बाध्यकारी है। एस. आई. सी. ए. की धारा 32 ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी भी नियम या योजनाओं को प्रबल प्रभाव दिया:

डी.

ई.

“32. अन्य कानूनों पर अधिनियम का प्रभाव।—(1) इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या योजनाओं के प्रावधान इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

च

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) के प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य कानून में निहित, कुछ समय के लिए या किसी औद्योगिक कंपनी के ज्ञापन या संघ के अनुच्छेदों में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी अन्य लिखत में।

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

764 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

282. टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम भारत के फार्मास्युटिकल उत्पाद

लिमिटेड **103** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस. आई. सी. ए. कंपनी अधिनियम की तुलना में एक विशेष विधान है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“22. एक विशेष अधिनियम के प्रावधान एक सामान्य अधिनियम के प्रावधानों पर हावी होंगे। इसके बाद वाला (एस. आई. सी. एक्ट) पहले के एक अधिनियम को ओवरराइड करेगा। 1956 का अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है। यह.

कंपनियों और कुछ अन्य संघों से संबंधित कानून को समेकित और दोहराता है। यह एस. आई. सी. ए. से पहले का समय है।

23. जहां भी दोनों अधिनियमों के प्रावधानों में कोई विसंगति देखी जाएगी, एस. आई. सी. ए. प्रबल होगा। इसके अलावा एस. आई. सी. ए. एक पूर्ण कोड है। इसमें धारा **32** में एक गैर-बाध्यकारी खंड शामिल है।

ग

24. एस. आई. सी. ए. एक विशेष कानून है। यह एक स्व-निहित कोड है।

ऐसे मामले में जहां बी. आई. एफ. आर. को निर्देश दिया गया था, कंपनी न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों के अधीन होगा।

डी.

(जोर दिया गया) 283। 2003 के अधिनियम में भी एस. आई. सी. ए. की धारा 32 के समान प्रावधान है। 2003 के अधिनियम की धारा 174 में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद प्रबल प्रभाव डालेंगे। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि एस. आई. सी. ए. और 2003 अधिनियम दोनों अपने-अपने क्षेत्र में विशेष कानून हैं। 284. एल. आई. सी. बनाम डी. जे. बहादुर, 104 में इस न्यायालय का सामना इस सवाल से किया गया था कि क्या एल. आई. सी. अधिनियम एक विशेष विधान है या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संबंध में एक सामान्य विधान है। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि यह निर्धारित करने में कि क्या कोई विशेष कानून सामान्य है या विशेष, मुख्य विषय वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस अवलोकन के आधार पर कि कोई विधान कुछ उद्देश्यों के लिए सामान्य और अन्य उद्देश्यों के लिए विशेष हो सकता है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक विशेष कानून होने के कारण एल. आई. सी. अधिनियम पर प्रबल है। यह आयोजित किया गया था:

ई.

च

जी.

“52. यह निर्धारित करने में कि कोई कानून विशेष है या सामान्य, ध्यान मुख्य विषय-वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए। कुछ उद्देश्यों के लिए, एक अधिनियम सामान्य हो सकता है

103 (2008) 7 एससीसी 619 104 (1981) 1 एससीसी 315 ए

एच.

765

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और हम कानून के सूक्ष्म बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर को धुंधला नहीं कर सकते हैं। कानून में, हमारे पास सापेक्षता का एक ब्रह्मांड है, निरपेक्ष नहीं-जीवन में भी ऐसा ही है।”

285. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरि शंकर जैन, 105 ए

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि क्या औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एक विशेष कानून है और सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में 1948 के अधिनियम को ओवरराइड करता है। न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी ने पीठ की ओर से कहा कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एक विशेष कानून है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सेवा की शर्तों से संबंधित है। दूसरी ओर, 1948 का अधिनियम बिजली के विकास के समन्वय के लिए एक अधिनियम है, और राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने का प्रयास नहीं करता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1948 का अधिनियम बिजली के विकास के संबंध में एक विशेष विधान है। यह देखा गया:

ग

“7. [.....] विद्युत आपूर्ति अधिनियम को राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला अधिनियम नहीं माना जाता है। यह बिजली के समन्वित विकास को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम है। यह बिजली के विकास के संबंध में एक विशेष अधिनियम है, भले ही औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सेवा की शर्तों के संबंध में एक विशेष अधिनियम है। यदि विद्युत आपूर्ति अधिनियम की धारा 79 (सी) आम तौर पर बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए विनियम बनाने का प्रावधान करती है, तो इसे केवल एक सामान्य प्रावधान के रूप में माना जा सकता है जो औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

डी.

ई.

च

286. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एस. आई. सी. ए. और 2003 के अधिनियम की विषय वस्तु की जांच करना आवश्यक है। एस. आई. सी. ए. के तहत, संचालन एजेंसी को वित्तीय पुनर्निर्माण, उचित प्रबंधन, एकीकरण और किसी भी अन्य निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के लिए एक बीमार औद्योगिक कंपनी के संबंध में एक योजना तैयार करनी थी। दूसरी ओर, 2003 का अधिनियम बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित एक समेकित कानून है। 2003 का अधिनियम विशेष रूप से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति से संबंधित है।

जी.

105 (1978) 4 एससीसी 16

एच.

जबकि एस. आई. सी. ए. उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के पहलुओं पर चुप है। एस. आई. सी. ए. का प्रमुख विषय बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए सुधारात्मक उपाय प्रदान करना है, जबकि 2003 के अधिनियम का उद्देश्य बिजली उद्योग का विकास है। इस प्रकार, दोनों अधिनियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। 2003 का अधिनियम एक बाद का अधिनियम है, और धारा 175 विशेष रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त हैं और एस. आई. सी. ए. सहित उस समय लागू किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं हैं।

287. केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड, 106 ए

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को यह तय करने के लिए बुलाया गया था कि एस. आई. सी. ए. और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 107 के बीच कौन सा अधिनियम दूसरे पर प्रबल होगा। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि दोनों विधान अपने-अपने विषय मामलों के संबंध में विशेष कानून हैं, एस. आई. सी. ए. आर. डी. डी. बी. अधिनियम में गैर-विवाद खंड को शामिल करने के आधार पर आर. डी. डी. बी. अधिनियम पर हावी होगा। आर. डी. डी. बी. अधिनियम में, संसद ने विशेष रूप से प्रावधान किया था कि आर. डी. डी. बी. अधिनियम एस. आई. सी. ए. सहित उसमें उल्लिखित अन्य कानूनों के अतिरिक्त होगा और उनका अपमान नहीं करेगा:

ग

डी.

"49. "अपमान में नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से संसद के इरादे को व्यक्त करता है कि वह किसी भी तरह से एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों को कम या निरस्त नहीं करेगी। वास्तव में इसका मतलब यह होना चाहिए कि संसद का इरादा एक बीमार कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही जारी रखने का था और उस उद्देश्य के लिए आगे यह इरादा था कि कंपनी और उसकी संपत्तियों के खिलाफ अन्य सभी कार्यवाही को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तक रोक दिया जाना चाहिए। जबकि शब्द

ई.

"एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के तहत कार्यवाही में मूल रूप से आर. डी. डी. बी. अधिनियम शामिल नहीं था, जो अस्तित्व में नहीं था, धारा 22 आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत कार्यवाही को शामिल करती है।

च

(जोर दिया गया) 288। इसी तरह, 2003 के अधिनियम की धारा 175 में प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त हैं और वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं हैं। इसलिए, विशेष रूप से यह प्रावधान करके कि 2003 का अधिनियम कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होगा और उसका अपमान नहीं करेगा, संसद ने संरक्षित किया है और

जी.

106 (2015) 1 एस. सी. सी. 166 107 आर. डी. डी. बी. अधिनियम

एच.

क.

एस. आई. सी. ए. के अधीन कार्यवाही को प्राथमिकता। एस. आई. सी. ए. की धारा 32 इसके तहत बनाई गई योजना को एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करती है। एस. आई. सी. ए. की धारा 18 बी. आई. एफ. आर. जैसी संचालन एजेंसी को योजना में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर बीमार औद्योगिक कंपनी के व्यवसाय, संपत्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करने का आदेश देती है।

289. एस. आई. सी. ए. एक विशेष कानून है और एस. आई. सी. ए. की धारा 18 (8) के साथ पठित धारा 32 योजना को एक प्रमुख प्रभाव देती है। 1996 की पुनर्वास योजना और 2006 की संशोधित पुनर्वास योजना अपीलार्थी को बाध्य करती है, लेकिन आपूर्ति के नियमों और शर्तों के खंड 2 (जे) को ओवरराइड करती है।

ग

290. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून की उपरोक्त स्थिति को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने बी. आई. एफ. आर. द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजना के अनुसरण में एन. सी. एस. एम. एल. की 'अधिशेष भूमि' खरीदी। जब 2003 में प्रत्यर्थी को भूमि का कब्जा दिया गया था, तो एन. सी. एस. एम. एल. एक चालू चिंता थी क्योंकि इसका संचालन एम. डी. टी. एल. सी. आई. एल. द्वारा जारी रखा गया था। बिक्री विलेख के प्रासंगिक खंडों ने प्रतिवादी को एन. सी. एस. एम. एल. के पिछले बकाया से स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया। वास्तव में, बिक्री विलेख के खंड 9 ने दोहराया कि एन. सी. एस. एम. एल. भूमि से संबंधित किसी भी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, 2006 की संशोधित पुनर्वास योजना केवल एन. सी. एस. एम. एल. पर बिजली बकाया की निकासी की जिम्मेदारी डालती है, जबकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को बिजली कनेक्शन जारी करने का निर्देश देती है। इस प्रकार, एन. सी. एस. एम. एल. उपभोक्ता होने के नाते, उक्त परिसर से संबंधित बिजली के बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य था। अपीलार्थी केवल एन. सी. एस. एम. एल. से देय राशि की वसूली कर सकता था, क्योंकि यह उस समय एक चिंता का विषय था जब प्रतिवादी ने बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था। यह स्वीकार्य मामला है कि अपीलार्थी ने एन. सी. एस. एम. एल. से बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी। उच्च न्यायालय के 14 जून 2010 के फैसले में यह देखा गया है:

डी.

ई.

च

“इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी द्वारा एन. सी. एस. एम. एल. के खिलाफ कोई वसूली नहीं की गई थी। यदि एन. सी. एस. एम. एल. के खिलाफ कोई वसूली नहीं की गई थी, तो याचिकाकर्ता (इसमें प्रतिवादी) के खिलाफ बकाया की मांग जो एन. सी. एस. एम. एल. द्वारा भूमि मालिकों के हिस्से का खरीदार है, टिकाऊ नहीं है।”

जी.

291. उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अपीलकर्ता पिछले बिजली बकाया की मांग की आड़ में प्रतिवादी को चुनिंदा रूप से बिजली नहीं रोक सकता है। अपीलार्थी के रुख का विरोध किया जाता है

एच.

768

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

बी. आई. एफ. आर. द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजना के लिए। बी. आई. एफ. आर. द्वारा तैयार की गई संशोधित पुनर्वास योजना एस. आई. सी. ए. की धारा 18 (8) के आधार पर अपीलार्थी के लिए बाध्यकारी होगी। उक्त प्रावधान के अनुसार, एक

बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, यह न केवल बीमार औद्योगिक कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी को बल्कि अपीलकर्ता जैसे लेनदारों को भी बाध्य करेगी। वैधानिक प्रावधान नीचे दिया गया है:

“18. योजनाओं की तैयारी और मंजूरी -

(8) स्वीकृत योजना या उसके किसी प्रावधान के लागू होने की तारीख को और उसके बाद से, योजना या ऐसा प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी या, जैसा भी मामला हो, दूसरी कंपनी और उक्त कंपनियों के शेयरधारकों, लेनदारों और गारंटर्स और कर्मचारियों पर भी बाध्यकारी होगा।”

ग

292. 20 मार्च 2015 को, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शर्तों में विवादित फैसले के संचालन पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया:

डी.

“गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुल बकाया राशि के 50 प्रतिशत की बैंक गारंटी देने के अधीन रोक लगा दी गई है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त बैंक गारंटी देने पर ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

ई.

ऐसे खरीदार जो याचिकाकर्ता को देय राशि का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति है। याचिकाकर्ता गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करेगा और बिजली कनेक्शन प्रदान करने पर निर्णय लेगा।”

च

293. हम तदनुसार 21 नवंबर 2014 के विवादित फैसले पर लगी रोक को हटा देते हैं। प्रत्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी राशि वापस कर दी जाएगी। अपील खारिज हो जाएगी।

वस्तु **101.8:** पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम सरिफाबेन महबूबभाई सोलंकी, एसएलपी (सी) सं।

जी.

294. पिछले मालिक कांति कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की बिजली आपूर्ति 09 जून 1981 को काट दी गई थी। इस मिल को बॉम्बे राहत उपक्रम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत एक 'राहत उपक्रम' माना गया था। 1982 में गुजरात राज्य ए

एच.

769

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

कपड़ा निगम 108 ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत मिल का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 1996 में बी. आई. एफ. आर. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि भारी नुकसान हो रहा है और एस. आई. सी. ए. की धारा 20 के तहत इसे समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। 1997 में, कंपनी अदालत ने बंद करने का आदेश दिया और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। 21 अक्टूबर 1997 को, जी. एस. टी. सी. ने समापन की कार्यवाही को देखते हुए बिजली की आपूर्ति को काटने का अनुरोध किया। 22 जुलाई 1998 को अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक अदालती नीलामी आयोजित की गई थी। जय महाकाली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 109 के प्रस्ताव को स्वीकार्य पाया गया

और उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। 28 जून 2004 को जे. एम. आई. पी. एल. के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। 5.5 करोड़।

ग

295. 23 मई 2005 को, अपीलार्थी ने जे. एम. आई. पी. एल. को एक नोटिस दिया जिसमें रुपये के भुगतान की मांग की गई। 2.3 करोड़। 05 सितंबर 2006 को, एक एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे जे. एम. आई. पी. एल. द्वारा यह कहते हुए स्थापित किया गया था कि बिजली बकाया के लिए अपीलार्थी का दावा, धन दावे की प्रकृति में होने के कारण, 3 साल के भीतर दायर किया जाना आवश्यक था, और इसे सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। डिवीजन बेंच द्वारा 04 अप्रैल 2014 के एक फैसले द्वारा अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी के लिए उपलब्ध उचित उपाय एक दीवानी मुकदमा दायर करना या गारंटी आदेश प्राप्त करना था ताकि खरीदार को पता चल सके कि संपत्ति पर एक देयता है। 16 दिसंबर 2016 को उच्च न्यायालय ने विलंब के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। 296. उत्तरदाताओं ने 2012 में जे. एम. आई. पी. एल. से एक छोटा आवासीय घर खरीदा। 4 अक्टूबर 2014 को, उत्तरदाताओं ने बिजली कनेक्शन देने के लिए आवेदन किया। चूंकि अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जिसमें पहले के मालिक के बकाया पर जोर दिए बिना कनेक्शन की मांग की गई क्योंकि उन्होंने जे. एम. आई. पी. एल. से भूखंड खरीदा था। फोरम ने बिजली आपूर्ति संहिता के खंड 4.1.11 के आलोक में मामले का निपटारा किया, जिसे 2010 में संशोधित किया गया था। प्रत्यर्थी ने विद्युत लोकपाल से संपर्क किया, जिन्होंने 30 मार्च 2015 के एक आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए अपीलार्थी को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के पिछले आदेश पर भरोसा किया। अपीलकर्ताओं ने लोकपाल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष नागरिक आवेदन दायर किया। 16 फरवरी 2016 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया। 8 तारीख के फैसले द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ

डी.

ई.

च

जी.

108 "जी. एस. टी. सी. "109" जे. एम. आई. पी. एल "

एच.

770

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

सितंबर 2017 ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि 4 अप्रैल 2014 के आदेश के खिलाफ इस अदालत के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका 110 को खारिज कर दिया गया था।

297. यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी के पूर्ववर्ती शीर्षक जे. एम. आई. पी. एल. को बिजली कनेक्शन देने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि, जे. एम. आई. पी. एल. ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी। अपीलार्थी ने एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 04 अप्रैल 2014 के एक फैसले द्वारा सीमा के आधार पर खारिज कर दिया था। लोकपाल ने 30 मार्च 2015 के अपने आदेश में डिवीजन बेंच के इस फैसले के आधार पर अपना निर्णय दिया। 04 अप्रैल 2014 के फैसले को अंतिम रूप दिया गया। बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने का प्रत्यर्थी का अधिकार अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने पर अंतिम रूप प्राप्त करने वाले निर्णय पर स्पष्ट हो गया। इसलिए, लोकपाल द्वारा पारित आदेश और लोकपाल के निर्णय की पुष्टि

करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को इसी कारण बरकरार रखा गया है। अपील खारिज हो जाएगी।

ग

डी.

वस्तु **101.16**: टोरेट पावर लिमिटेड बनाम **2013** का मेसर्स अभिसार डेवलपर्स, एसएलपी (सी) **9092-9094**

298. 1 सितंबर 1986 को, न्यू गुजरात सिंथेटिक कंपनी, जो पिछली मालिक थी, परिसमापन में चली गई। 12 सितंबर 1986 को बकाया राशि का भुगतान न करने पर पिछले मालिक के परिसर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। 77 लाख। 12 अक्टूबर 2006 को, पिछले मालिक की अचल संपत्तियों की एक सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें उनके परिसर भी शामिल थे। इन्हें स्टार एसोसिएट्स द्वारा खरीदा गया था और इसमें प्रतिवादी अभिसार डेवलपर्स को सूचित किया गया था।

ई.

च

299. 28 दिसंबर 2006 को, प्रतिवादी-खरीदार ने परिसर के लिए एक नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया। हालाँकि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से परिसर के बकाया का भुगतान करने का आह्वान किया। 2007 में, प्रतिवादी ने गुजरात के उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें बकाया के भुगतान के बिना नए कनेक्शन के लिए अनुरोध किया गया। 2010 में, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और लाइसेंसधारी को कनेक्शन प्रदान करने का निर्देश दिया। 3 दिसंबर 2012 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने

जी.

एच.

110 2017 ए की डायरी संख्या 23261

771

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

यह अभिनिर्धारित किया गया कि गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता का खंड 4.1.11, जैसा कि 2010 में संशोधित किया गया था, 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार से बाहर है।

300. अपीलार्थी ने खंड 4.1.16, 4.8 का उल्लेख किया है। 1, और 4.8। 4 विद्युत आपूर्ति संहिता का यह तर्क देना कि नीलामी-खरीदार परिसर के बकाया भुगतान की आवश्यकता के बारे में जानकारी से इनकार नहीं कर सकता है। जवाब में, नीलामी-खरीदार ने प्रस्तुत किया है कि नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में बाद के मालिक से पिछले मालिक के बकाया के भुगतान की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक समय पर कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था।

301. प्रासंगिक खंड 4.1.16, 4.8। 1, और 4.8। 4 2005 के विद्युत आपूर्ति संहिता को नीचे निकाला गया है:

ग

“4.1.16 वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर कोई बकाया प्रमाण पत्र नहीं देगा ताकि नया घर/परिसर खरीदते समय पिछले मालिक के बकाया होने की किसी भी संभावना से बचा जा सके। [.....]

डी.

4.8.1 उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना वितरण लाइसेंसधारी के साथ निष्पादित समझौते के लाभ के साथ आवंटन, हस्तांतरण या भाग नहीं करेगा और न ही किसी भी तरह से किसी भी आंशिक या अलग ब्याज के साथ भाग लेगा या बनाएगा। यदि पंजीकृत उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है या संपत्ति का स्वामित्व या व्यवसाय बदल गया है या स्थानांतरित हो गया है, तो आवेदन पर सेवा कनेक्शन का हस्तांतरण प्रभावी होगा। इस तरह के हस्तांतरण के सभी मामलों में, प्रत्येक विवरण के बकाया का भुगतान संबंधित जी. ई. आर. सी. विनियमों में निर्धारित हस्तांतरण शुल्क के साथ किया जाएगा।

ई.

च

[.....]

4.8.4 जहां लाइसेंसधारी द्वारा जिन परिसरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है, उन्हें हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है और हस्तांतरणकर्ता को अपने नाम पर स्थानांतरित किए गए परिसरों में सेवा कनेक्शन नहीं मिलता है, और वह पिछले नाम से सेवा कनेक्शन का उपयोग करना जारी रखता है, तो हस्तांतरणकर्ता चालू ऊर्जा बिलों के साथ-साथ ऊर्जा बिलों के बकाया और सेवा कनेक्शन से संबंधित अन्य राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। वितरण अनुज्ञापिधारक को देय राशि मांग पर देय होगी, जिसमें चूक होने पर परिसरों को आपूर्ति काट दी जा सकती है, जो उस समय लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन है।”

जी.

एच.

772

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

302. गुजरात विद्युत आपूर्ति संहिता के खंड 4.1.16 ने वितरण लाइसेंसधारी को अनुरोध करने पर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए बाध्य किया।

एक उपभोक्ता द्वारा "नया घर/परिसर खरीदते समय पिछले मालिक के बकाया बकाया की किसी भी संभावना से बचने के लिए।” यह केवल

एक प्रक्रियात्मक प्रावधान और स्वयं परिसर के बाद के मालिक पर कोई दायित्व नहीं लगाता है। "उपभोक्ता" शब्द नीलामी-खरीदार को खंड 4.1.16 के दायरे में नहीं लाएगा क्योंकि नीलामी-खरीदार वितरण लाइसेंसधारी के साथ समझौता करने से पहले उपभोक्ता नहीं बन जाता है।

303. खंड 4.8 के अनुसार। 1, उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी की पूर्व सहमति के बिना सेवा कनेक्शन हस्तांतरित नहीं करेगा। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत उपभोक्ता की मृत्यु होने या संपत्ति का स्वामित्व या व्यवसाय बदलने या हस्तांतरित होने की स्थिति में आवेदन पर सेवा कनेक्शन का हस्तांतरण प्रभावित होगा। हस्तांतरण के मामले में, खंड में प्रावधान है कि प्रत्येक विवरण के बकाया का हस्तांतरण शुल्क के साथ पूरा भुगतान किया जाएगा। हालांकि, उक्त प्रावधान केवल उन स्थितियों में लागू होता है जहां सेवा कनेक्शन का हस्तांतरण हुआ है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम एक ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जहां नीलामी-खरीदार ने परिसर में बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। अतः, खंड 4.8।1 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

ग

डी.

304. खंड 4.8।4 यह प्रावधान है कि परिसर का हस्तांतरणकर्ता चूककर्ता हस्तांतरणकर्ता के ऊर्जा बिलों के अवैतनिक बकाया के लिए केवल तभी उत्तरदायी होगा जब वे अपने नाम पर स्थानांतरित किए बिना पिछले नाम में सेवा कनेक्शन का उपयोग करना जारी रखेंगे। उक्त खंड केवल तभी लागू होता है जब कोई हस्तांतरणकर्ता कनेक्शन के हस्तांतरण के लिए आवेदन करता है, न कि जहां कोई हस्तांतरणकर्ता अपने नाम से नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है। 305. वर्तमान मामले में, तथ्यों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने 28 दिसंबर 2006 को परिसर के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा बिजली के लिए आवेदन जमा करने की तारीख को, गुजरात बिजली आपूर्ति संहिता का असंशोधित खंड 4.1.11 लागू था, जिसके अनुसार केवल वितरण लाइसेंसधारी को आवेदक का बकाया एक नए कनेक्शन या बिजली आपूर्ति के पुनः कनेक्शन के लिए दिया जाना था। नीलामी खरीदारों को नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था।

ई.

च

जी.

एच.

773

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

306. यह केवल 2010 में था कि उक्त बिजली आपूर्ति संहिता के खंड 4.1.11 में संशोधन किया गया था, जिसमें परिसर के बाद के मालिक को नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, उस समय जब प्रत्यर्थी ने बिजली आपूर्ति के नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, परिसर से जुड़े पिछले मालिक के बकाया का भुगतान करने के लिए नए कनेक्शन के आवेदक की आवश्यकता का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय के 3 दिसंबर 2012 के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। अपील खारिज हो जाएगी।

IV. असम

307. असम विद्युत नियामक आयोग ने बिजली शुल्क की वसूली के लिए 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 30 अगस्त 2004 को ए. ई. आर. सी. आपूर्ति संहिता तैयार की। खंड 3 आपूर्ति की मांग से संबंधित है। खंड 3.4 इसे नीचे निकाला गया है:

ग

“ 3.6.4 किसी नई संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के मामले में, यह उस व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह पिछले महीनों के बिलों की जांच करे या आपूर्ति बंद होने की स्थिति में, अपने कब्जे से तुरंत पहले लाइसेंसधारी के रिकॉर्ड के अनुसार देय राशि की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के अनुसार सीमा के अधीन बिलों में निर्दिष्ट सभी बकाया बिजली बकाया का विधिवत भुगतान और भुगतान किया जाए। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर ऐसे परिसर में कनेक्शन से बकाया राशि का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य होगा।”

डी.

ई.

विवादित खंड परिसर के एक नए अधिभोगियों को पिछले महीनों के बिलों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि सभी बकाया राशियों का विधिवत भुगतान किया जाए और उनका भुगतान किया जाए।

च

वस्तु 101.15: कार्बन संसाधन बनाम असम विद्युत नियामक आयोग; 2010 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 24502

308. पिछले मालिक, ईस्टर्न स्टील एंड अलॉयज कंपनी लिमिटेड के पास 1988-1989 अवधि के लिए बिजली का बकाया था, जिसके कारण 1992 में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। असम राज्य विद्युत बोर्ड 111 ने पिछले मालिक के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष धन का मुकदमा दायर किया, जिसे 24 फरवरी को 2 करोड़ 07 लाख रुपये में उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया।

जी.

111 "ए. एस. ई. बी "

एच.

774

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

1997. यूको बैंक की देनदारियों के कारण, 30 जून 2004 को कुर्की का वारंट लगाया गया था।

309. 2002 में, यूको बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष पिछले मालिक के खिलाफ एक आवेदन को प्राथमिकता दी। 16 मार्च 2007 को, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी के वसूली अधिकारी ने विचाराधीन भूमि के लिए नीलामी बिक्री नोटिस जारी किया। नीलामी बिक्री के नोटिस के खंड 7 में निर्धारित किया गया था कि संपत्तियों को "जैसा है वैसा ही" आधार पर बेचा जा रहा था और यह आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन था। अपीलकर्ता सबसे अधिक बोली लगाने वाला था और उसे 20 फरवरी 2008 को नीलामी-खरीदार घोषित किया गया था। 24 मार्च 2008 को, अपीलार्थी के पक्ष में एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था और 27 मार्च 2008 को यूको बैंक द्वारा अपीलार्थी को कब्जा सौंप दिया गया था। वसूली अधिकारी ने अपीलार्थी के पक्ष में नीलामी बिक्री की पुष्टि की, जिसने 27 मार्च 2008 को संपत्ति का कब्जा ले लिया। 21 जनवरी 2009 को, अपीलार्थी ने उच्च-तनाव वाले उद्योगों के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया, लेकिन पिछले मालिक के बकाया बकाया के कारण ए. एस. ई. बी. ने इसे अस्वीकार कर दिया।

ग

डी.

310. इसलिए, अपीलार्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया था: (i) पिछले मालिक के बकाया का भुगतान किए बिना बिजली कनेक्शन; और (ii) विनियमन सं. 3.6 के अधिकारों को चुनौती देना। 4 ए. ई. आर. सी. विद्युत आपूर्ति संहिता। 2 जून 2010 को, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए एक फैसला सुनाया।

ई.

311. अपीलार्थी ने इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि प्रत्यर्थी ने पिछले उपभोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें एक डिक्री पारित की गई थी। अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि पिछले मालिक के बकाया की वसूली डिक्री के निष्पादन में प्रभावी हो सकती है। तथ्यों के अवलोकन से, यह सच है कि प्रतिवादी ने पहले ही पिछले उपभोक्ता के खिलाफ धन का मुकदमा दायर कर दिया था और एक डिक्री प्राप्त की थी। हालाँकि, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि निष्पादन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका। इन कार्यवाही में, हम पिछले मालिक के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही की वैधता से चिंतित नहीं हैं। 312. प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि परिसर खरीदने से पहले, अपीलार्थी को उचित सावधानी बरतने और यह सत्यापित करने की आवश्यकता थी कि परिसर के संबंध में कोई बिजली बकाया नहीं थी। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री की वैधता पर भी इस आधार पर सवाल उठाया है कि ए में एक स्थायी धन डिक्री थी।

च

जी.

एच.

775

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

प्रत्यर्थी के पक्ष में और परिसर अदालत की कुर्की के अधीन थे। प्रत्यर्थी ने 29 नवंबर 2004 के राज्य सरकार के एक आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों को बिजली बकाया की निकासी के बिना भूमि की बिक्री/हस्तांतरण की अनुमति जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था। 26 जून 2006 को, बिजली वितरण कंपनियों ने एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें नए उपभोक्ताओं को पिछले उपभोक्ता के बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता थी। उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

“यह देखा गया है कि कुछ बिजली उपभोक्ता जिनके पास ऊर्जा खपत के लिए देय बकाया है, वे बिजली बकाया का भुगतान किए बिना अपने परिसर (भूमि और भवन सहित) को बेचने या पट्टे पर देने की कोशिश कर रहे हैं।

ग

असम सरकार ने पहले ही परिसरों के इस तरह के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है और हस्तांतरण की अनुमति के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से बिजली बकाया निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

डी.

सभी संभावित खरीदारों या पट्टेदार से अनुरोध है कि वे ऐसे परिसर का कब्जा लेने से पहले बिजली बकाया की निकासी के संबंध में खुद को संतुष्ट करें।

पिछले मालिक द्वारा बिजली बकाया की देनदारियों का निर्वहन न करने की स्थिति में, खरीदार/पट्टेदार असम विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित नियम और शर्त विनियमन के प्रावधान के अनुसार उन्हें प्रदान की गई बिजली आपूर्ति से पहले उक्त बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।”

ई.

313. इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं को संपत्ति खरीदने से पहले बकाया चुकाने की आवश्यकता के बारे में पर्याप्त सूचना दी गई थी। वर्तमान कार्यवाहियों में, अपीलार्थी को परिसर की नीलामी बिक्री की वैधता विचार के लिए उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि यह अलग-अलग कार्यवाहियों में तय किया जाने वाला मामला है। हम केवल इस बात से चिंतित हैं कि क्या अपीलार्थी, परिसर का नया मालिक होने के नाते, बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने से पहले पिछले उपभोक्ता के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

च

जी.

314. 2 जून 2010 के विवादित फैसले से उच्च न्यायालय ने विनियमन 3 की वैधता को बरकरार रखा है। 4 ए. ई. आर. सी. विद्युत आपूर्ति संहिता। इसने अभिनिर्धारित किया कि उक्त विनियमन में निहित शर्त उचित है और 2003 के अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दायरे में है। हमारी राय है कि आक्षेपित खंड है -

एच.

776

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ उचित और सुसंगत। तदनुसार, अपीलार्थी पिछले महीनों के बिलों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य था कि सभी बकाया राशियों का विधिवत भुगतान किया जाए और उनका भुगतान किया जाए। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हालांकि, पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि पिछले मालिक से बिजली का कोई बकाया प्राप्त होता है, तो राशि को अपीलार्थी के बिजली बिलों के साथ समायोजित किया जाएगा।

वी. पश्चिम बंगाल

315. पश्चिम बंगाल में, 2003 के अधिनियम के तहत 2012 में डब्ल्यू. बी. विद्युत आपूर्ति संहिता लागू की गई है। सुसंगत विनियम-खंड 3.4।2, 4.6.1 और 4.6।4 - इनका उल्लेख नीचे किया गया है:

ग

“ 3.4.2. लाइसेंसधारी एक नए और बाद के उपभोक्ता (ओं) से उसी परिसर के संबंध में पिछले और चूक करने वाले उपभोक्ताओं के बकाया की वसूली करने के लिए तभी पात्र होगा जब उसी परिसर के संबंध में पिछले और चूक करने वाले उपभोक्ता (ओं) और नए उपभोक्ता (ओं) के बीच सांठगांठ साबित हो। सांठगांठ साबित करने की जिम्मेदारी, यदि किसी लाइसेंसधारी द्वारा दावा किया जाता है, तो लाइसेंसधारी पर होगी।”

डी.

4.6.1. यदि किसी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए लगातार काट दी जाती है, जहां अधिनियम या विनियमों के किसी भी प्रावधान के अनुपालन में बिजली काट दी गई है, तो बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्ता के साथ लाइसेंसधारी का समझौता एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर परिणामी प्रभाव से समाप्त कर दिया गया माना जाएगा। यह ऐसी अन्य कार्रवाई या उस दावे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा जो आपूर्ति के विच्छेद या उससे संबंधित मुद्दों से उत्पन्न हो सकता है। समझौते की समाप्ति पर, लाइसेंसधारक को सेवा लाइन और अन्य प्रतिष्ठानों को हटाने का अधिकार होगा जिनके माध्यम से उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति की जाती है।”

ई.

च

जी.

“ 4.6.4. इन विनियमों में कहीं और इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहां समझौते की मानित समाप्ति हुई है, तो किसी भी उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर नया सेवा कनेक्शन केवल उसी परिसर में प्रदान किया जा सकता है जब मानित समाप्त उपभोक्ता के खिलाफ बकाया बकाया का भुगतान विलंब भुगतान अधिभार के साथ किया जाता है।”

एच.

777

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई] ए

क.

316. विनियमन 3.4 के तहत 2 डब्ल्यू. बी. विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार, यदि पिछले मालिक और नए उपभोक्ता के बीच सांठगांठ है तो लाइसेंसधारी नए और बाद के मालिक से पिछले मालिक के बकाया की वसूली करने का हकदार है। विनियम 4.6।1 यह प्रावधान है कि यदि किसी भी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति 180 दिनों की निरंतर अवधि के लिए काट दी जाती है तो समझौते को समाप्त माना जाएगा। विनियम 4.6।4 डब्ल्यू. बी. विद्युत आपूर्ति संहिता के अन्य प्रावधानों को ओवरराइड करता है

क्योंकि इसमें एक गैर-अस्थायी खंड शामिल है। विनियमन 4.6 के तहत 4, एक नए उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन केवल तभी दिया जा सकता है जब उसी परिसर के बकाया को विलंब भुगतान अधिभार के साथ भुगतान कर दिया जाए।

ग

वस्तु **101.18**: दामोदर घाटी निगम बनाम श्री रामदूत रोलर्स प्राइवेट; 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या **15723**

317. 30 जून 2012 को, अपीलकर्ता बिजली उपयोगिता, दामोदर घाटी निगम और पिछले मालिक मकर इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। प्रत्यर्थी द्वारा दी गई बैंक गारंटी 4 जून 2014 को समाप्त हो गई। सूट परिसर में बिजली बकाया के भुगतान में चूक के लिए 21 सितंबर 2016 को पिछले मालिक का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। 14 अगस्त 2018 को, भारतीय स्टेट बैंक ने सरफेसी अधिनियम के तहत ई-नीलामी के लिए संपत्ति का विज्ञापन "जैसा है, जहां है" के आधार पर बकाया के चूक के लिए किया। ई-नीलामी बिक्री के प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

डी.

ई.

1. "ई-नीलामी एज इज व्हेयर इज पर आयोजित की जा रही है और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।***

2. [अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के लिए संपत्तियों का कोई बोझ नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी में रखी गई संपत्तियों के बोझ स्वामित्व के बारे में अपनी खुद की स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्तियों को प्रभावित करने वाले अधिकारों का दावा करना चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के बोझ के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात और अधिकृत अधिकारी सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावों, अधिकारों, बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

च

जी.

एच.

778

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

7. इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्तियों का निरीक्षण करें और उन्हें संतुष्ट करें।"

नियम और शर्तों के खंड 1 में प्रावधान किया गया है कि ई-नीलामी "जैसा है, जहां है" के आधार पर आयोजित की जा रही थी। खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि संपत्ति को सभी वर्तमान और भविष्य की बाधाओं के साथ बेचा जा रहा था, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। खंड 7 में प्रावधान किया गया है कि इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्तियों का निरीक्षण करें और उन्हें संतुष्ट करें।

318. 31 अगस्त 2018 को, पिछले मालिक की संपत्ति को एक ई-नीलामी के माध्यम से मैगनम ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ले लिया गया था। संपत्ति का पंजीकरण श्री रामदूत रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर किया गया था, जो इसमें प्रतिवादी

हैं। 04 अक्टूबर 2018 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से एक नए कनेक्शन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। जब अपीलार्थी ने इनकार कर दिया, तो प्रत्यर्थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 17 अप्रैल 2019 को, एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी के आवेदन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। हालाँकि, 10 मई 2019 के अपने पत्र द्वारा अपीलार्थी ने बिजली बकाया रुपये को देखते हुए कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। 22.05 परिसर के संबंध में पूर्व मालिक द्वारा देय करोड़। प्रतिवादी ने अपने परिसर में बिजली की आपूर्ति के लिए निर्देश की मांग करते हुए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 19 जून 2019 को, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को मंजूरी दी और प्रतिवादी को बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने 24 अप्रैल 2020 के एक फैसले से रिट अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। 319. 24 अप्रैल 2020 के विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय की व्याख्या काफी हद तक विनियमन 4.6 में निहित वाक्यांश "किसी भी उपभोक्ता" पर केंद्रित थी। 4. विनियमन 4.6 के तहत 4, एक नए उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन तभी दिया जा सकता है जब उसी परिसर के बकाया को विलंब भुगतान अधिभार के साथ भुगतान कर दिया जाए। न्यायालय ने ईशा मार्बल्स (उपरोक्त) को यह अभिनिर्धारित करने के लिए संदर्भित किया कि धारा 2 (15) में निहित "उपभोक्ता" की परिभाषा में नीलामी-खरीदार शामिल नहीं है। तथापि, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नीलामी-खरीदार को विनियमन 4.6 के दायरे में लाना संभव है। 4 यदि: (i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस तथ्य को स्थापित करता है कि संबंधित परिसर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों से जुड़े थे; (ii) बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से; और (iii) इस तरह से कि बिजली की आपूर्ति 'बस एक स्विच लगाकर' फिर से शुरू की जा सकती है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

779

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

320. अपीलार्थी ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि 21 सितंबर 2016 को परिसर में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। इसलिए, अपीलकर्ता प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी को परिसर की बिक्री की तारीख, यानी 31 अगस्त 2018 को, 180 दिनों से अधिक समय तक बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। इसलिए, यह अपीलार्थी का तर्क है कि विनियम 4.6।1 लागू होता है और समझौते की समाप्ति मानी जाती है। यह आगे तर्क दिया गया है कि विनियमन 4.6।4 इसका एक प्रबल प्रभाव होता है क्योंकि यह एक गैर-अस्थायी खंड से शुरू होता है। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि विनियमन 3.4।2 यह वर्तमान मामले में लागू होगा। यह तर्क दिया गया है कि विनियमन 4.6।4, एक गैर-अस्थायी खंड होने के बावजूद, विनियमन 3.4 के संचालन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2.

ग

321. 21 सितंबर 2016 को बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। 14 अगस्त 2018 को, जो नीलामी नोटिस की तारीख थी और 31 अगस्त 2018 को, जिस तारीख को परिसर प्रत्यर्थी को बेचा गया था, आपूर्ति 180 दिनों से अधिक समय तक बंद रही। विनियम 4.6 के संदर्भ में 1, 180 दिनों से अधिक समय तक आपूर्ति बंद रहने के कारण समझौते को समाप्त माना गया था। तथापि, विनियम 4.6।4 "किसी भी उपभोक्ता" को सेवा कनेक्शन देने के लिए पात्र होने के लिए परिसर के बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को तब तक "उपभोक्ता" नहीं माना जा सकता जब तक कि वितरण लाइसेंसधारी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया हो। ईशा मार्बल्स (ऊपर) में भी निम्नलिखित शब्दों में इसे दोहराया गया है:

डी.

ई.

“62. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त सारणीबद्ध विवरण से पता चलता है कि नीलामी-खरीदार संपर्क विच्छेद के बाद संपत्ति खरीदने के लिए आए थे, लेकिन जब तक कोई अनुबंध नहीं हो जाता, तब तक वे उपरोक्त प्रावधानों के अर्थ में "उपभोक्ता या अधिभोगकर्ता" नहीं हो सकते।" नीलामी-खरीदार, जैसे कि प्रतिवादी, को तब तक "उपभोक्ता" नहीं कहा जा सकता जब तक कि वितरण लाइसेंसधारी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया हो। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के तर्क में कोई गलती नहीं पाते हैं।

च

जी.

322. नतीजतन, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखते हैं। अपील खारिज हो जाएगी।

एच. समानता और निष्पक्षता

323. इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार सौंपा गया है। कहाँ?

एच.

780

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

उचित है, इस न्यायालय को पर्याप्त न्याय लाने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी संवैधानिक शक्ति का सहारा लेना होगा।

324. ईशा मार्बल्स (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के बाद से, पिछले मालिक के बिजली बकाया के बकाया भुगतान के लिए बाद के मालिक के दायित्व के संबंध में कानून चल रहा है। विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के निर्णयों को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2001 की शुरुआत में दायर की गई थीं। उच्च न्यायालयों के आदेशों का प्रभाव या तो विद्युत उपयोगिताओं को बकाया बिजली के भुगतान पर जोर दिए बिना नीलामी खरीदारों को बिजली कनेक्शन देने का निर्देश देना था, या नीलामी खरीदारों को आपूर्ति या बिजली आपूर्ति संहिता की शर्तों का पालन करने का निर्देश देना था, जैसा भी मामला हो। उन्नीस मामलों में से कुछ में, इस न्यायालय ने अनुमति देते हुए अंतरिम आदेश पारित किए। जहां तक हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता का संबंध है, बिजली बकाया संपत्ति पर शुल्क है या नहीं, इस कानूनी मुद्दे को 2006 में इस न्यायालय के एक आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। मुकदमों के इस समूह में मुकदमेबाजी लंबित रही।

ग

डी.

325. हमारे समक्ष विशिष्ट मामलों में, जहां इस न्यायालय ने अधीनस्थ विनियमों (आपूर्ति की शर्तें या बिजली आपूर्ति संहिता, जैसा भी मामला हो) की वैधता को बरकरार रखा है और प्रासंगिक विनियम को तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लागू होने के लिए अभिनिर्धारित किया है, नीलामी खरीदार पिछले उपभोक्ता के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। विद्युत उपयोगिताओं की ओर से, ऐसे बकाया पर ब्याज के लिए दावे किए गए हैं।

ई.

326. इस न्यायालय को इक्विटी को संतुलित करने में सार्वजनिक हित के तत्व को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से इस स्तर पर जहां मुद्दा पहली बार उत्पन्न होने के बाद से मुकदमेबाजी में दो दशक से अधिक समय बीत चुका है। 2003 का अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बिजली उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नीलामी-खरीदारों में से कई वाणिज्यिक संस्थाएं हैं जिन्होंने वाणिज्यिक उद्यमों के लिए परिसर खरीदा था। बिजली किसी भी वाणिज्यिक उद्यम के संचालन के लिए एक आवश्यकता होने के कारण, नीलामी-खरीदारों को अनिश्चित काल के लिए बिजली कनेक्शन से इनकार करने के परिणामस्वरूप व्यवसाय का नुकसान हुआ। अदालती कार्यवाही में देरी से वादियों को और नुकसान नहीं होना चाहिए।

च

जी.

327. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर किए जाने के दो दशक से अधिक का अंतराल और एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में उत्पन्न होने वाले इक्विटी शामिल हैं, हम

एच.

781

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

विद्युत उपयोगिताओं को नीलामी खरीदारों द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन की तारीख से मूलधन बकाया पर उपार्जित बकाया ब्याज को माफ करने का निर्देश दें।

I. Conclusions

328. निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है: ए। 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने का शुल्क पूर्ण नहीं है, और बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन के हिस्से के रूप में विद्युत उपयोगिताओं द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्कों और अनुपालनों के अधीन है;

बी। धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य परिसर के मालिक या अधिभोगियों के संबंध में है। 2003 का अधिनियम उपभोक्ता और परिसर के बीच तालमेल पर विचार करता है। धारा 43 के तहत, जब बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो मालिक या अधिभोगकर्ता केवल उन विशेष परिसरों के संबंध में उपभोक्ता बन जाता है जिनके लिए बिजली की मांग की जाती है और विद्युत उपयोगिताओं द्वारा प्रदान की जाती है। ग. किसी आवेदन को 'पुनर्संयोजन' के रूप में माने जाने के लिए, आवेदक को उसी परिसर के संबंध में बिजली की आपूर्ति की मांग करनी होगी जिसके लिए पहले से ही बिजली प्रदान की गई थी। भले ही उपभोक्ता एक ही हो, लेकिन परिसर अलग-अलग हो, इसे एक नया कनेक्शन माना जाएगा न कि पुनः कनेक्शन।

ग

डी.

ई.

घ. 1948 के अधिनियम की धारा 49 के तहत अधिनियमित आपूर्ति की एक शर्त जिसमें परिसर के नए मालिक को बिजली आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में पिछले मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, का एक वैधानिक चरित्र होगा।

च

ई. 2003 के अधिनियम की धारा 50 के तहत राज्य आयोग की नियामक शक्तियों का दायरा नए या बाद के मालिकों से पिछले मालिकों के बिजली बकाया की वसूली के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।

जी.

च. एक नए मालिक से पिछले उपभोक्ता के बिजली बकाया की वसूली के लिए प्रदान की जाने वाली बिजली आपूर्ति संहिता का 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ एक उचित संबंध है।

एच.

782

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

छ. 2003 के अधिनियम की धारा 50 के साथ पठित धारा 181 के तहत निहित नियम बनाने की शक्ति इतनी व्यापक है कि नियामक आयोग को ऐसे शुल्क के निर्माण के लिए प्रावधान करने वाले पूर्ण कानून में प्रावधान के अभाव में वैधानिक शुल्क का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

ज. चूक करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करके वसूली की कार्यवाही शुरू करने की शक्ति 2003 के अधिनियम की धारा 56 के तहत वसूली के साधन के रूप में बिजली की आपूर्ति को काटने की शक्ति से स्वतंत्र है।

आई. "जैसा है जहां है" अभिव्यक्ति का निहितार्थ यह है कि प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता इस बात पर ध्यान देता है कि विक्रेता सेवा शुल्क, बिजली कनेक्शन के लिए बिजली बकाया और स्थानीय अधिकारियों के करों जैसे बकाया के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में बिक्री के लिए दी गई संपत्ति के संबंध में जिम्मेदारी नहीं लेता है; और

ग

जे. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विद्युत उपयोगिताओं को हमारे समक्ष मामलों के तथ्यों में निर्देश दिया गया है कि वे नीलामी खरीदारों द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन की तारीख से मूल बकाया पर उपार्जित बकाया ब्याज को माफ कर दें।

डी.

ई.

329. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायक: शुभांशु दास, एलसीआरए)

च

जी.

एच.